07 पटरी पर लौटने की राह पर अर्थ-व्यवस्था
15 राजे का चक्रव्यूह

15 फरवरी, 2021

₹40

तहलका

HINDI.COM

राष्ट्र शर्मसार

बाइडन-हैरिस का अमेरिका

अमेरिका में जो बाइडन युग का आग़ाज़ हो गया है। दुनिया के सबसे ताक़तवर देश में इस सत्ता परिवर्तन के बाद भारत में भी दोनों देशों के सम्भावित रिश्तों को लेकर अनुमान लगाये जा रहे हैं। कमला हैरिस के रूप में भारतीय मूल की उप राष्ट्रपति बनना भारत के लिए एक सकारात्मक सन्देश है।

26

VISIT…

EXCELLENCE, LIKE COURAGE, CAN BECOME A HABIT

Tehelka

WINS IPI INDIA AWARD

FOR TWO CONSECUTIVE YEARS IN A ROW

AWARDED FOR EXCELLENCE IN JOURNALISM 2011 & 2012 BY THE INDIA CHAPTER OF
THE INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE

TEHELKA'S PATHBREAKING WORK HAS WON IT MORE THAN 40 AWARDS

विश्वसनीयता का संकट

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता के बीच व्हाट्स ऐप पर साझा की गयी हालिया चैट ने कुछ टीवी चैनल्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिये हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सार्वजनिक हो चुकी इस चैट से जहाँ टीवी चैनल की रेटिंग की साज़िश बेनक़ाब होती है, वहीं गोस्वामी की सरकार के साथ निकटता और बेहद संवेदनशील जानकारी उनको लीक करने के बात भी सामने आती है। सन् 2010 में इसी तरह राडिया टेप विवाद था, जिसने पत्रकारिता की निष्पक्षता पर काली छाया डाली थी और कॉरपोरेट घरानों, पत्रकारों तथा राजनेताओं के बीच साँठगाँठ का ख़ुलासा हुआ था। और अब नवीनतम लीक, प्रस्तावित हवाई हमले की अत्यधिक गुप्त सैन्य सूचनाओं का उपयोग टीआरपी को बढ़ाने के लिए किये जाने की ओर इशारा करती है; जो विज्ञापनों के एक वृहद् राजस्व हिस्से को अपने पाले में करने के लिए है।

हालाँकि कथित लीक चैट्स पर बड़ा और गम्भीर सवाल यह है कि क्या गोस्वामी को फरवरी, 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ़ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बालाकोट हवाई हमले करने की योजना की पूर्व जानकारी थी? जो कि दुनिया को हिला देने वाली ख़बर बन गयी थी। चैट में गोस्वामी ने कथित तौर पर हमला करने की सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को यह घटना 'उन्माद' से भर देगी। क्या यह लीक चैट राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में गम्भीर सवाल नहीं खड़े करती? यह चैट टीआरपी में हेराफेरी के आरोप वाली मुम्बई पुलिस की 500 से ज़्यादा पेज की चार्जशीट का हिस्सा है, जिसे मुम्बई पुलिस ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह चैट सोशल मीडिया पर यह काफ़ी वायरल हो गयी है, जिसने एक तरह से विस्फोट किये हैं। अब महाराष्ट्र सरकार मामले में कार्रवाई कर रही है और उसने क़ानूनी राय माँगी है कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह पूछते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया है कि गोस्वामी की ऐसी संवेदनशील सूचनाओं तक पहुँच कैसे बनी? जो केवल कुछ चुनिंदा सरकारी लोगों को ही पता होती हैं।

लीक चैट्स से ज़ाहिर होता है कि 26 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जब भारतीय वायु सेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहमद के प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया था, उस एयर स्ट्राइक की अर्नब को पहले से जानकारी थी। यह एयर स्ट्राइक भारत की तरफ़ से तब की गयी थी, जब देश में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ग़ुस्से की लहर थी; जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में किये गये हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद पैदा हुई थी। अब तक न तो टीवी चैनल और न ही सरकार ने इन लीक चैट्स का खण्डन किया है, जिससे यही पता चलता है कि व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है। ऐसी ख़बरें, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से उत्तेजित करती हैं, काफ़ी दिनों तक चलती रहती हैं; क्योंकि चैनल्स दर्शकों के लिए एजेंडा सेट करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की ख़बर इसका एक बड़ा उदाहरण है। अनेक मौक़ों पर समाचार को एक प्रकार के मनोरंजन के रूप में पेश किया जाता है और कई दिनों तक उस पर बहस की जाती है। समय-समय पर मीडिया में कुछ कलंकित लोग हमें इसकी रुग्ण हालत की याद दिलाते हुए इसकी तेज़ी से गिरती हुई साख की तरफ़ इशारा करते हुए दिखते हैं। क्या यह गन्दगी कभी साफ़ होगी?

चरणजीत आहुजा
letters@tehelka.com

संपादक : **चरणजीत आहुजा***
समाचार संपादक : **पंडित प्रेम बरेलवी**

विशेष संवाददाता
रियाज़ वानी (श्रीनगर)
मुदित माथुर (लखनऊ)
राकेश रॉकी (दिल्ली)
राजीव दुबे (दिल्ली)

डिजाइन
अनंगपाल सिंह

फोटो संयोजन : **दीपक झा**

वेब
सनी शर्मा

ऐडसेल्स
वीपी ऐडसेल्स : **ज़ाकिया ख़ान**
डिप्टी मैनेजर : **रजनी भल्ला**
adsales@tehelka.com

प्रोडक्शन मैनेजर : **पीयूष श्रीवास्तव**

सर्कुलेशन टीम : **उमा शंकर तिवारी** (9818009833), **सूरज सिंह**

एकाउंट्स : **प्रदीप शर्मा**

मुद्रक एवं प्रकाशक : **सविंदर बाजवा**

स्वामित्व : **तहलका कॉम प्राइवेट लिमिटेड**
प्रकाशक : **सविंदर बाजवा** द्वारा **तहलका कॉम प्राइवेट लिमिटेड** के लिए एमपी प्रिंटर्स, बी-220, फेज-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और बिल्डिंग संख्या 23, नेहरू प्लेस, नयी दिल्ली-110019 से प्रकाशित

प्रधान कार्यालय
बिल्डिंग संख्या-23
नेहरू प्लेस, नयी दिल्ली-110019
दूरभाष : 011-40600890
ईमेल : hindi@tehelka.com
सब्सक्रिप्शन की जानकारी और सर्कुलेशन की शिकायत के लिए ईमेल :
wecare@tehelka.com
वर्ष 13, अंक 3; 1-15 फरवरी, 2021
कुल पृष्ठ 52 (आवरण सहित)

*समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट 1867 के तहत ज़िम्मेदार

इस अंक में

गिद्ध पत्रकारिता !

ढेरों सवालों / आरोपों को अपने ऊपर ओढ़े हुए यह नये दौर की पत्रकारिता है; टीआरपी और राजनीति की स्याही में गहरे से भीगी पत्रकारिता! इसमें देशभक्ति के नाम पर राजभक्ति है। यानी अब पत्रकारिता की परिभाषा भरोसे की चिन्दी-चिन्दी है। इसका प्रमाण देश की सुरक्षा से जुड़ी ख़ुफिया जानकारियों पर व्हाट्स ऐप चैट्स में अर्नब-पार्थो के लगते शाब्दिक अट्टहास से मिल जाता है। टीआरपी और राजनीतिक आकाओं की बदौलत कैसे कोई पत्रकार दिखावटी देशभक्ति का ड्रामा करता है,...।

19

बजट 2021

25

कोविड-19 से मार खायी अर्थ-व्यवस्था के बीच अगला वित्तीय बजट पेश हो रहा है। इसमें 'वी' अर्थात् वैक्सीन का प्रभाव तो है ही, लेकिन महामारी में लगे अर्थ-व्यवस्था के झटकों के बाद...।

कोरोना टीका लगवाने से क्यों कतरा रहे लोग?

36

देश में भले ही कोरोना टीके को लेकर उपलब्धि भरी गाथाएँ गायी और सुनायी जा रही हों, लेकिन हक़ीक़त तो कुछ और ही है।

क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज़रूरी है?

40

आप भावनात्मक तरीक़े से मूर्ख बनाना बन्द कीजिए! ऐसे वाक्यों का मतलब यह भी है कि किसी को भावनात्मक तरीक़े से जुड़ने के लिए ख़ुद को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए।

अफ़ग़ानी महिलाओं में फिर दहशत !

42

...क़ाबुल में बन्दूकधारियों ने एक कार पर गोलीबारी की, जिसमें उच्च अदालत में कार्यरत दो महिला न्यायधीशों को मौत हो गयी।

वक़्त के निशान

48 लेखक वेद मेहता के निधन के साथ, मैं केवल यह कह सकती हूँ कि हमने एक महान् लेखक ही नहीं, बल्कि एक दृढ़ व्यक्तित्व वाले इंसान को भी खो दिया है। मैं उनसे दो बार मिली थी और सन् 2009 की शरद ऋतु के दौरान एक बार उनका साक्षात्कार किया था; जब वह अपनी पत्नी लिन कैरी नई दिल्ली आये थे।

चींटी के बराबर भी नहीं हमारी हैसियत

50 बचपन में कबूतरों और आखेटक यानी शिकारी की कहानी पढ़ी थी। अपनी चतुराई और चूहे की मित्रता के दम पर कबूतर न केवल ख़ुद आज़ाद हो गये, बल्कि आखेटक का जाल भी ले उड़े। आज हम इंसान आपस में इतने बिखर गये हैं कि एक-एक करके आखेटकों के जाल में फँसते जा रहे हैं और आखेट होते जा रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि हम एक-दूसरे के फँसने और फड़फड़ाने पर ख़ुश हैं और उछल रहे हैं। हम ख़ुश इस बात पर भी हैं कि फँसने वाले दूसरे हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसियन हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, फलाँ हैं-फलाँ हैं।

आपके पत्र

letters@tehelka.com

किसानों की सुने सरकार

अपनी खेती बचाने के लिए किसान दो महीने से आन्दोलन पर बैठे हैं। लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को यह समझना होगा कि स्वाभाविक तौर पर जब कोई किसी के अधिकार क्षेत्र या रोज़ी-रोज़गार पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, तो पीढ़ित व्यक्ति उसका विरोध और प्रतिकार करेगा ही। मान लीजिए कि किसी उद्योगपति से मैं कहूँ कि आपकी कम्पनी मेरे हिसाब से काम करेगी और उसमें पहले की ही तरह आप काम करेंगे। अगर आपने मेरे हिसाब से उत्पाद तैयार किये, तो आपको मैं हर महीने उसका अपने हिसाब से एक भाव दूँगा। मगर आप फ़िक्र न करें, वह भाव ठीकठाक होगा। और अगर आपके उत्पाद में कमी हुई, तो मैं आपका उत्पाद नहीं ख़रीदूँगा और आपको मेरी लागत वापस करनी होगी। तो क्या वह उद्योगपति मुझे अपनी कम्पनी सौंपने को तैयार होगा? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, कोई भी छोटे-से-छोटा काम करने वाला व्यक्ति अपने रोज़ी-रोज़गार के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। वह भी तब तो और नहीं, जब उसे यह भी न पता हो कि उसे इसका लाभ मिलेगा भी या नहीं? आप किसी ठेले-खोमचे वाले से कहकर देखिए कि तुम इसी तरह ठेला लगाओगे और मैं जो कहूँगा, वह बेचोगे; कच्चा माल मैं तुम्हें दूँगा। शाम को सारे पैसे तुम मुझे दोगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के हिसाब से ठीकठाक पैसे दूँगा और उसमें यह शर्त रख दीजिए कि अगर बिक्री का माल ख़राब हुआ या उसके सही ग्राहक न मिले, तो ज़िम्मेदारी तुम्हारी! ऐसा होने पर तुम्हें मेरी लागत मुझे वापस करनी होगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वह ठेले या खोमचे वाला आपकी बात मानेगा? मुझे लगता है कि लड़ जाएगा और गालियाँ ही देगा। फिर सोचिए, क़ीमती ज़मीनों के मालिक किसान अपने इस महत्त्वपूर्ण रोज़ी-रोज़गार से समझौता क्यों करें? अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर कौन बनना चाहेगा? क्या आप अपनी ही ज़मीन पर दूसरे के दिशा-निर्देशों पर काम करना चाहेंगे? वह भी इस शर्त पर कि वह व्यक्ति मालिक की तरह आप पर हुक्म चलायेगा और आप उसके नौकर की तरह काम करेंगे और अगर काम बिगड़ गया, तो उसके लिए आप और सिर्फ़ आप ही ज़िम्मेदार होंगे! और आपको ही उसका दण्ड भुगतना होगा!

कुंभाराम भामी, चूरू, राजस्थान

सभी को लगे कोरोना वैक्सीन

कोरोना वायरस की वैक्सीन स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना योद्धाओं को लगने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि बाक़ी देशवासियों को वैक्सीन कब लगेगी? बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार में भाजपा नेता और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यदि बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, तो सभी बिहारवासियों को मुफ़्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ख़बरें तो यहाँ तक फैल रही हैं कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन पूरे विश्वास के बग़ैर ही लोगों को लगवानी शुरू कर दी है और इसमें भेदभाव की कोशिश हो रही है। लेकिन इन बातों / अफ़वाहों को हवा देने से बेहतर है इस बात पर चर्चा हो कि आख़िर कब तक सभी देशवासियों को कोरोना वायरस की यह वैक्सीन लग जाएगी? ताकि देश को कोरोना वायरस से मुक्ति मिले और लोगों के दिलों से इस महामारी का डर दूर हो। इसके लिए सरकार को बिना किसी भेदभाव के सभी को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करानी चीहिए। क्या सरकार ऐसा करेगी?

अनिल कुमार, मयूर बिहार, दिल्ली

स्कूल खोले सरकार

हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। पिछले साल कोरोना वायरस के चलते पूरे देश के स्कूल, कॉलेज बन्द होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। अब जब रैरियाँ हो रही हैं, बाज़ार खुल रहे हैं, किसान आन्दोलन चल रहा है, तक़रीबन सभी कम्पनियाँ खुल रही हैं और यात्राएँ शुरू हो गयीं हैं, तो फिर स्कूलों और कॉलेजें को क्यों बन्द रखा जा रहा है? क्या सरकार को इस बात का अहसास नहीं कि वह देश के नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। ऐसा करके आख़िर क्या फ़ायदा मिलने वाला है सरकार को? अब जबकि कोरोना वैक्सीन भी आ गयी है, तो फिर सरकार को बच्चों को घरों में क़ैद करने से क्या मिल रहा है? माना कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन क्या इसका फ़ायदा सभी बच्चे उठा पा रहे हैं? इस बात पर सरकार को ठीक से विचार करना चाहिए और हरियाणा सरकार से सीख लेते हुए देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को खोल देना चाहिए, अन्यथा अनेक बच्चों का भविष्य ख़तरे में पड़ जाएगा, जिसकी ज़िम्मेदार सबसे पहले सरकार ही होगी।

राजेश कश्यप, पटना, बिहार

बेकार बहसों में उलझें लोग

बचपन से हम सभी एक मुहावरा सुनते आये हैं- बेग़ानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज भी यह कहावत कम-से-कम राजनीतिक लोगों के लिए लड़ने वालों पर पूरी तरह सटीक बैठती है। मैंने आये दिन सियासी लोगों के लिए बिना फ़ायदे के, बिना स्वार्थ के मूर्खों की तरह बहुतों को लड़ते देखा है। अगर यही समय लोग अपने ऊपर देने लगें, तो शायद उनका और उनके परिवार का भविष्य सुधर जाए। ऐसे लोगों की बहसों पर बहुत-से लोग अनायसास कूद जाते हैं। मुझे हँसी आती है। सोचता हूँ कि कैसे लोग हैं, जो अच्छे-बुरे लोगों की पहचान तक नहीं कर सकते! हालाँकि इन बहस करने वालों में एक पक्ष काफ़ी हद तक सही होता है और ईमानदार राजनेताओं का पक्ष लेता है; लेकिन एक पक्ष उन नेताओं की तरफ़दारी करने पर आमादा रहता है, जो ग़लत होते हैं। ऐसे लोग अक्सर गुणगान करने वालों में होते हैं। जो भी हो, मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही कि अगर लोग बेकार की बहसों में उलझने की बजाय आत्मचिन्तन करें, हर हाल में अपने हित और रोज़गार के बारे में सोचें और अपने विवेक से चुनावों में सही नेताओं चुनाव करें, तो यह रोना ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।

विक्की, नोएडा, उत्तर प्रदेश

वेबसाइट पर सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली ख़बरें

अहंकार या कुछ और? आला अफ़सरों की शादियाँ क्यों हो रहीं नाकाम

आईएएस अफ़सर टीना डाबी और अतहर ख़ान मार्च, 2018 में शादी के बन्धन में बँधे और राजस्थान कैडर में अपनी सेवाएँ देने लगे। उनके रिश्ते में खटपट की बात तब सामने आयी, जब टीना ने सोशल मीडिया पर अपने उपनाम से ख़ान टाइटल हटा दिया। **श्वेता मिश्रा**

यह मात्र छलावा है : टिकैत

हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन हम तो कृषि क़ानूनों को रद्द करने की माँग कर रहे हैं। यह नहीं हुआ। ऊपर से जिस समिति का गठन हुआ है, उसके सभी सदस्य कृषि क़ानूनों के घोर समर्थक हैं। ऐसे में हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम तो न्यायालय में गये ही नहीं हैं। **राकेश रॉकी**

साड़ी के धागों के बीच उलझती ज़िन्दगी

होल्कर वंश की महान् शासक देवी अहिल्याबाई होल्कर ने सन् 1767 में आज के मध्य प्रदेश राज्य के महेश्वर में कुटीर उद्योग स्थापित किया था। इसके लिए उन्होंने भारत के अन्य राज्यों से बुनकरों को बुलाकर यहाँ बसाया था और उन्हें घर, व्यापार के साथ अन्य सुविधाएँ भी मुहैया करवायी थीं। **अर्चना सिंह**

अविश्वास की लकीर, किसान आन्दोलन : सुप्रीम कोर्ट की पहल पर क़ानून समर्थक समिति के गठन ने फेरा पानी

यह 14 दिसंबर, 2020 की बात है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दफ़्तर में एक पत्र पहुँचा। यह पत्र अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह मान ने लिखा था। **राकेश रॉकी**

इन स्थानों पर मिलेगी तहलका पत्रिका

दक्षिण भारत

- **हैदराबाद :** भाग्यनगर न्यूज़ एजेंसी (फोन- 8374941140)
- **चेन्नई :** सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (फोन- 044-45508213)

उत्तर भारत

- **दिल्ली :** दिल्ली मैग्ज़ीन डिस्ट्रिब्यूटर (फोन- 011-41561060, 41561061)
- **जयपुर :** नवरतन बुक सेलर (फोन- 0141-2317661, 9829373912)
- **भोपाल :** लाइफ बुक हाउस (फोन- 9826313349)
- **रायपुर :** श्री रामचंद्र बुक स्टॉल (फोन- 9827145302)
- **अमृतसर :** पंडित बेलीराम एंड सन्स (फोन- 0183-2550285)
- **जोधपुर :** लेटेस्ट मैग्ज़ीन सेंटर (फोन- 0291-2620686)
- **पठानकोट :** भाटिया बुक डिपो (फोन- 0186-2221916)
- **मेरठ :** चावला बुक डिपो (फोन- 9837015153)
- **वाराणसी :** लक्ष्मी नारायण न्यूज़ एजेंसी (फोन- 9307023122)
- **लखनऊ :** मॉडर्न बुक स्टॉल (फोन- 7235873108)
- **चंडीगढ़ :** पुरी न्यूज़ एजेंसी (फोन- 9888057364)
- **देहरादून :** गुप्ता न्यूज़ एजेंसी (फोन- 0135-2717810
- **जम्मू :** रैना न्यूज़ एजेंसी (फोन- 9419109550)
- **करनाल :** एच.आर. बुक स्टॉल (फोन- 9255426821)
- **इंदौर :** सोगानी न्यूज़ एजेंसी (फोन- 9826033552)
- **हिसार :** वर्मा न्यूज़ एजेंसी (फोन- 0166-2225293)
- **जबलपुर :** जनता न्यूज़ एजेंसी (फोन- 9691888306)

पूर्वी भारत

- **पटना :** ईस्टर्न न्यूज़ एजेंसी (फोन- 9334115121)
- **रांची :** मॉडर्न न्यूज़ एजेंसी (फोन- 9835329939)
- **गुवाहाटी :** दुर्गा न्यूज़ एजेंसी (फोन- 9435049511)
- **गोरखपुर :** स्टूडेंट कॉर्नर (फोन- 9415326404)
- **जमशेदपुर :** प्रसाद मैग्ज़ीन सेंटर (फोन- 0657-2420086)
- **बोकारो :** त्रिलोकी सिंह (फोन- 9334911785)

पश्चिम भारत

- **मुम्बई :** सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (फोन- 022- 66393468, 22691504)
- **नागपुर :** नेशनल बुक सेंटर (फोन- 8007290786)
- **नागपुर :** पाठक ब्रदर्स (फोन- 9823125806)
- **पुणे :** वीर न्यूज़ एजेंसी (फोन- 8149916544)
- **अहमदाबाद :** विधि न्यूज़ एजेंसी (फोन- 9727525414)
- **अहमदाबाद :** नवकर डिस्ट्रिब्यूटर (फोन- 07925503836)

पटरी पर लौटने की राह पर अर्थ-व्यवस्था

भारत हितैषी

क्या हम अर्थ-व्यवस्था के सबसे बुरे दौर से गुजर चुके हैं और क्या अब आगे इससे उबरने की राह सुनिश्चित है? इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं मिला है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट में ऐसे संकेत मिले हैं कि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में आर्थिक क्षेत्र में तेज़ी से उछाल दर्ज किया जाएगा। आईएमएफ ने कहा है कि भारत की अगले वित्त वर्ष में विकास दर दो अंकों में रहेगी।

आरबीआई ने कहा है कि हाल ही में वृहद आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ने बेहतर विकल्प और परिणाम के संकेत दिये हैं। इससे सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक क़दम और मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। वित्तीय बाज़ार मज़बूत पोर्टफोलियो प्रवाह के बावजूद सुस्त बना हुआ है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रिकॉर्ड वार्षिक प्रवाह प्राप्त करने के ट्रैक पर है। यदि ये गतिविधियाँ बनी रहती हैं, तो पुनर्बढ़त (रिकवरी) का समर्थन करने के विकल्प खुल सकते हैं। नये साल की शुरुआत दुनिया भर के देशों में बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकरण अभियान के साथ हुई और महसूस किया गया कि सबसे बुरा दौर अब पीछे छूटने वाला है।

आरबीआई ने कहा है कि हाल के उच्च आवृत्ति संकेतकों से पता चलता है कि अर्थ-व्यवस्था मज़बूत हो रही है और जल्द ही यह सन्तोषजनक स्थिति में होगी। दिसंबर, 2020 के जारी आँकड़ों में ई-वे बिलों की संख्या सबसे अधिक थी, साथ ही जीएसटी संग्रह भी अब तक का रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया। इससे पता चलता है कि कमायी और ख़र्च अब त्योहार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक आंतरिक गति के पंखों पर फीनिक्स की तरह बढ़ रहा है।

केंद्रीय रिजर्व बैंक का बयान एक अच्छी ख़बर क्यों है? विभिन्न क्षेत्रों द्वारा विकास और गिरावट दिखाते हैं कि भारत सुधारों की राह पर है। देखा गया कि कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिक्की-यस बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत पर्यटन के साथ ही बिजलीघर के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। भारत में पर्यटन का सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 फ़ीसदी है और इसने सन् 2018 में 2.67 करोड़ नौकरियों के सृजन के साथ 247.3 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया। वर्तमान में यह जीडीपी में योगदान के मामले में 8वाँ सबसे बड़ा देश है।

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2029 तक पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 5.3 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। सन् 2019 में भारतीय खुदरा उद्योग का मूल्य 790 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का 10 फ़ीसदी है और क़रीब आठ फ़ीसदी लोगों को रोज़गार मुहैया कराता है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन रिटेल (संचार माध्यम से फुटकर बिक्री) में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक, पिछले साल ऑनलाइन रिटेल में 30 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई।

खुदरा (फुटकर) क्षेत्र में दबी हुई माँग में बहुत तेज़ी से उबारने की प्रवृत्ति होती है और लॉकडाउन हटने के बाद इस सेक्टर के उबरने में मदद मिलेगी। लॉकडाउन अवधि के दौरान देश के कुछ हिस्सों में ऑनलाइन रिटेल चालू था और इससे उद्योग के लिए कुछ नुक़सानों को दूर करने में मदद मिली, जो आगे भी मिलेगी। कुछ सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, जैसे- (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) एमएसएमई; लेकिन खेती ने इनको राहत पैकेज प्रदान किये। हालाँकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपनी विकास गति को हासिल करने के मानकों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। समान विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा तक सभी की समान पहुँच एक महत्त्वपूर्ण शर्त है। कोविड-19 महामारी ने भारत में नीति-निर्माताओं को बता दिया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को अहमियत देनी होगी। महामारी ने श्रम सुधारों की प्रक्रिया को तेज़ करने का अवसर प्रदान किया है। श्रम सुधारों के साथ वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी, यानी इससे मज़दूरी भी बढ़ेगी साथ ही बेरोज़गारी भी कम होगी। वर्तमान हालात से इतर पहले भारत में सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से नीतियाँ बनती थीं। ग़रीब और कमज़ोर तबक़ा ही लोगों के यहाँ काम करता था। इसमें लोगों को भिक्षा के तौर पर भोजन देना भी संस्कृति का एक हिस्सा था। लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन जैसे संकट ने लोगों को नये सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया है। संकट के समय में सरकारों की बजाय पीड़ितों की मदद का एक बड़ा हिस्सा ख़ुद लोगों ने बढ़-चढ़कर दिया; जो समुदाय आधारित सामाजिक सुरक्षा की याद दिलाता है। देश में सभी के लिए राज्य-प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा को अभी विकसित किया जाना बाक़ी है।

भारत में उन्नत डिजिटल तकनीक की उपलब्धता से आसानी से पुन: उन्नति सम्भव है। सनद रहे कि पिछले साल कोरोना के आने के साथ ही केंद्र सरकार ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। इससे बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक बड़े शहरों से पलायन करने को मजबूर हुए और इसके बाद विकट परेशानियों का सिलसिला शुरू हुआ। श्रमिकों की परेशानियों, भूख-प्यास और मजबूरियों ने हर संवेदनशील शख़्स को झकझोर दिया था। हालाँकि कई मामलों में सरकार की असंवेदनशीलता और ग़ैर-ज़िम्मेदाराना रवैये ने लोगों को असन्तुष्ट भी किया। तहलका

letters@tehelka.com

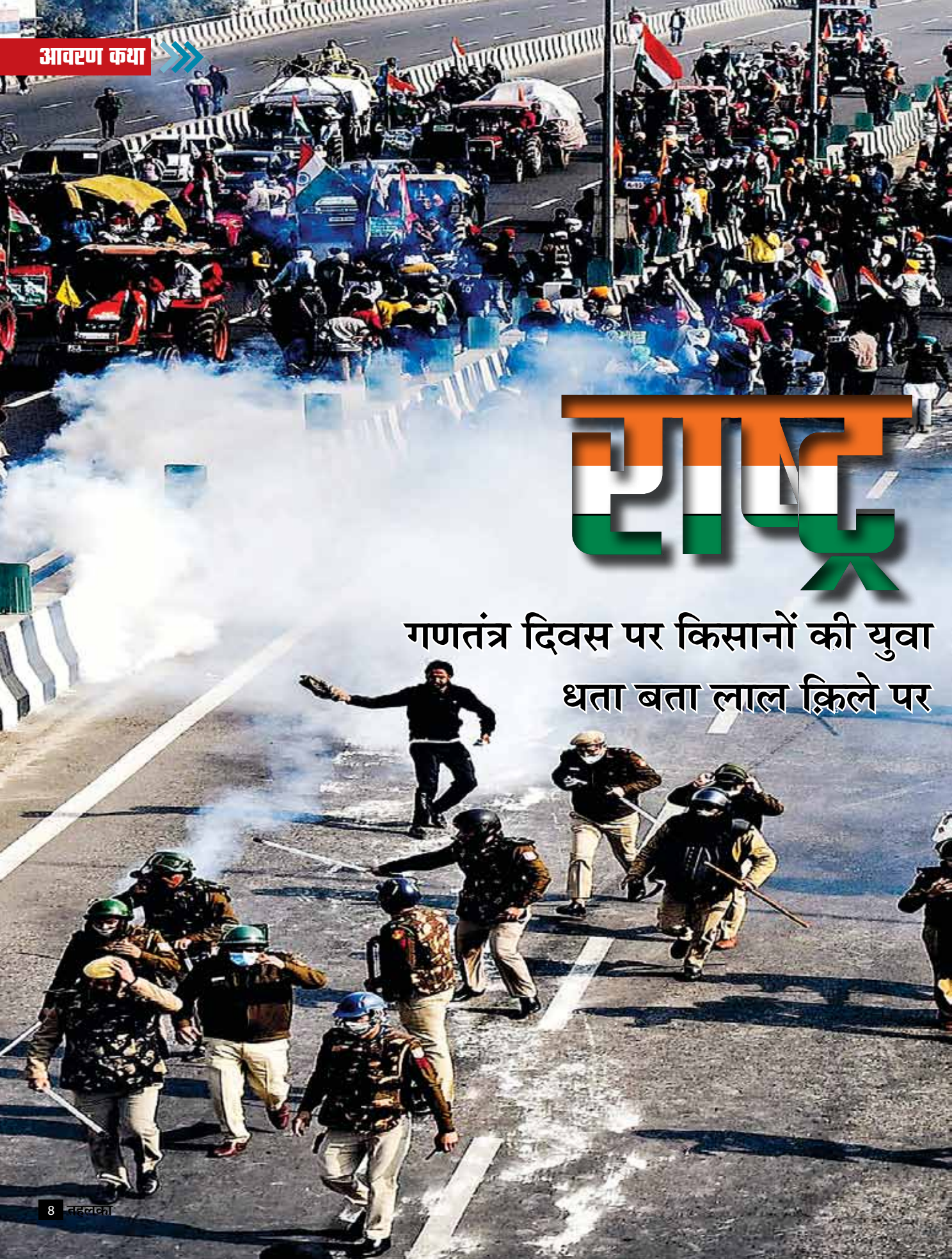

शर्म

गणतंत्र दिवस पर किसानों की युवा धता बता लाल क़िले पर

शर्मसार

टोली ने सुरक्षा व्यवस्था को फहराया अपना झण्डा

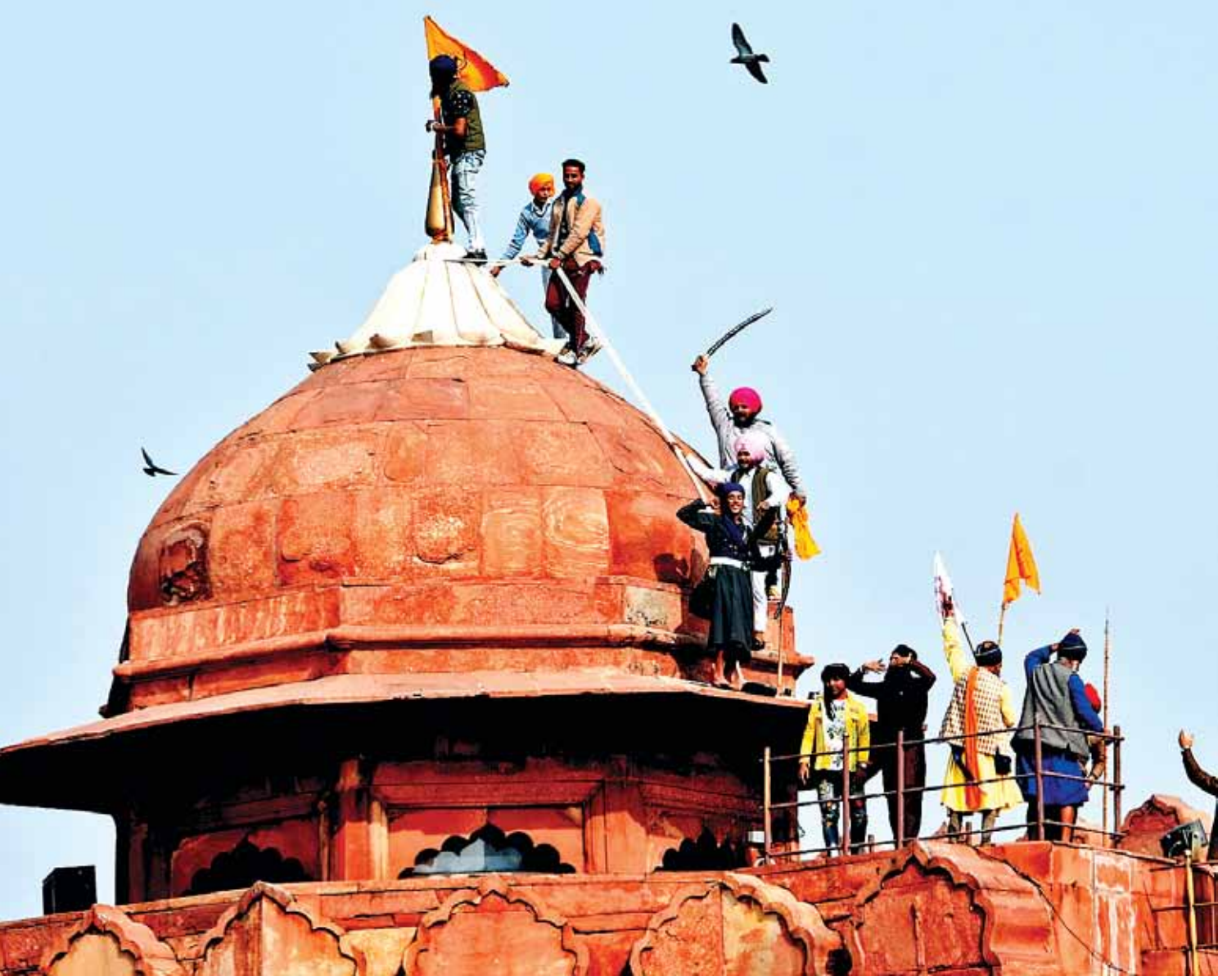

केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की 11 दौर की बातचीत में जब सरकार ने कह दिया कि नये कृषि क़ानूनों को डेढ़ साल तक टालने से बेहतर विकल्प हमारे पास नहीं है, इसके बाद अगली वार्ता का रास्ता भी एक तरह से बन्द हो गया। लेकिन इससे किसान आन्दोलन नहीं रुका और सबकी निगाहें 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की किसान परेड यानी ट्रैक्टर रैली पर टिक गयीं। हालाँकि पहले से अंदेशा भी था कि जब हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर राजधानी में प्रवेश करेंगे, जिनके साथ लाखों किसान, ख़ासकर युवा दिल्ली में लाल क़िले की ओर बढ़ेंगे और उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, तो टकराव मुमकिन है। तमाम कयासों और किन्तु-परन्तु के बावजूद जब किसान राजधानी की सीमाओं के अन्दर घुस रहे थे, तो उनका पुलिसकर्मियों के साथ टकराव हुआ, इसमें जन-धन हानि के साथ एक युवा समर्थक की मौत हुई। मौत कैसे हुई, इस पर भी बवाल मचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत हादसे में हुई। लेकिन परिजनों का कहना है कि नवदीप की मौत पुलिस की गोली से हुई है। युवा किसान का नाम नवदीप था, वह रामपुर, उत्तर प्रदेश के थे। शुरू में यह आरोप भी लगे थे कि नवदीप की मौत पुलिस की गोली से हुई है। वहीं एक वीडियो में उनका ट्रैक्टर पुलिस बैरिकेड से टकराकर पलटता नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इस हिंसा में सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार और किसान दोनों के अड़ियल रुख़ के चलते ही हिंसा पनपी, जिसकी ज़िम्मेदारी प्रशासक के तौर पर निश्चित रूप से सरकार की है और उसे ही इसका हल निकालना होगा। अभी भी सवाल वहीं-का-वहीं है, यानी नये क़ानूनों पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे हालात आगे और भी बदतर हो सकते हैं और टकराव बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि संवेदनशील और विशेषज्ञों की टीम को लेकर समाधान निकालना ही होगा। क्योंकि यह मामला अब महज़ भारत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लाल क़िले की घटना के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरमा गया है।

देश की राजधानी नई दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कृषि क़ानून के विरोध में किसानों की बेक़ाबू ट्रैक्टर रैली ने शक्ति प्रदर्शन करके देश के सियासतदानों को साफ़ बता दिया है कि अगर अभी कृषि क़ानूनों को वापस नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र हो सकता है। गणतंत्र दिवस पर एक ओर दिल्ली के राजपथ पर देश के शूरवीरों के पराक्रम और शौर्य की गाथाओं का प्रदर्शन और सम्मान किया जा रहा था, तो दूसरी ओर देश के कोने-कोने में अन्नदाता अपने अधिकार और

आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसानों का इतना बड़ा आन्दोलन देखने को मिला है, जिसमें ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि नये कृषि क़ानूनों में कुछ-न-कुछ तो काला है। लाल क़िले की घटना और आन्दोलन से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल करती राजीव दुबे और शबाना की रिपोर्ट :-

सम्मान को बरक़रार रखने के लिए तीनों नये कृषि क़ानूनों को वापस लेने की माँगों को लेकर प्रदर्शन करके जद्दोजहद कर रहे थे। राजपथ पर पहली बार राफेल लड़ाकू विमान की गर्जना के आगे ट्रैक्टरों की गूँज हावी हो गयी। महज़ दिल्ली ही नहीं, पंजाब-हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण के कई राज्यों में भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। संगठनों का कहना है कि सरकार किसानों को धमकाना छोड़े और कृषि क़ानून को वापस ले; ताकि देश का किसान तसल्ली से खेती-बाड़ी कर सके। विदित हो कि ट्रैक्टर रैली का मामला पहले उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) पहुँचा था, जिसमें सीधे दख़ल देने से उचचतम न्यायालय ने इन्कार कर दिया। उसने कहा कि इस पर दिल्ली पुलिस और सरकार ही फ़ैसला करें। इसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ किसानों को दिल्ली में तीन जगहों से प्रवेश की अनुमति दी थी। इसमें यह भी कहा गया था कि हर प्रवेश द्वार से महज़ 5,000 ट्रैक्टर ही प्रवेश करेंगे, जिनके साथ 5,000 ही किसानों को अनुमति होगी; वह भी एक तय रूट पर। रैली का समय सुबह राजपथ पर परेड पूरी होने के बाद यानी दोपहर 12:00 से शाम बजे तक तय किया गया था। लेकिन कुछ किसानों, ख़ासकर युवाओं की टोली ने सुबह से ही सिंघु बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर ट्रैक्टरों के ज़रिये प्रवेश करना शुरू कर दिया। सिंघु बॉर्डर पर एक किसान नेता पर भड़काऊ भाषण देने के भी आरोप लगे हैं। इसके बाद तो जगह-जगह बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रैक्टरों को प्रवेश करा दिया गया, साथ ही युवाओं का जोश और उफान मारने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि लाल क़िले से पहले आईटीओ पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया। कई जगह ट्रैक्टर और किसानों को रोकने के लिए बसें, ट्रक और ट्रॉले भी लगाये गये थे; लेकिन सब नाकाम साबित हुए। जब किसान लाल क़िला पहुँचे, तो वहाँ पर जो घटना हुई उससे न सिर्फ़ किसान आन्दोलन की किरकिरी हुई, बल्कि इसके संचालकों पर भी उँगलियाँ उठायी गयीं।

हालाँकि संचालकों ने इससे पल्ला झाड़ लिया कि जो भी हिंसा हुई वह अराजक तत्त्वों ने की, उनका किसान संगठनों से कोई लेना-देना नहीं है। वे किसानों के समर्थक क़तई नहीं हो सकते। पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को लाल क़िले के गेट से जबरन हटा दिया गया। जोश से भरी युवाओं की टोली इस तरह से लाल क़िले पर चढ़ गयी, मानो उसने क़िला फ़तह कर लिया हो। चूँकि सरकार इससे पहले उनकी बातों को गम्भीरता से नहीं ले रही थी, ऐसा उनका मानना है। शायद इसीलिए वे अपनी बात को प्रभावी तरीक़े से मनवाने के लिए दुनिया को दिखाने के लिए ऐसी हरकत कर बैठे। हालाँकि इस पर कई सवाल खड़े हो गये हैं। पहला यह कि जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों पर लाठियाँ भाँजी जा रही थीं और आँसू गैस के गोले दाग़े जा रहे थे, तो लाल क़िले पर पुलिस इतनी शान्ति से तमाशा क्यों देखती रही? दूसरा, लाल क़िले की प्राचीर पर जब युवा चढ़ रहे थे, तब उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? तीसरा, लाल क़िले तक मुख्य किसानों को क्यों नहीं पहुँचने दिया गया? कितनी ही जगह किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, आँसू गैस के गोले दाग़े गये, लाठियाँ भी भाँजी गयीं, मगर लाल क़िले पर घटना ऐसे घटने दी गयी, जैसे कोई फ़िल्म की शूटिंग चल रही हो। यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गयी। 72वें गणतंत्र की इस घटना को शायद देश का कोई नागरिक भुला पाएगा।

ग़ाज़ीपुर से नेशनल हाई-वे के रास्ते दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में शामिल किसान सुरजीत और भीरू ने 'तहलका' को बताया कि देश को गुमराह करते-करते राजनेता अब किसानों को गुमराह करने में लगे हैं। सुरजीत ने बताया कि 26 नवंबर से 26 जनवरी तक तक़रीबन डेढ़ सौ किसानों की जान ठण्ड और दूसरे कारणों से जा चुकी है। लेकिन सरकार ने किसानों की मौत पर दु:ख तक नहीं जताया है। बल्कि किसानों की मौत पर सियासत कर रही है कि ये तो किसान ही नहीं हैं। ऐसे में किसानों को ग़ुस्सा आना स्वाभाविक है। किसान सुरजीत की मानें तो देश का अन्नदाता जब पहले से बने क़ानूनों से ख़ुश है, तो नये क़ानूनों की ज़रूरत ही क्या है? नये क़ानून हम पर क्यों थोपे जा रहे हैं? दिल्ली के अक्षरधाम मन्दिर के पास ट्रैक्टर रैली को

झण्डा फहराने वाला दीप सिद्धू कौन ?

दिल्ली के जंतर-मंतर में बैठे किसानों के समर्थन में अन्नदाताओं ने कहा कि दीप सिद्धू भाजपा के एक नेता का रिश्तेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ 36 वर्षीय अभिनेता दीप सिद्धू की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दीप ही आन्दोलन को तहस-नहस करने पर तुला है। पंजाब कांग्रेस की युवा नेता जे.एन. ने बताया कि सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों में दीप सिद्धू को सब जानते हैं। उनकी पहल पर ही लाल क़िले पर धार्मिक झण्डा फहराया गया है। उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू को पहले ही आन्दोलन को कुचलने के लिए किसान संगठनों ने अलग कर दिया था। उसके बावजूद वह लाल क़िले में पहुँच गया और धार्मिक झण्डा लगा दिया। इसके पीछे भी सियासत की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो, आन्दोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक कृषि क़ानून वापस नहीं हो जाते। वहीं मामले में दीप सिद्धू का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को नहीं हटाया है, बल्कि नये कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने निशान साहिब और किसान झण्डा साथ लगाये और साथ ही किसान एकता का नारा भी लगाया।

लक्खा सिधाना : कबड्डी खिलाड़ी से लेकर गैंगस्टर और नेता बनने का सफ़र

हिंसा भड़काने में जिस 42 वर्षीय लक्खा सिधाना का नाम आ रहा है, वह पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। सिधाना कभी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम हुआ करता था। बाद में वह राजनीति में आया और फिर समाजसेवा के कामों में लग गया। लक्खा कबड्डी खिलाड़ी भी रह चुका है। खेल से अपराध और फिर राजनीति में आने वाले लक्खा ने किसान आन्दोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गैंगस्टर लक्खा सिधाना का असली नाम लखबीर सिंह है और डबल एम.ए. है। उस पर हत्या, हत्या के प्रयास और

मारपीट के कई आरोप हैं। लक्खा विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन उसकी जमानत ज़ब्त हो गयी थी। सिधाना कुछ साल से पंजाबी सत्कार समिति से जुड़कर पंजाबी भाषा को बचाने के लिए भी काम कर रहा है। इसके अलावा गैंगस्टर पंजाब के युवाओं को बड़े पैमाने पर अपने साथ जोड़ रहा था।

रोकने के लिए पुलिस ने आँसू गैस के गोले दाग़े। इससे झड़पें हुईं, जिसमें किसानों के साथ-साथ कई पुलिसकर्मी भी हुए। लेकिन किसानों का हौसला कम नहीं हुआ, वे आगे बढ़ते गये। आँसू गैस को गोले से घायल किसान मंदीप ने बताया कि वह पिछले दो महीने से किसान आन्दोलन में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम पुलिस और सरकार से लड़ने के लिए नहीं आये हैं, हम नये कृषि क़ानूनों को वापस कराने के लिए आये हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार तीनों क़ानूनों को वापस नहीं लेती, तो वे अपनी जान तक क़ुर्बान करने को तैयार हैं। आँसू गैस का गोला लगने से ट्रैक्टर से गिर पड़ने पर किसान सोनू रंधावा ने कहा कि ये सरकार की दमनकारी नीतियों का नतीजा ही है, जिससे देश का अन्नदाता आज परेशान है। सरकार सत्ता के नशे में चूर है और किसानों की एक नहीं सुन रही।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह का कहना है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली में जो भी उत्पात, उपद्रव और हिंसा हुई है, उसकी वे कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। लेकिन इस हिंसा में किसानों की कोई भूमिका नहीं है। इसमें असामाजिक तत्त्वों के घुसने से माहौल ख़राब हुआ है। पुलिस को इसकी गहन छानबीन करनी चाहिए। मौजूदा हालात को देखते हुए किसानों

"जो किसान नेता आन्दोलन की अगुवाई कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ केंद्र सरकार ने मुक़दमे दर्ज किये हैं। लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह केंद्र सरकार की साज़िश थी।

अभय चैटाला
(विधानसभा से इस्तीफ़ा देने के बाद)

"दिल्ली की क़ानून व्यवस्था और ख़ुफ़िया तंत्र की नाकामी के लिए गृहमंत्री अमित शाह बर्ख़ास्त हों। हिंसा के लिए सीधे गृहमंत्री ज़िम्मेदार हैं। उपद्रवियों की अगुवाई कर रहे अवांछित तत्त्वों पर मुक़दमे दर्ज न कर किसान मोर्चा नेताओं पर मुक़दमों ने मोदी सरकार और उपद्रवियों की मिली-भगत तथा साज़िश को बेनक़ाब कर दिया है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला, *काग्रेस नेता*

"हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और इस क़ानून को तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए। चोट किसी को भी लगे, नुक़सान हमारे देश का ही होगा। देशहित के लिए कृषि-विरोधी क़ानून वापस लो।

राहुल गाँधी
काग्रेस नेता

"आज भाजपा और मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि मुद्दा भटक जाए। किसान नेताओं पर मुक़दर्म दर्ज किये हैं; जबकि देश का अपमान करने वालों के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज नहीं किया है। हमारा सवाल है कि दीप सिद्धू को अब तक क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया है।

राघव चड्ढा
आप नेता

की माँगों पर सरकार को भी ग़ौर करना चाहिए। क्योंकि किसानों के आन्दोलन के चलते मंडियों के साथ-साथ कारोबार भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर धरने में बैठे किसान कश्मीरी सिंह का कहना है कि सरकार कहती है कि जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वे सियासी लोग हैं, किसान। तो सरकार उन सियासतदानों से निपटे। किसानों को बदनाम करने से सरकार को कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये किसान कोई विदेश से नहीं आये हैं। जैसा किसान चाहते हैं, वैसा ही सरकार कर दे, तो ठीक है। अन्यथा किसानों का ये आन्दोलन मई, 2024 तक चलेगा। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसानों का इतना बड़ा आन्दोलन देखने को मिला है, जिसमें ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार से आगे बड़ा टकराव हो सकता है। क्योंकि देश के किसान खेती-बाड़ी को छोड़कर, तमाम नुक़सान उठाकर दिल्ली की सीमाओं पर दो महीने से अधिक समय से बैठे हैं और अब किसी भी हाल में पीछे लौटने को तैयार नहीं हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में 72वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार ऐसा हुआ कि गणतंत्र लहूलुहान हुआ। कुछ हिंसक भीड़ की वजह से, जिसे सरकार और पुलिस किसान बता रही है और किसान किराये के सियासी तथा उपद्रवी लोग; और कुछ सरकार व किसानों की हठधर्मिता की वजह से। लेकिन इस गणतंत्र में दिल्ली की पाँच तस्वीरें बड़ी साफ़ देखने को मिलीं, पहली- किसानों की अहिंसक ट्रैक्टर रैली, दूसरी- दिल्ली के बहुत-से लोगों द्वारा किसानों के स्वागत में पोस्टर लेकर खड़े होना, तीसरी- किसानों और पुलिस की हिंसक झड़प, तीसरी लाल क़िले पर अभद्रता और लाल क़िले के प्राचीर पर धार्मिक झण्डे का फहराया जाने के बावजूद पुलिस की चुप्पी और पाँचवीं- इंटरनेट सेवाएँ बन्द करने की घटना। इसमें दो मामले- झड़प और लाल क़िले की घटना से लोकतंत्र शर्मसार हुआ। आईटीओ यानी दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर बेहद तनावपूर्ण माहौल में किसानों ने पुलिस को चेताया कि सरकार ने अगर क़ानून वापस नहीं लिए, तो भयानक परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई का ख़ौफ़ भी किसानों में देखा गया। एक ओर जहाँ बेहद ख़ामोशी थी, तो दूसरी ओर वे सहमे हुए भी थे। अब पुलिस हरकत में आ गयी है, क्योंकि मामले में क़रीब तीन दर्ज़न लोगों के ख़िलाफ़ा एफआईआर दर्ज की गयी है। माना जा रहा है कि पुलिस आरोपियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई कर सकती है।

ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की निन्दा करते हुए स्वराज इंडिया के नेता व किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की हठ की वजह से किसानों को आन्दोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। लाल क़िले पर धार्मिक झण्डा लगाये जाने की निन्दा करते हुए किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में ये धार्मिक झण्डा लगाया गया है। मामले की जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने से किसान शान्तिपूर्वक तरीक़े से आन्दोलन कर रहे हैं। अगर अचानक ये हिंसा हुई है, तो इसके पीछे ज़रूर कोई सियासी चाल है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के लिए सरकार और पुलिस को ज़िम्मेदार क़रार देते हुए कहा कि जब पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की अनुमति दी थी, तो किसानों को क्यों रोका गया? इतना हीं नहीं, युवा किसानों को उकसाया तक गया। किसान मंगल सिंह ने 'तहलका' को बताया कि सरकार जानबूझकर आन्दोलन को बदनाम करने के लिए किसानों को भड़काया। इसको उन्होंने समझाया कि जब किसान आईटीओ से लाल क़िले की ओर कूच कर थे, तब पुलिस ने क्यों नहीं रोका? और तो और नजफ़गढ़ और द्वारका से किसानों का जत्था ऐलान कर रहा था कि लाल क़िले पर झण्डे को फहराने जा रहे हैं, तो भी पुलिस ने क्यों नहीं रोका? इससे साफ़ ज़ाहिर है कि लाल क़िले की घटना कोई स्वत:स्फूर्त नहीं हुई, बल्कि कहीं-न-कहीं कोई बड़ी चूक हुई है या जानबूझकर होने दी गयी है।

इंटरनेट के साथ 50 मेट्रो स्टेशन करने पड़े बन्द

सुरक्षा के तमाम पुख़्ता दावों के बावजूद 26 जनवरी को दिल्ली में अफ़रा-तफ़री का आलम हो गया था। आनन-फ़ानन में प्रभावित इलाक़ों में इंटरनेट सेवाएँ बन्द कर दी गयीं, बाक़ी जगह भी इंटरनेट की स्पीड कम कर दी गयी। इतना ही नहीं, हरियाणा और पंजाब में भी कई ज़िलों में इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया। इसके अलावा मोबाइल से एसएमएस भेजने पर भी पाबन्दी लगायी गयी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रभावित सीमांत इलाक़ों के 50 मेट्रो स्टेशनों को बन्द कर दिया गया। इसके अलावा कहीं मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो कहीं बाहर नहीं निकलने की। हिंसक झड़पों में क़रीब

300 पुलिसकर्मी घायल हुए। दिल्ली पुलिस के संयुक्त सचिव आलोक कुमार का कहना है कि किसानों ने अपना वादा नहीं निभाया है। उन्होंने गणतंत्र की गरिमा पर प्रहार किया है। मामले में सैकड़ों किसानों व उनके समर्थकों को गिरफ़्तार किया गया। दिग्गज किसान नेताओं के ख़िलाफ़ भी नामजद एफआईआर दर्ज की गयी है।

भाजपा में भी अंतर्कलह!

'तहलका' की जानकारी के अनुसार, सरकार और भाजपा के अन्दर भी सब ठीक नहीं चल रहा है। कुछ पार्टी नेताओं की मानें, तो अन्दरख़ाने मतभेद और कलह का उबाल है, जो लम्बे खिंचते किसान आन्दोलन का नतीजा है। पार्टी में एक बड़ा गुट और कार्यकर्ता नहीं चाहते कि किसानों को कोई परेशानी हो। इललिए वे दबी ज़ुबान या ऑफलाइन यह कह रहे हैं कि तीनों कृषि क़ानून वापस लेने में सरकार को हिचक नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन आलाकमान अपनी ज़िद पर अड़ा है। इससे किसानों का सरकार के प्रति मोह सा भंग हो रहा है। कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि कोरोना काल में कृषि क़ानून को लाकर सरकार ने पूँजीपतियों के लिए काम किया है। उससे किसान ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी नाराज़ हैं, जिससे पार्टी को नुक़सान हो रहा है।

...और बढ़ेगा किसानों का साहस

दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को रोकने लिए सरकार नज़र ज़रूर रख रही है, लेकिन यह भी सच है कि किसानों के समर्थन करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, आन्दोलनकारी किसान सोशल मीडिया के ज़रिये देश भर के किसानों और आम लोगों से जुड़ रहे हैं। टीकरी बॉर्डर में बैठे किसानों का कहना है कि सरकार के रवैये से किसानों का साहस और प्रबल होगा।

इधर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्बित पात्रा ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने जो भी किया है, उससे ये आन्दोलन किसानों के हाथों से निकल गया है। उन्होंने कहा कि ये आन्दोलन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सहयोग से चल रहा था। लेकिन उनकी पोल खुल गयी है। किसान ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आज पूरे देश के किसानों में उग्र सोच रखने वाले नेतृत्व को बल मिलेगा और पूरा आन्दोलन अतिवादी तत्त्वों के हाथों में आ जाने का ख़तरा हो जाएगा। नरमी रखने वालों नेताओं के हाथ से आन्दोलन निकल जाएगा। क्योंकि ये किसान रैली राजनीतिक रूप से मायने रखती है। ऐसे में अगर हिंसा हो रही है, तो ज़रूर चिन्ता का विषय है। जो भी हो, 'तहलका' का मानना है कि देश में किसी तरह की हिंसा, उपद्रव या आन्दोलन सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे देश और देशवासियों का ही नुक़सान करते हैं। इसलिए किसानों और सरकार को जल्द-से-जल्द इस मामले को सुलझा लेना चाहिए, ताकि देश का और नुक़सान न हो। त

letters@tehelka.com

पत्रकारों के ख़िलाफ़ एडआईआर की एडिटर्स गिल्ड ने की भर्त्सना

दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के विरोध-प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकारों के ख़िलाफ़ जिस तरह से डराने-धमकाने के लिए एफआईआर दर्ज की है, उसकी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भर्त्सना की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा, महासचिव संजय कपूर ने 29 जनवरी को एक लिखित बयान में कहा है- 'ईजीआई विभिन्न राज्यों में एफआईआर के ज़रिये मीडिया को डराने, परेशान करने और धमकाने का प्रयास करता है।'

पत्र में लिखा गया बयान :-

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने किसानों के विरोध-प्रदर्शन की रैलियों की रिपोर्टिंग करने पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों राज्यों के वरिष्ठ संपादकों और पत्रकारों (ईजीआई के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों सहित) के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की तीखे शब्दों में भर्त्सना की है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को किसानों की ट्रैक्टर रैली में जबरदस्त हिंसा हुई। पत्रकारों ने इस ख़बर, ख़ासकर प्रदर्शनकारी किसानों में से एक किसान की मौत की ख़बर की रिपोर्टिंग की और कुछ ने उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चलाया। एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा है- 'ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसानों के दिल्ली कूच के दौरान पुलिस और किसानों के बीच क्या होगा? इसकी रिपोर्टिंग करना पत्रकारिता के लिहाज़ से स्वाभाविक था; क्योंकि यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की ज़िम्मेदारी भी है, पत्रकारीय व्यवहार के स्थापित मानदण्डों के अनुरूप भी है और पत्रकारों का काम भी।' पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पत्रकारों ने जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण ट्वीट किये थे, जो कि लाल क़िले की घटना का कारण बने।

वहीं एडिटर्स गिल्ड ने कहा है- 'सच्चाई से कुछ भी दूर नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस ने फिर भी पत्रकारों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है। दोनों प्रदेशों की पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में पत्रकारों पर राजद्रोह क़ानून, साम्प्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने और धार्मिक विश्वासों का अपमान करने सहित 10 विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पत्रकारों को इस तरह निशाना बनाने से हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए खड़े पत्रकारिता के मूल्यों पर गम्भीर चोट हुई है। इसका उद्देश्य पत्रकारों को प्रताड़ित करना और उन्हें निष्पक्ष तरीक़े से काम करने से रोकना है। इसलिए हम माँग करते हैं कि एफआईआर तुरन्त वापस ली जाए और मीडिया को बिना किसी भय और स्वतंत्रता के साथ रिपोर्टिंग करने दी जाए। कई क़ानूनों, जैसे कि देशद्रोह का इस्तेमाल अक्सर बोलने की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए किया जाता है। हम अपनी पहले की माँग पर भी फिर से ज़ोर देते हैं कि उच्च न्यायपालिका इस तथ्य पर गम्भीरता से संज्ञान ले और दिशा-निर्देश जारी करे कि ऐसे क़ानूनों का दुरुपयोग न हो। इस तरह के क़ानूनों का उपयोग स्वतंत्र-निष्पक्ष पत्रकारिता के रास्ते में रोड़े डालने के लिए नहीं करना चाहिए।'

राजे का चक्रव्यूह

वसुंधरा राजे ने बनाया नया संगठन, अलग पार्टी बनाकर भाजपा नेतृत्व को दे सकती हैं झटका

विजय माथुर

प्रदेश भाजपा की भगवा राजनीति में इन दिनों जिस तरह अमूर्त रणनीतियों के पासे चले जा रहे हैं, उनमें किसी धारावाहिक से कम नाटकीयता नहीं है। जिस समय भाजपा की सियासी चर्चा में वसुंधरा राजे के बारे में 'इस्तेमाल करके फेंकने' वाले शब्द-आडंबर पैकेज की षड्यंत्रकारी बातें चल रही थीं, उस समय वसुंधरा के मन में इस बात की आशंका यक़ीन में बदलती दिख रही थी। अब जब उन्हें भाजपा नेतृत्व की नीयत में खोट का लगातार अहसास होने लगा, उन्होंने एकाएक अपने समर्थकों को साथ लेकर 'टीम वसुंधरा' नाम का संगठन खड़ा करके पार्टी नेतृत्व को हक्का-बक्का कर दिया। वसुंधरा राजे के आकस्मिक विस्फोट का क्या अर्थ लगाया जाए? विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पार्टी (भाजपा) में बाहर का रास्ता दिखाने के लिए चिह्नित की गयीं राजे महज़ हवा का रुख़ भाँपने के लिए पतंग उड़ा रही हों।

सूत्रों का कहना है कि फ़िलहाल तो भाजपा नेतृत्व ने इस उकसावे को अनदेखा कर दिया है और असल नीति बनने तक इंतज़ार करना बेहतर समझा है। राजनीति के इस तूफ़ानी मंजर में भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी में वसुंधरा राजे को शामिल करने से तो यही लगता है। विश्लेषकों का कहना है कि विरोध के इस जलसे पर भाजपा की उदास ख़ामोशी का क्या मतलब हुआ? विश्लेषक इसे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कुटिल पैंतरे की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि दरअसल पूनिया वसुंधरा पर ताबड़तोड़ हमले कर पार्टी में अपने विश्वास का निवेश करना चाहते हैं। लेकिन पूनिया का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उनके बढ़ते हमलों ने प्रदेश की राजनीति में वसुंधरा का क़द और ऊँचा कर दिया है। भले ही इस मुद्दे पर दिल्ली का असमंजस चौंकाता है। लेकिन दिल्ली की बेख़ुदी बेसबब भी तो नहीं, कुछ तो परदादारी है। आख़िर इस दोहरे खेल का क्या मतलब है कि एक तरफ़ तो प्रदेश कार्यकारिणी में वसुंधरा समर्थकों को फटकने तक नहीं दिया।

भाजपा नेतृत्व में डर भी

दूसरी तरफ़ वसुंधरा को कोर कमेटी में शामिल कर लिया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि यह ख़बरों के सिलसिले को अपने हिसाब से फेंटने और लगातार आ रही बुरी ख़बरों से ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। अलबत्ता यह कोई साधारण सियासी गणित नहीं है। इस गोपनीय गणितीय आकलन के जो भी मायने रहे हों, वसुंधरा ने कोर कमेटी की बैठक में जाना तो दूर, उधर का रुख़ भी नहीं किया। इससे कहीं-न-कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व एक डर तो है कि कहीं आने वाले समय में राजस्थान में वह बहुत कमज़ोर न हो जाए। भले ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने दफ़्तर में अपनी पीठ ठोंकने की मुद्रा में बैठे हों, लेकिन न तो उनकी कार्रवाइयों में षड्यंत्र छिपाये छिप रहे हैं और न पार्टी नेतृत्व को क़रार पड़ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि सतीश पूनिया को टकराव के अलावा कोई दूसरी राजनीति नहीं आती। इसलिए उन्होंने गवर्नेंस के मूलभूत कामों पर भी टकराव को ही संवाद बना लिया। बहरहाल फ़िलहाल तो उपेक्षा के अभिशाप से जूझ रही वसुंधरा कुछ भी कहने की बजाय धौलपुर महल में शाही चुप्पी ओढ़े बैठी हैं। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी शक्ति का अहसास कराने के लिए यह क़दम उठाया है। अब तक प्रदेश के 28 ज़िलों में इस संगठन का गठन हो चुका है। समझा जाता है कि यह संगठन वसुंधरा की भाजपा में यथास्थिति में वापसी के लिए प्रभावी मंच साबित हो सकता है। हालाँकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसे जुगाड़ का नाम दे रहे हैं। बहरहाल वसुंधरा राजे ने तीसरे मोर्चे की सम्भावनाओं का ढक्कन तो खोल ही दिया है। उधर वसुंधरा राजे के धुर विरोधी गिने जाने वाले विधायक मदन दिलावर का कहना है कि टीम वसुंधरा राजे से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। जिसने भी यह संगठन बनाया, भाजपा से उसका कोई सरोकार नहीं हो सकता। विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच यह लुकाछिपी का खेल विधानसभा चुनावों में भाजपा की पराजय के बाद से ही चल रहा है। इस सियासी पतंग की डोर आरएसएस के हाथों में है। संघ वसुंधरा को सक्रिय राजनीति या चुनावी राजनीति में देखना ही नहीं चाहता। नतीजतन लाख प्रतिरोध के बावजूद वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने दिया गया। राजे की असहमतियों के बावजूद एक दूरदर्शी फ़ैसले के तहत गुलाब चंद कटारिया को यह पद सौंप दिया गया। जिस वक़्त नेता प्रतिपक्ष पद पर कटारिया की ताजपोशी की जा रही थी, वसुंधरा के चेहरे पर खीझ के भाव साफ़ नज़र आ रहे थे। टीम वसुंधरा के गठन की पटकथा अनायास ही नहीं लिख दी गयी। सूत्रों

वसुंधरा समर्थकों की पार्टी नेतृत्व को चेतावनी

वसुंधरा समर्थकों ने दबाव की राजनीति का कार्ड खेलते हुए पार्टी हाईकमान को दो-टूक शब्दों में कह दिया है कि अगले विधानसभा चुनावों के लिए वसुंधरा राजे को अधिकृत रूप से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए। राजे के पूर्व मंत्रिमंडलीय सहयोगी और छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए पार्टी आलाकमान को कह दिया है कि राजस्थान में अगले विधानसभा चुनावों के लिए वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। सिंघवी का कहना था कि वसुंधरा राजे राजस्थान में भाजपा की सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को चेतावनी भरा मशविरा देते हुए कहा कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो पार्टी को पराजय के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि पार्टी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। पार्टी का सिर्फ़ एक ही चेहरा है और वह नरेंद्र मोदी हैं। सवाल यह है कि क्या पूनिया मोदी के नाम का सहारा लेकर किसी और की राह में रोड़ा बनकर ख़ुद मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ़ यह सवाल है कि क्या सिंघवी की चेतावनी वाक़ई वसुंधरा का भाजपा के ही ख़िलाफ़ पार्टी बनाकर आगामी विधानसभा के चुनावों में मैदान में कूदने को लेकर है? क्योंकि वसुंधरा राजे पहले दो बार पार्टी नेतृत्व को अपना अलग दल बनाने की धमकी दे चुकी हैं। लेकिन इस बार तो वह संगठन भी बना चुकी हैं। कुल मिलाकर अब गेंद भाजपा नेतृत्व के पाले में है। अगर वह राजस्थान में वसुंधरा नेतृत्व को स्वीकार करता है, तब तो ठीक, अन्यथा लगता तो यही है कि पार्टी में पड़ी फूट अलग ही इतिहास गढ़ेगी। बहरहाल, क्या होना है? यह तो भविष्य ही बतायेगा।

की मानें तो सम्भवत: यह मकर संक्रांति की पूर्व संध्या थी, जब वसुंधरा के बेहद ख़ास माने जाने वाले भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के घर पर वसुंधरा गुट के तमाम विधायकों और सांसदों की गुप्त बैठक हुई। यह बैठक विधायकों, सांसदों का जमावड़ा अधिक लग रही थी। इस बैठक में वसुंधरा राजे ख़ुद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअली जुड़ी हुई थी। अधिकांश की राय थी कि वसुंधरा राजे अपना अलग राजनीतिक दल बनाएँ और अगले विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ शुरू कर दें। हालाँकि बैठक में ठहाकों की गूँज भी थी। लेकिन इन हँसी-ठहाकों के पीछे दर्द भी छिपा था।

दरअसल पिछले दिनों भाजपा नेतृत्व द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया को फ्री हैंड दिये जाने के बाद यह बात तक़रीबन तय हो चुकी थी कि पूनिया कभी भी वसुंधरा को राजनीतिक वानप्रस्थ पर भेजने के अपने खेल में सफल हो सकते हैं। वसुंधरा समर्थकों का अभिमत था कि फ़िलहाल केंद्रीय नेतृत्व को गुर्राहट दिखाने की बजाय 2008 और 2013 की दबाव की राजनीति करनी चाहिए। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति लेकर देव दर्शन यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इस बीच पूनिया की त्रिपुरा सुन्दरी की यात्रा को लेकर नयी अटकलें शुरू हो गयी हैं।

त्रिपुरा सुन्दर की आराधना

उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा सुन्दरी वसुंधरा राजे की अराध्या है। जब भी राजे राजनीतिक दूरभिसंधियों से दो चार हुईं, उन्होंने त्रिपुरा सुन्दरी के मन्दिर की तरफ़ ही रुख़ किया। ऐसे में सतीश पूनिया का त्रिपुरा सुन्दरी जाना और राजसमंद में भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश देना इस बात का साफ़ संकेत है कि भाजपा संगठन वसुंधरा राजे के ख़िलाफ़ उन्हीं हथियारों की आजमाइश कर रहा है, जिनके बूते वसुंधरा दो बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। बहरहाल राजे की देव दर्शन यात्रा के बारे में कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी।

राजनीति के जानकार कहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच शीत युद्ध चरम पर है, वहीं भाजपा में भी वसुंधरा राजे और संगठन मुखिया के नाते सतीश पूनिया के बीच सियासी पैंतरेबाज़ी चरम पर है; जिसके और तेज़ होने की सम्भावना जतायी जा रही है। इसे संयोग नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में भाजपा की कलह उस समय सतह पर आयी, जब कॉर्पोरेशन चुनावों में पार्टी ने अपने जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े क़िले गँवा दिये। हालाँकि इसका अंदेशा पहले से ही था कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक वरिष्ठ नेता आंतरिक आकलन का हवाला देते हुए कहते हैं कि पिछले दो साल में यह पहला मौक़ा है, जब किसी चुनावी रण क्षेत्र से वसुंधरा राजे लापता रहीं। चुनावों की बाग़डोर ऐसे लोग थामे हुए थे, जिनका न कोई रसूख़ था और न ही कोई तजुर्बा। उन्होंने कहा कि

प्रधानजी बने पूनिया !

निगम चुनावों में जिस तरह भाजपा की मिट्टी पलीद हुई, उसकी राजनीतिक रणनीति का सबसे दुखांत पहलू क्या रहा? इन दिनों केसरिया ख़ेमे में सबसे ज़्यादा कोलाहल इसी बात को लेकर है। हालाँकि चुनावी नतीजों के बाद एक बनवटी बहस चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पार्टी के अंदरख़ाने से रिसती ख़बरों की बात करें, तो प्रदेश भाजपा में अध्यक्ष के तौर पर सतीश पूनिया ने जबसे पद सँभाला है, भाजपा के हर संगठनात्मक फ़ैसले में संगठन की भूमिका निर्णायक हो गयी है। सही मायनों में देखें, तो प्रधानजी (पूनिया) पार्टी नेतृत्व की खुली छूट के चलते ब्रांड एम्बेसेडर की तरह हो गये हैं। नतीजतन पार्टी को डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह चला रहे हैं। यह स्थिति भाजपा के स्वयंभू नेताओं के लिए किस क़दर अखरने वाली है, कहने की ज़रूरत नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि जब कोई राजनीतिक दल अपनी प्रगति के लक्ष्य बदलता है, तो उसे चिन्ताओं के आयाम भी बदल लेने चाहिए। अन्यथा बेगानगी दलीय निष्ठा का तियाँ-पाँचा कर देती है। कोई राजनीतिक दल जब तक एक दबाव समूह के रूप में होता है, वह स्वच्छंद तरीक़े से व्यवहार कर सकता है; लेकिन आज भाजपा दबाव समूह के रूप में है। जबकि सतीश पूनिया की सदारत में पार्टी अनेक सवालों से घिरी है, जो उसकी विरासत और वैचारिक मिशन से मेल नहीं खाते। लेकिन सवाल है कि जब सिद्धांतकार बनकर कारण तलाशेंगे, तो नतीजा समझा जा सकता है। ग़लतफ़हमी की खोह की अथाह गहराई में गले-गले तक डूबे पूनिया का मन पढ़ें, तो वही पार्टी का विस्तार हैं; जो कि अपने मन में महाराजा होने जैसा ही है। इसलिए वह ही सम्पर्क मिशन का शुभंकर हैं, वह ही पार्टी के कर्ता-धर्ता हैं और वही प्रधानजी हैं। लेकिन प्रधानजी की पूरी तरह आवभगत में लगे राष्ट्रीय नेतृत्व को शायद ही अंदाज़ा होगा कि उनकी सांगठनिक मनमानी थुलथुलेपन का साझेदार हो जाएगी। पार्टी में सदाबहार गुटबन्दी के चलते भले ही पूनिया प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना की विदाई में सफल हो गये; लेकिन क्या उनकी जगह लेने वाले अरुण सिंह पूनिया की कूटनीतिक पच्चीकारी में फँस पाएँगे? सूत्रों का कहना है कि संघ अब तक भाजपा में भेजे गये विश्वस्त स्वयं सेवकों पर निर्भर रहता आया है। किन्तु इसके परिणामों ने इस सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है कि राजनीतिक शैली एवं प्रक्रियाओं पर नियंत्रण ज़रूरी है। सूत्रों का कहना है कि कुल मिलाकर पूनिया का मकड़जाल राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे को परे रखने और रजवाड़ी राजनीति की नायिका दीयाकुमारी को लाइम लाइट में लाने का है। लेकिन विश्लेषकों की मानें, तो सियासी दूरंदेशी के मायने में पूनिया वसुंधरा राजे के आगे बहुत बोने हैं। कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर पूनिया पार्टी दफ़्तर में सिर्फ़ गुलदस्ता बनकर रह जाएँ!

बेशक सियासत पैंतरे और चेहरे बदलती है, लेकिन राजस्थान की रेतीली राजनीति में तो भाजपा का मतलब ही वसुंधरा राजे हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से उनकी अनदेखी पार्टी को पराजय की ढलान पर लुढ़कने से कैसे रोक पाती?

अवसरवाद की राजनीति !

प्रदेश में चल रहे इस केसरिया कोलाहल को लेकर राजनीतिक जानकारों का नज़रिया कहता है कि राजनीतिक दलों के अपने-अपने हित होते हैं। ऐसे में राजनीति को अवसरवाद का आईना कहना ज़्यादा सटीक होगा। इसलिए किसी नेता का अगला क़दम क्या होगा? इस बाबत कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस मुकाम पर यह तर्क समझना आसान नहीं हो सकता कि बीती चुनावी फ़िज़ाँ में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे की तारीफ़ में क़सीदे पढ़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी कि जब तक वसुंधरा हैं, राज्य में नेतृत्व कोई मुद्दा नहीं है। आज वही वसुंधरा नेतृत्व की आँखों का कांटा बन गयी हैं। हालाँकि इस ज़ोर आजमाइश की राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा बौद्धिकता के साथ व्याख्या करते हैं कि अगर नये नेतृत्व को सक्रिय करना है, तो उन्हें काम करने की आज़ादी देनी होगी। इसलिए प्रदेशों में बरसों से जमे पुराने नेताओं को वहाँ से बाहर निकालकर केंद्रीय राजनीति में सक्रिय करना होगा, तभी राज्यों में नया नेतृत्व उभरेगा। चर्चित अनुवादक आलोक राय कहते हैं कि राजनीति जोड़-तोड़ और छल-प्रपंचों की महारत रचने का मैदान बन गया है। इसलिए कैसी भी किसी घटना-परिघटना पर तात्कालिक टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो दर्द की गर्द को ज़िन्दगी भर बैठने नहीं देना चाहते। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया भी ऐसे ही हैं। और सियासी रंजिश के ऐसे अलाव को भड़काने के लिए घास-फूँस डालने वालों की कौन-सी कमी रहती है? यह काम विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेन्द्र सिंह राठौड़ बख़ूबी कर रहे हैं। सतीश पूनिया यह भूलने को तैयार ही नहीं हैं कि वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया। दिलचस्प बात है कि इस दौड़ में पूनिया संघ की पहली पसन्द थे; जबकि वसुंधरा राजे दोबारा से ताजपोशी पर तुली हुई थीं।

संघ की पसन्द पूनिया

पार्टी अध्यक्ष अमित शाह तो यहाँ तक कह चुके थे कि जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, वहाँ मुख्यमंत्री का ख़ास समझा जाने वाला व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष नहीं होना चाहिए; इससे संगठन चौपट हो जाता है। इस सियासी खींचतान में जिस तरह पूनिया की भद्द उड़ी, उसे न तो

पूनिया भूलने को तैयार हैं और न ही संघ। वसुंधरा को लेकर संघ के थिंक टैंक की अनेक आशंकाएँ हैं। संघ के पदाधिकारियों का मानना है कि वसुंधरा शक्तिपुंज बनकर फिर अधिनायकवाद को बढ़ावा दे सकती हैं। तब भाजपा की रीति-नीति के विरुद्ध एक अटपटा परिदृश्य उभर आयेगा। एक आशंका यह भी है कि कालांतर में पार्टी में धृतराष्ट्र, भीष्म और गांधारियों का बोलबाला हो जाएगा; जिसकी परिणिति इस परिदृश्य में होगी कि वसुंधरा का आचरण अहसान करने जैसा हो जाएगा कि उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा बहुमत लेकर आयी, अन्यथा किसमें इतनी सामर्थ्य थी?

प्रधानमंत्री के मन में खटास

वसुंधरा की वापसी को लेकर पार्टी नेतृत्व भी विश्वास की लकीर खींचने को तैयार नहीं है। वसुंधरा का रोचक राजनीतिक रोज़नामचा बाँच चुके रणनीतिकार अनेक दृष्टांत गिनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से तो राजे के रिश्तों में तब खटास आ गयी थी, जब वसुंधरा प्रतिगामी राजनीति की पटरी पर चल पड़ी थी। विश्लेषकों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वसुंधरा को राज्य की नयी गवर्नेंस का सूत्रधार होना चाहिए था, वह अचानक मोदी मॉडल की सबसे कमज़ोर कड़ी बन गयी है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर रहे ललित मोदी को लेकर पासपोर्ट विवाद ने भाजपा नेतृत्व को कितनी मुश्किलों से दो-चार होना पड़ा था। कहने की ज़रूरत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर पार्टी में सुलग रही आग आज भी नहीं बुझी है। राजमहल होटल विवाद ने भाजपा नेतृत्व को क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा था? कहने की ज़रूरत नहीं है।

क्या सियासी दाँव समझ चुकी थीं राजे

अतीत के पन्ने पलटें, तो राज्य में समग्र बदलाव का ख़ाका खींचने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने राजे को विकल्प भी दिया था कि आम चुनाव जीतने के बाद विधानसभा सीटों से इस्तीफ़ा दिलवाकर उनके बेटे दुष्यंत को चुनाव लड़वाया जाए, ताकि राज्य की सियासत में युवा सक्रिय भूमिका निभा सकें। लेकिन राजे ने केंद्रीय नेतृत्व के दाँव पर खेलने से साफ़ इन्कार कर दिया। राजे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इसलिए भी तैयार नहीं थीं, क्योंकि इससे उनके बेटे दुष्यंत की उम्मीदवारी ख़तरे में पड़ जाती; जो इस समय झालावाड़ से सांसद हैं। राजे के निकटवर्ती सूत्रों का कहना है कि वह इस व्यवस्था के पीछे छिपा संदेश पढ़ चुकी थीं। उन्होंने इस बात को भी समझ लिया था कि उन्हें सियासत की किस धुरी पर स्थापित किया जाएगा? सूत्र कहते हैं कि राजे इस मुद्दे पर भी नाराज़गी भरी चुप्पी साधे रही हैं कि उन्हें पार्टी संगठन में उपाध्यक्ष का ओहदा तो बख़्श दिया, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनावों के लिए बनायी गयी 17 समितियों में से एक में भी जगह क्यों नहीं दी गयी? जबकि इन समितियों में केंद्रीय मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों और हिन्दी भाषी राज्यों के नेताओं को प्रमुखता से जगह दी गयी। राजे के निकटवर्ती सूत्रों का कहना है कि उन्हें यह कहकर उपाध्यक्ष बनाया गया था कि उन जैसी जनाधार वाली और सक्रिय नेता के दिल्ली जाने से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूती मिल सकती है। निकटवर्तियों का कहना है कि उनकी (वसुंधरा की) तेज़-तर्रार नेता की छवि और अनुभव का फ़ायदा पार्टी को आम चुनावों में राजस्थान समेत अन्य राज्यों को मिल सकता था, तो फिर समितियों से उन्हें दूर क्यों रखा गया?

राजे इस बात से भी ख़फ़ा हैं कि लोकसभा चुनावों में भाजपा के सभी मोर्चों की संयुक्त कार्यशाला में लगे बैनर-पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दीन दयाल उपाध्याय और सुंदर सिंह भंडारी के ही फोटो क्यों थे? कार्यशाला जब जयपुर में आयोजित हुई, तो प्रदेश की क़द्दावर नेता होने के नाते उन्हें भी पोस्टरों में जगह देनी चाहिए थी; लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वसुंधरा के व्यवहार में हमेशा चक्रवर्ती होने की बात झलकती है। बेशक भाजपा नेतृत्व ने वसुंधरा के धुर-विरोधी संघनिष्ठ सतीश पूनिया को प्रदेश का मुखिया बनाकर उन्हें पूरी तरह फ्री हैंड कर दिया है। लेकिन वसुंधरा कहते नहीं अघातीं कि यह पार्टी मेरी माँ विजयाराजे सिंधिया ने बनायी और बढ़ायी है। उनके नाम और काम से ही आज भाजपा शिखर पर पहुँची है। ऐसे में उन्हें (वसुंधरा को) राजनीतिक वानप्रस्थ पर भेजने की तैयारी क्यों? तहलका

letters@tehelka.com

मोहरा चुनने की मनमानी

अपने मन की करने के मामले में वसुंधरा राजे की बराबरी भाजपा का शायद ही कोई क्षत्रप कर सके। जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उप चुनावों की पराजय से ख़फ़ा होकर वसुंधरा राजे के सर्वाधिक भरोसेमंद प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को हटाया था, तो उनकी जगह लेने के लिए नये शख़्स की राजनीतिक तस्वीर 70 दिनों तक धुँधली ही बनी रही। प्रदेश अध्यक्ष पद पर अपनी पसन्द का नेता बैठाने की जद्दोजहद में दिल्ली में डेरा डाले रहे मुख्यमंत्री के समर्थकों को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि नया प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा? हालाँकि सब जानते थे कि इसका फ़ैसला तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। मामले का पटाक्षेप इसलिए भी आसानी से नहीं हो पाया, क्योंकि इसी अखाड़े से चुनावी टिकट बँटवारे का दंगल होना था। बेशक केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पसन्दीदा नेता गजेन्द्र सिंह शेखावत का नाम पाले में फेंककर तसल्ली कर ली कि शेखावत के अलावा कोई और नाम क़ुबूल नहीं। बावजूद इसके वसुंधरा राजे आत्मविश्वास से कितनी लबरेज थीं, इसका मुजाहिरा तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाक़ात के बाद मीडिया के सवाल पर कर दिया था- 'आप मेरा चेहरा देखिए...' इसके साथ ही राजे मुस्कुराते हुए निकल गयीं। आख़िरकार पार्टी संगठन के नेता व सांसद भूपेन्द्र यादव, किरोड़ीलाल मीणा और ओम माथुर के साथ लम्बे बहस-मुबाहिसों के बाद नये प्रदेश अध्यक्ष का नाम मदनलाल सैनी पर आकर टिका। भले ही यह नाम कभी सुर्ख़ियों में ढला हुआ नहीं रहा; लेकिन प्रिंट मीडिया का कयास सही निकला, जिसमें कहा गया था कि नया प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

मदनलाल सैनी की तैनाती कैसे हुई और इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उत्पन्न विवाद पर भाजपा नेता ओम माथुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का आग्रह किया था; साथ ही मशविरा दिया था कि अगर लोगों को गजेन्द्र सिंह शेखावत स्वीकार्य नहीं, तो किसी और की नियुक्ति की जाए। नतीजतन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात मानी और शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की ज़िद छोड़ दी। हालाँकि सूत्रों का कहना है कि गजेन्द्र सिंह को नकारने से भाजपा को राजपूत वोट बैंक से हाथ धोना पड़ा। इधर मदन लाल सैनी वह संघ परिवार के अग्रिम संगठन भारतीय मज़दूर संघ के नेता थे; लिहाज़ा उन्हें किसी गुट का मानने का सवाल ही नहीं था। जनाधार की बात करें, तो भी उनके अपने घर शेखावाटी तक में उन्हें कोई नहीं जानता। सवाल यह है कि चुनाव क़रीब होने की बात देखते हुए क्या भाजपा के पास इतना समय था कि उन्हें जनसम्पर्क की मचान पर बैठाने के लिए लोकप्रियता के पायदान पर लाया जाता? जबकि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका सेनापति की होती है। लेकिन जब सेना ही उन्हें नहीं जानेगी, तो जनता कैसे जान पाएगी?

गिद्ध पत्रकारिता !

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के लीक व्हाट्स ऐप चैट्स से जो चीज़ें बाहर आयी हैं, उन्होंने मीडिया जगत में ही नहीं, सुरक्षा और राजनीतिक हलक़ों में भी खलबली मचा दी है। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह इस मामले की जाँच करवाये कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारी कैसे एक पत्रकार तक पहुँच गयी? विपक्ष ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हुए पुलवामा और ऑपरेशन बालाकोट को लेकर फिर सवाल उठा दिये हैं। टीआरपी स्कैम से शुरू हुआ यह मामला अब बेहद गम्भीर मुद्दे पर आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि अर्नब चैट गेट ने एक पत्रकार और सरकार के बीच गठजोड़ को बेनक़ाब किया है। विशेष संवाददाता **राकेश रॉकी** की रिपोर्ट :-

ढेरों सवालों / आरोपों को अपने ऊपर ओढ़े हुए यह नये दौर की पत्रकारिता है; टीआरपी और राजनीति की स्याही में गहरे से भीगी पत्रकारिता! इसमें देशभक्ति के नाम पर राजभक्ति है। यानी अब पत्रकारिता की परिभाषा भरोसे की चिन्दी-चिन्दी है। इसका प्रमाण देश की सुरक्षा से जुड़ी ख़ुफिया जानकारियों पर व्हाट्स ऐप चैट्स में अर्नब-पार्थो के लगते शाब्दिक अट्टहास से मिल जाता है। टीआरपी और राजनीतिक आकाओं की बदौलत कैसे कोई पत्रकार दिखावटी देशभक्ति का ड्रामा करता है, यह रिपब्लिक चैनल के प्रमुख अर्नब गोस्वामी गोस्वामी और ब्राडकॉस्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता के बीच हुए कथित व्हाट्स ऐप चैट्स से ज़ाहिर हो जाता है, जो अब लीक हो चुकी हैं। यह व्हाट्स ऐप चैट्स 10-20 नहीं हैं। इनकी संख्या इतनी है कि क़रीब 500 पृष्ठों में आयी है। इन लीक व्हाट्स ऐप चैट्स से कई सवाल पत्रकारिता पर तो उठे ही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी उठे हैं। आने वाले समय में कुछ और चैट्स लीक हो सकती हैं। दिलचस्प यह भी है कि इस लीक चैट्स का खण्डन अभी तक न तो सरकार ने किया है और न ही अर्नब ने; भले ही इसे जोड़कर कुछ और बातें कही गयी हों।

कश्मीर में कुछ बड़ा होगा! मतलब क्या है? अर्नब गोस्वामी की चैट के इस हिस्से को कश्मीर में अनुच्छेद-370 को ख़त्म करने से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी नीत केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्ज़ा ख़त्म करके उसे दो हिस्सों में बाँट दिया। कुछ चैट्स 2019 की हैं, जब लोकसभा चुनाव को

कुछ महीने थे और इसके बाद ही पुलवामा में भारत के वीर जवानों ही शहादत हुई थी और बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई हुई थी। कांग्रेस ने एक पत्रकार वार्ता करके इस सारे मामले की जाँच की माँग की है और इसे देशद्रोह बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह किसी दुश्मन देश पर हमला करने की एडवांस जानकारी केबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) के पाँच सदस्यों और सरकार में एक-दो टॉप के लोगों को ही होती है। इसके बाद हमला कब होना? कहाँ होना है? यह निर्णय वायुसेना लेती है। ऐसे में यह बहुत गम्भीर बात है और सवाल उठता है कि एक निजी चैनल के पत्रकार अर्नब को यह महत्त्वपूर्ण जानकारी किसने दी?

सुरक्षा फ़ैसलों, और वह भी दूसरे देश में सैन्य कार्रवाई के मामले में देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी जानकारी कभी किसी पत्रकार के पास पहले से आ गयी हो और वह उसे बड़े लापरवाह तरीक़े से सोशल मीडिया पर किसी अन्य से साझा कर रहा हो। दूसरे बालाकोट और पुलवामा से जुड़ी जानकारी को लेकर अर्नब और दासगुप्ता की कथित लीक चैट्स में जो बातें कही गयी हैं, उनको लेकर भी ढेरों सवाल उठाते हैं। इसमें 'बिग मैन' को लाभ मिलने की बात की गयी है, जिससे बड़ा विवाद पैदा हो गया है। यह माना जा रहा है कि इसमें बिग मैन शब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया है, अर्थात् बालाकोट और पुलवामा से

उन्हें (भाजपा, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी को) 2019 के लोगसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ मिलने की सम्भावना जतायी गयी है। वरना इस तरह के सैन्य अभियान या भारतीय सैनिकों की आतंकवादियों के हाथों शहादत को पहले से ही क्यों बिग मैन को लाभ मिलने से जोड़ा गया है? क्या यह सब पहले से ही तय था? क्योंकि दोनों घटनाएँ 2019 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले की हैं। ज़ाहिर है देश के एक बड़े पत्रकार के व्हाट्स ऐप चैट लीक ने बहुत गम्भीर सवाल देश के सामने खड़े कर दिये हैं।

सब जानते हैं कि मुम्बई पुलिस टीआरपी स्कैम की जाँच कर रही है। निश्चित ही उसने अपना पक्ष मज़बूत करने के लिए अर्नब और अन्य के मोबाइल फोन खँगाले होंगे। इसमें भी कोई दो-राय नहीं कि यह व्हाट्स ऐप चैट वहीं कहीं से लीक हुई होगी। चैट्स ग़लत या झूठी होतीं, तो निश्चित ही अर्नब और सरकार ने इनका खण्डन कर दिया होता। अब तक नहीं किया, तो इसका मतलब यही कि इनमें सच्चाई होगी। लेकिन इनमें जो चीज़ें सामने आ गयीं; पहली, वो सिर्फ़ टीआरपी स्कैम तक सीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद संवेदनशील मुद्दों पर जिस तरह तफ़रीह के मूड में चैट हुआ और जिस तरह इसमें राजनीतिक लाभ की बातें हुईं, उन्होंने देश के चौंका दिया है। यह बातें बहुत गम्भीर हैं।

अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता के बीच की चैट (लीक) का एक अंश :-

अर्णब हाँ एक और बात, कुछ बड़ा होने वाला है।

पार्थो दाऊद?

अर्णब नहीं सर, पाकिस्तान! इस बार कुछ बड़ा होने वाला है।

पार्थो ऐसे वक़्त में उस बड़े आदमी (बिग मैन) के लिए अच्छा है, तब वह चुनाव जीत जाएगा। स्ट्राइक? या उससे भी कुछ बड़ा?

अर्णब सामान्य स्ट्राइक से काफ़ी बड़ा और साथ ही इस बार कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर सरकार को विश्वास है कि ऐसा स्ट्राइक होगा, जिससे लोगों में जोश आ जाएगा।

दूसरी, सरकार की देशसेवा पर सवाल उठते हैं। तीन महीने पहले मुम्बई पुलिस ने दावा किया

था कि बार्क के पूर्व सीओओ रोमिल रामगढ़िया ने अर्णब के रिपब्लिक टीवी की लॉन्चिंग के क़रीब 40 हफ़्तों में उनके प्रतिस्पर्धी चैनलों की टीआरपी रेटिंग से छेड़छाड़ की थी, जिससे रिपब्लिक की टीआरपी बढ़ जाए। इसी सिलसिले में पार्थो दासगुप्ता गिरफ़्तार हुए और उनका फोन पुलिस ने अपने क़ब्ज़े में ले लिया। इसके इस चैट में कई काले सच उजागर हुए। एक जगह टीआरपी देने के एवज़ में दासगुप्ता ट्राई पर दबाव डलवाने की बात कर रहे हैं और एक जगह अर्नब से पूछा जा रहा है कि क्या वह किसी एएस से कहकर ट्राई पर नकेल कसवा सकते हैं?

लीक चैट के अन्य कुछ हिस्से बहुत ख़तरनाक संकेत देते हैं। इनमें देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और हमारे सैनिकों की शहादत से जुड़ा है। कथित चैट में अर्नब एक जगह दावा कर रहे हैं, उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी तीन दिन पहले ही हो गयी थी। यह मामला इसलिए गम्भीर है कि इस तरह के ऑप्रेशन बहुत महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील होते हैं और उन्हें बहुत गोपनीय रखा जाता है, ताकि दुश्मन को भनक भी न लगे। एक पत्रकार को तीन दिन पहले ही इसकी जानकारी हो गयी। निश्चित ही एक बेहद गोपनीय ऑप्रेशन की जानकारी लीक होने से योजना पर पानी फिर सकता था या हमारे देश के जवानों की ज़िन्दगी भी ख़तरे में पड़ सकती थी।

बहुत-से जानकार अब इसे राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ बता रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इसकी जाँच होगी? कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) इसकी जाँच की माँग कर चुकी है। कांग्रेस अर्नब को गिरफ़्तार करने की माँग कर चुकी है। सरकार ने फ़िलहाल इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। लीक चैट में एक मौक़े पर अर्नब गोस्वामी अपने चैनल की टीआरपी के लिए दिवंगत पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली को भी लपेट लेते हैं। जेटली की मृत्यु को अर्नब के हिन्दी चैनल रिपब्लिक भारत पर एक 'बड़ी जीत' की तरह दर्शाया गया। अब कई नेताओं और अन्य हस्तियों ने गोस्वामी की इसके लिए निंदा की है। इन चैट्स के लीक होने के बाद अर्नब और सरकार सवालों के घेरे में हैं। नैतिकता का ढोल पीटने वाले अर्नब आज अनैतिकता की ऊँची मीनार पर बैठे दिख रहे हैं।

याद रहे मुम्बई पुलिस ने पिछले साल 24 दिसंबर को दासगुप्ता को गिरफ़्तार किया था। अर्नब गोस्वामी से सीधे जुड़ी 500 से ज़्यादा पन्नों की व्हाट्स ऐप चैट्स आज सोशल मीडिया में वायरल हैं। 'तहलका' की जानकरी के मुताबिक, अगले हफ़्तों में इस तरह की और चैट्स लीक हो सकती हैं या कोर्ट में बतौर सुबूत पेश की जा सकती हैं। वैसे इस मामले में अभी तक 15 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और दो बार (नवंबर और जनवरी में) चार्जशीट भी दायर की गयी हैं और लीक चैट्स चार्जशीट का हिस्सा हैं। अभी कुछ और लोगों की तलाश अधिकारियों को है। अर्नब और दासगुप्ता के बीच कथित व्हाट्स ऐप चैट्स टीआरपी घोटाले में मुम्बई पुलिस के 3,600 पन्नों की पूरक चार्जशीट का हिस्सा हैं, जो 11 जनवरी को दाख़िल की गयी।

टीआरपी मामले की बात करें तो चैट्स से ज़ाहिर होता है कि दासगुप्ता और अर्नब लगातार सम्पर्क में थे। बार्क के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रोमिल रामगढ़िया और रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी के बीच हुए चैट भी सामने

"यह बेहद संगीन मामला है। सरकार को उसी वक़्त कार्रवाई करनी चाहिए थी और इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। मैं ख़ुद सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करता रहा। यह क्या हो रहा है? कि सुरक्षा के ऐसे संवेदनशील मामलों को बिना किसी जाँच के पसरने दिया जा रहा है; जबकि अनाप-शनाप फेसबुक पोस्ट करने वालों को पीट दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है।

रवीश कुमार

वरिष्ठ पत्रकार के एक लेख का हिस्सा

"बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी बस चार या पाँच लोगों को थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वायुसेना प्रमुख। और इनमें से ही किसी ने अर्नब गोस्वामी को जानकारी दी है। यह एक आपराधिक कृत्य है। जिसने जानकारी दी और जिस व्यक्ति के पास जानकारी आयी, दोनों के ही ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए; जाँच की जानी चाहिए। लेकिन यह जाँच कभी शुरू ही नहीं होगी। मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि यह जानकारी प्रधानमंत्री ने ही दी होगी। **राहुल गाँधी,** *कांग्रेस नेता*

आये हैं। दासगुप्ता फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि रामगढ़िया और खानचंदानी जमानत पर हैं। चैट से ज़ाहिर होता है कि दासगुप्ता ने गोस्वामी के साथ ग्रेन्यूलर डाटा भी शेयर किया था, साथ ही यह भी लिखा था कि बार्क ने इस स्तर के डाटा को किसी और के साथ शेयर नहीं किया है। इसके जवाब में गोस्वामी ने उनकी प्रशंसा की। दासगुप्ता ने रामगढ़िया को दर्शकों की संख्या पर नज़र रखने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने दो चैनलों (रिपब्लिक और टाइम्स नाउ) के बीच अन्तर करने का भी ज़िक्र किया है।

एक अन्य चैट में दासगुप्ता कहते हैं कि एनबीए को जाम कर दिया गया है और वह यह बात बहुत भरोसे के साथ बता रहे हैं। दासगुप्ता एक जगह अर्नब से कहते हैं कि आपके कुछ कहे बिना मैंने आपको सपोर्ट किया है। मैंने बाक़ी सब चैनलों, लोगों को जाम कर दिया है। मुम्बई क्राइम ब्रांच के प्रमुख मिलिंद भारंबे ने कुछ दिन पहले कहा था कि दोनों के ख़िलाफ़ सीआईयू को बार्क के सर्वर से महत्त्वपूर्ण सुबूत मिले हैं। इनसे यह साबित होता है कि इन दोनों आरोपियों ने अर्नब गोस्वामी के साथ साज़िश रची और उसी के तहत रिपब्लिक टीवी को अवैध तरीक़े से नंबर-1 बनाया गया।

चैट से साफ़ संकेत मिलते हैं कि बार्क के अधिकारी रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत के पक्ष में रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ हेरफेर कर रहे थे। यह भी पता चलता है कि बार्क के अधिकारी रिपब्लिक टीवी को रेटिंग बढ़ाने की रणनीति भी समझा रहे थे। इसके बदले में अर्नब गोस्वामी दासगुप्ता को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केबिनेट में फेरबदल और सचिवों की नियुक्तियों जैसी अहम जानकारी उन्हें दे रहे थे।

सीआईयू ने कोर्ट में बताया था कि अर्नब ने टीआरपी में हेर-फेर के लिए पार्थो दासगुप्ता को लाखों रुपये दिये थे। दासगुप्ता ने बार्क को गोपनीय डाटा को व्हाट्स ऐप और ई-मेल से अर्नब को लीक किया और बदले में अर्नब के ज़रिये केंद्र सरकार में मीडिया सलाहकार बनाने में मदद माँगी। अर्नब की इससे मोदी सरकार में पैठ ज़ाहिर होती है। यह भी रिपोर्ट्स हैं कि सीआईयू के पास अर्नब और पार्थो की मुम्बई के अलग-अलग होटलों में हुई मुलाक़ातों के भी पुख़्ता सुबूत हैं। याद रहे इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जाँच कर रहा है।

मुम्बई में अर्नब वाला मामला पहले से ही राजनीति के केंद्र में है। अब अर्नब और दासगुप्ता की व्हाट्स ऐप चैट लीक होने के बाद मुम्बई कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि साफ़ हो गया है कि टीआरपी घोटाले में भाजपा और मोदी की केंद्र सरकार का भी हाथ है। ज़ाहिर है भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर व्हाट्स ऐप चैट लीक होने के बाद रक्षात्मक होना पड़ा है। विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा टीआरपी घोटाले की जाँच को दबाने की कोशिश कर रही है। अब लीक चैट्स में यह ख़ुलासा हो गया है कि अर्नब गोस्वामी बार-बार यह ज़ाहिर करते हैं कि उनकी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सीधी पैठ है।

यही नहीं, एएस से घनिष्ठ सम्बन्ध के उनके दावे को लेकर विरोधी पार्टियों के नेता इस एएस को मोदी सरकार के एक ताक़तवर मंत्री का नाम बता रहे हैं। कांग्रेस माँग कर चुकी है कि एएस नाम का व्यक्ति कौन है? इसकी जाँच हो। यही नहीं, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के हवाले से चैट में लिखा गया है कि उन्होंने रिपब्लिक चैनल के ख़िलाफ़ मिली शिकायत को दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि भाजपा को साफ़ करना चाहिए कि रिपब्लिक चैनल के ख़िलाफ़ मिली शिकायत पर कार्रवाई न करके उसे बचाने की कोशिश क्यों की गयी? अब मुम्बई पुलिस की अन्तिम जाँच पर देश भर की नज़रें हैं।

अर्नब को फ़िलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट से 29 जनवरी तक सुरक्षा मिली हुई है। उसके बाद यदि वह इस मामले में गिरफ़्तार हुए, तो मुम्बई पुलिस उनके ख़िलाफ़ दायर होने वाले पूरक आरोप-पत्र में उनसे जुड़ी और व्हाट्स ऐप चैट्स शामिल कर सकती है। 'तहलका' ने इन चैट्स का जो अध्ययन किया है, उसके मुताबिक, अर्नब और पार्थो की 7 जनवरी, 2017 की रात 9:44 बजे की एक चैट में अर्नब कहते हैं कि हम दोनों की व्हाट्स ऐप पर चैट्स और कॉल्स कोई पढ़ और सुन नहीं सकता। यहाँ तक की व्हाट्स ऐप कम्पनी से जुड़े लोग भी। अब यही अति आत्मविश्वास उनके ख़िलाफ़ सुबूत बन गया है।

विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि भाजपा और केंद्र सरकार टीआरपी में अर्नब को बचाने की कोशिश कर रही है। यह कहा जाता है कि फ़र्ज़ी टीआरपी मामले में ईडी को केंद्र सरकार ने जानबूझकर डाला। यहाँ तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मौक़े पर मुम्बई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में ईडी के कार्यक्षेत्र को लेकर सवाल उठाये थे। दिलचस्प यह भी है कि ईडी टीआरपी मामले की जाँच मुम्बई में दर्ज एफआईआर के आधार पर नहीं कर रही, बल्कि उस एफआईआर पर कर रही है, जो बहुत गुपचप तरीक़े से लखनऊ के हज़रतगंज पुलिस स्टेशन में 17 अक्टूबर, 2020 को दर्ज हुई थी। इस एफआईआर पर अगले ही दिन मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। विपक्ष को आशंका रही है कि लखनऊ की एफआईआर पर मुम्बई क्राइम ब्रांच का टीआरपी वाला केस सीबीआई अपने पास न ले ले। वैसे महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर में एक आदेश जारी करके कहा था कि सीबीआई भविष्य में महाराष्ट्र सरकार की अनुमति के बिना किसी भी केस को सीधे अपने हाथ में नहीं ले सकती। वैसे टीआरपी मामले में सीबीआई की जाँच के स्टेटस की किसी को कोई जानकारी नहीं है; जबकि ईडी

"मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सैनिकों की बलि चढ़ायी थी। यह बात आज देश के सैनिक भी कह रहे हैं और भाजपा के पत्रकार के लीक हुए मेसेजेज ने भी यह साबित कर दिया है। भाजपा किसी की सगी नहीं है। वह अपने लाभ के लिए सैनिकों के ख़िलाफ़ षड्यंत्र करने से भी पीछे नहीं हटती। **शंकर सिंह भगेला**

पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात

"ये हैं अर्नब गोस्वामी और बार्क के सीईओ के बीच बातचीत के व्हाट्स ऐप चैट्स के कुछ स्क्रीनशॉट। इन स्क्रीनशॉट में कई षड्यंत्र देखे जा सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी की सरकार में कितनी पैठ है! यह मीडिया का बेजा इस्तेमाल है। अर्नब और मीडिया अपनी ताक़त का इस्तेमाल ब्रोकर के तौर पर कर रहे हैं। किसी भी अन्य देश में, जहाँ क़ानून का राज है; वहाँ अर्नब गोस्वामी जेल में होते। **प्रशांत भूषण**

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील

सामना

"लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने 40 जवानों की बलि चढ़ायी। यह अच्छा है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश और बिहार में तांडव के निर्माताओं और निर्देशकों के ख़िलाफ़ मामले दर्ज किये हैं; लेकिन अगर भाजपा सैनिकों की शहादत का अपमान करने के लिए अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ ऐसे मामले दर्ज करने जा रही है, तो वह एक असली आदमी है। अगर अर्नब गोस्वामी के देशद्रोह की भी चर्चा होती है, तो पुलवामा हमले के शहीदों की आत्माएँ शान्त हो जाएँगी। स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की लड़ाई दूसरों द्वारा लड़ी जाती थी; लेकिन यह राष्ट्र का चौथा स्तम्भ है! सब कुछ किया है, किसे दोष देना है? तांडव जारी है, यह जारी रहेगा। **शिवसेना**

मुखपत्र सामना में

ने जनवरी के दूसरे पखवाड़े बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि उसकी अब तक की जाँच की स्टेटस रिपोर्ट तैयार है।

बार्क और रिपब्लिक ने क्या कहा

तमाम आरोपों पर बार्क ने अभी तक यही कहा है कि मामला न्यायालय में लम्बित है और जाँच जारी है। लिहाज़ा इस बारे में कुछ नहीं कहना है। उधर रिपब्लिक टीवी नेटवर्क ने एक बयान में कहा कि उसके ख़िलाफ़ जो केस दर्ज किया गया है, वह राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया है। ये रिपब्लिक को कुचलने का कुछ चैनलों का मिलाजुला प्रयास है। हम सरकार और इस देश के लोगों से अपील करते हैं कि यह अन्याय मत होने दीजिए। तहलका

letters@tehelka.com

स्ट्राइक की सूचना लीक होना राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा : कांग्रेस

पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं– ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आज़ाद, सुशील कुमार शिंदे, सलमान ख़ुर्शीद और पवन खेड़ा ने कहा कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीओई पार्थो दासगुप्ता के बीच बालाकोट हवाई हमले को लेकर जो व्हाट्स ऐप चैट सामने आये हैं; वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गम्भीर ख़तरा हैं और इस पूरे मामले की तुरन्त जाँच होनी चाहिए। पार्टी नेताओं ने कहा कि बालाकोट हवाई हमले की जानकारी एक पत्रकार के पास पहुँचना असामान्य बात है। किसी भी सैन्य कार्रवाई की जानकारी अत्यन्त गोपनीय होती है और इसकी जानकारी सिर्फ़ पाँच लोगों प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, वायु सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पास ही होती है। इन पाँच लोगों के अलावा इस सूचना को लीक करना गम्भीर अपराध होता है। कांग्रेस ने पूछा कि बालाकोट हवाई हमले की जानकारी पत्रकार अर्नब को कैसे मिली? और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह मामला लीक कैसे हुआ? इसकी जाँच ज़रूरी है। इन नेताओं ने कहा कि इस पूरे प्रकरण को पार्टी बजट सत्र के दौरान संसद में उठायेगी और सरकार से इस मुद्दे पर जवाब देने की माँग करेगी। एंटनी ने कहा कि लीक चैट्स में जो तथ्य सामने आये हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गम्भीर ख़तरे की तरफ़ इशारा करते हैं। इन दोनों के बीच व्हाट्स ऐप पर जो बातचीत हुई है, वह बहुत दु:खद और अत्यंत गम्भीर है। यह बड़ा सवाल है कि एक पत्रकार को बालाकोट हवाई हमले की जानकारी पहले कैसे और किसने दी? यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। यह साफ़ है कि सैन्य कार्रवाई से जुड़ी यह अति गोपनीय और अति संवेदनशील सूचना किसी मंत्री या सेना के शीर्ष नेतृत्व ने दी है। यह राष्ट्र विरोधी गतिविधि है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले की व्यापक जाँच कर राष्ट्र विरोधी गतिविधि से जुड़े लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए। शिंदे ने कहा कि सरकारी गोपनीय सूचना अधिनियम महत्त्वपूर्ण क़ानून है और इसका उल्लंघन होना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। सरकार इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए इस प्रकरण में कार्रवाई करे और गुनाहगारों को सज़ा दिलाये। आज़ाद ने कहा कि यहाँ एक तरफ़ तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जिससे किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा है और दूसरी तरफ़ टीआरपी बढ़ाने के लिए साज़िश करने का मामला है, जिसमें ज़्यादा टीआरपी के माध्यम से दबदबा बढ़ाकर ज़्यादा विज्ञापन हासिल करना है। यहाँ दोनों गम्भीर अपराध हुए हैं। टीआरपी बढ़ाने की साज़िश किये जाने का मतलब है कि आप अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि आपराधिक साज़िश के माध्यम से टीआरपी में गड़बड़ी करके आगे बढ़े हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार और एक व्यक्ति के बीच साज़िश हुई है; जो कि सबसे ज़्यादा चिन्ता का विषय है। आज़ाद ने कहा कि इन दोनों स्थितियों की गम्भीरता को देखते हुए बार्क और टीआरपी प्रणाली को राष्ट्रीय सुरक्षा की क़ीमत पर जारी नहीं रखा जा सकता है। पवन खेड़ा ने कहा कि देश के साथ जो खिलवाड़ मोदी, अमित शाह और अर्नब गोस्वामी ने मिलकर किया है, उससे पूरा देश स्तब्ध है। यह आश्चर्य की बात है कि बड़े–बड़े दिखने वाले लोग कितने बौने हो जाते हैं कि वे मिलकर अपना ईमान एक पत्रकार को बेच रहे हैं।

खेती अगर घाटे का सौदा है, तो इसमें रईसों की रुचि क्यों ?

के.पी. मलिक

भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेती-किसानी में आधी से अधिक आबादी लगी हुई है; लेकिन भारत की कुल जीडीपी में इसका योगदान केवल 16 से 17 फ़ीसदी के आसपास ही रहता है। देश में एक किसान की औसत मासिक आय भी 6,000 रुपये से अधिक नहीं हो पा रही है। यह 200 रुपये रोज़ की औसत दिहाड़ी है, जो कि न्यूनतम मज़दूरी दर से भी बहुत कम है। हज़ारों किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। क़रीब 70 फ़ीसदी किसान खेती के अतिरिक्त दैनिक कमायी पर निर्भर हैं। ग्रामीण आय में खेती का हिस्सा क़रीब 40 फ़ीसदी से भी कम है। मेरा सवाल यह है कि अगर खेती-किसानी की स्थिति इतनी बुरी है, तो देश के पूँजीपति (रईस) और उद्योगपति इसकी ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं? कुछ साल पहले जब फ़िल्मी महानायक अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश के ज़िले बाराबंकी में उनकी पसंदीदा पार्टी (सपा) की सरकार में ज़मीन ख़रीदी, तो बसपा की सरकार बनते ही मायावती ने उन्हें किसान मानने से इन्कार करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की।

अमिताभ बच्चन किसान बनना चाहते हैं। बाराबंकी में उन्होंने इसके लिए ज़मीन भी ख़रीदी। सवाल यह है कि अमिताभ बच्चन, जिनकी हर महीने करोड़ों की कमायी है, किसानी क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब शायद हम सभी को कोरोना-काल में अच्छी तरह मिल चुका है। कोरोना-काल में जब दूसरे उद्योगों की तरह फ़िल्म उद्योग भी ठप पड़ गया, तब एक मात्र कृषि ही एक ऐसा उद्योग या कहें कि व्यवसाय रहा, जिसमें ताला नहीं लगा। दूसरा पूँजीपतियों और उद्योगपतियों को हर माह जो करोड़ों की आय होती है, उसको कृषि आय बताकर सरकार के आयकर विभाग की आँखों में धूल झोंकने का एक आसान रास्ता बन जाता है, क्योंकि कृषि उपज पर आयकर (इनकम टैक्स) नहीं लगता। इस मामले में अगर हम अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को दूरदर्शी कहें, तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। यह कृषि के कभी न बन्द होने की ही वजह है कि लॉकडाउन में जब पूरा देश डर से घरों में बन्द था, तब उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए संसद में तीन नये कृषि क़ानून बन गये, जिसके चलते किसान कई महीनों से आन्दोलन पर हैं और दो महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। अगर हम केवल फ़िल्मी सितारों की बात करें, तो सलमान ख़ान भी खेती करते हैं। फ़िल्म स्टार जितेंद्र ने भी राजस्थान के बूंदी में ज़मीन ख़रीदी हुई है। फ़िल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जादौन में ज़मीन ख़रीद चुके हैं। खेती-बाड़ी (कृषि) को लेकर इन सभी करोड़पतियों की एक ही राय है कि यह फ़ायदे का धन्धा है। लेकिन दूसरी तरफ़ खेती में हो रहे लगातार घाटे और सिर पर बढ़ते क़र्ज़ के चलते हर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के लाखों किसान चिन्ता में तिल-तिल घुट रहे हैं। अगर हम आँकड़े उठाकर देखें, तो पता चलता है कि कम जोत वाले किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या का रुख़ करते हैं। लेकिन उद्योगपतियों, पूँजीपतियों के कृषि की ओर रुख़ करने से बार-बार यही सवाल उठता है कि क्या कृषि घाटे का सौदा है? मेरे ख़याल से ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि फिर ये छोटे-मझोले किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? इसका सीधा-सा जवाब है कि खाद, पानी, कीटनाशक सब कुछ काफ़ी महँगा है और खाद्यान्न का वह उचित दाम किसान को कभी नहीं मिलता, जिसका वह हक़दार है, उसमें कई हिस्सेदार आ जाते हैं। यह किसान की ग़लती नहीं है, यह व्यवस्था की ग़लती है। किसान तो मजबूर है। किसान की न तो इतनी पहुँच है कि वह अपने खाद्यान्न को सीधे उपभोक्ता तक पहुँचा सके और न उसकी इतनी क्षमता है। इसकी एक वजह अधिकतर किसानों का अनपढ़ या कम पढ़ा-लिखा होना है और दूसरी वजह उन्हें उन्नत खेती करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलना है।

कहीं भुखमरी, तो कहीं अन्न की बर्बादी

वरिष्ठ पत्रकार और चिन्तक नारायण बारेठ कहते हैं कि बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में तक़रीबन 20 फ़ीसदी लोग इतना अधिक खाते हैं कि इन 20 फ़ीसदी में से क़रीब 60 फ़ीसदी को उसे पचाने के लिए जिम जाना पड़ता है। वहीं एक बड़ी आबादी ऐसी है, जिसमें से क़रीब 65 फ़ीसदी को पोष्टिक आहार नहीं मिलता और क़रीब 35 फ़ीसदी को भरपेट भोजन ही नसीब नहीं होता। अब तो कोरोना-काल में हम भुखमरी के मामले में और भी आगे निकल गये हैं। हालत यह है कि देश में 92 फ़ीसदी महिलाओं के शरीर में ख़ून की कमी है और क़रीब 40 फ़ीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। हालत यह है कि कहीं भुखमरी है और कहीं अन्न की बुरी तरह से बर्बादी हो रही है। पंजाब, हरियाणा में एक संस्था ने ऐसे ही बर्बाद खाने को इकट्ठा करके ग़रीबों का पेट भराने की एक मुहिम चला रखी है। मेरा सवाल है- क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अन्न और दूसरे खाद्य पदार्थों को बर्बाद होने से पहले ही भूखों और ग़रीबों तक पहुँचा दिया जाए। हम कितनी ही शादियों-पार्टियों में लोगों को खाना बर्बाद करते देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ़ भूख से तड़प-तड़पकर दम तोड़ने वाली दर्ज़नों ख़बरें अन्दर तक झकझोर देती हैं। यह तब है, जब हमारे यहाँ अनाज की कमी नहीं है। यह दु:खद और विडंबना भरा है कि पिछले

सात वर्षों में हम कई मामलों में पिछड़े हैं। सरकारी सेक्टर्स को निजी हाथों में दिया जा रहा है और अब चन्द उद्योगपतियों के हाथों में किसानों की डोर देने की तैयारी भी हो चुकी है।

ऐसे में क्या यह माना जाए कि कृषि को जानबूझकर अब तक मुनाफ़े से दूर रखा जा है, ताकि किसानों का इस पेशे से मोह भंग हो और वे तंग आकर अपनी ज़मीनें पूँजीपतियों और उद्योगपतियों को सौंपने को मजबूर हो जाएँ। और ऐसा हुआ भी है। हज़ारों-लाखों कृषि भूमि को कहीं पैसे का लालच देकर तो कहीं झाँसे में लेकर तो कहीं डरा-धमकाकर अब तक पूँजीपतियों और उद्योगपतियों के हवाले किया जा चुका है। शायद यही वजह है कि किसान पुत्रों को खेती से ज़्यादा मुनाफ़े का सौदा ज़मीनों को बेचकर कोई दूसरा धन्धा करना लगता है। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि इससे उनकी जड़ कट रही है। ऐसे कई उदाहरण मेरी नज़र में हैं। मसलन एक शिवचरण नाम के किसान के पास तीन बीघा ज़मीन थी, जिसमें वह सब्ज़ियाँ उगाते थे। शिवचरण अनपढ़ थे। उनका इकलौता बेटा नरेश जब बड़ा हुआ, तो अपने परिवार की माली हालत देखकर उसका खेती में मन नहीं लगा। उसने अपने पिता से कहा कि वह बिजनेस करेगा। इकलौते बच्चे की ज़िद थी और इतने पैसे घर में थे नहीं कि उसे बिजनेस कराते। आख़िरकार हार खाकर ज़मीन बेच दी और एक बड़ी दुकान लड़के को शहर में खुलवा दी। माँ-बाप गाँव में रह गये और लड़का शहर में बस गया। कुछ ही दिनों में दुकान ठप होने लगी। इधर माँ-बाप की रोजी-रोटी का ज़रिया चला गया और उधर उनका बेटा दु:खी रहने लगा। माँ-बाप की आख़िर में बुरी दशा हुई और दोनों उम्र होने से पहले ही बीमारी में चल बसे। बाद में लड़के ने गाँव वाला घर भी बेच दिया और फिर हमेशा के लिए कहीं चला गया। ऐसे कई क़िस्से हैं, जो ऐसे लोगों के हैं, जो खेती-बाड़ी का महत्त्व नहीं समझते या इसमें लगातार होते घाटे या निम्न जीवन स्तर से तंग आकर अपनी जड़ यानी खेती की ज़मीन गँवा बैठते हैं और यही पूँजीपति तथा उद्योगपति चाहते भी हैं।

कहने का मतलब यह है कि उद्योगपतियों और पूँजीपतियों के लिए वही ज़मीन फ़ायदे का सौदा हो जाती है, जिस पर एक आम किसान खेती करके जीवनयापन भी नहीं कर पाता। इसके पीछे की वजह क्या है और कहाँ कमी रह जाती है? इस पर हम सभी देशवासियों और ख़ासकर सरकार को विचार करना होगा। मुझे शहर में रहते हुए क़रीब चार दशक बीत गये और यहाँ मेरा ठीकठाक घर भी है, घर चलाने के लिए रोज़गार भी है, लेकिन मैंने अपनी एक इंच ज़मीन भी आज तक नहीं बेची।

उद्योगपतियों और पूँजीपतियों के लिए वही ज़मीन फ़ायदे का सौदा हो जाती है, जिस पर एक आम किसान खेती करके जीवनयापन भी नहीं कर पाता।

क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर न करे, अगर कोई बड़ी आपदा आ गयी, जैसे पिछले साल कोरोना वायरस का कहर टूटा, जिसका साया अब भी है; तो गाँव में कम-से-कम भूखों नहीं मरेंगे।

मुझे बड़ी पीड़ा होती है, जब किसान पुत्र कृषि कार्यों को बड़ी गिरी हुई नज़र से देखते हैं और अपने ही पुस्तैनी काम में शर्म करते हैं। कई बार ऐसे युवाओं की आँखें तब खुलती हैं, जब उनके हाथ से सब कुछ छिन चुका होता है। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे किसान पुत्रों को सोचना चाहिए कि अगर कृषि घाटे का सौदा होता, तो पूँजीपति और उद्योगपति इस क्षेत्र में उतरने के लिए इतनी ताक़त क्यों लगाते?

देश की दो तस्वीरें

जब हम ग़ौर से देखते हैं, तो हमारे देश की दो तस्वीरें साफ़ नज़र आती हैं, एक तस्वीर वो है, जिसमें एक बेटी अपने किसान-मज़दूर बाप की इस लाचारी को देखते हुए कि वह उसकी शादी कैसे और कहाँ से करेगा, आत्महत्या कर लेती है और दूसरी तस्वीर वह है, जहाँ एक उद्योगपति की बेटी अपना एक शौक़ पूरा करने के लिए करोड़ों रुपये सेकेंडों में पानी की तरह बहा देती है। दोनों ही भारत की बेटियाँ हैं; लेकिन फ़र्क़ इतना है कि एक ईमानदार किसान-मज़दूर की बेटी है और दूसरी उस उद्योगपति की बेटी है, जो दूसरों की मेहनत-मज़दूरी काटकर, टैक्स की चोरी करके, यहाँ तक कि काले धन्धे करके दिन-ब-दिन अमीर होता जाता है। एक तरफ़ 70 फ़ीसदी वह आबादी है, जिसमें परिवारों के मुखिया को पूरी ज़िन्दगी में एक घर बनाना मुश्किल हो जाता है और दूसरी तरफ़ 30 फ़ीसदी आबादी है, जिसमें परिवारों के पास हर सुख-सुविधा है। इनमें से 10 फ़ीसदी के पास तो इतनी सम्पत्ति है कि परिवार के हर सदस्य के पास यहाँ तक कि पैदा होने वाले बच्चे के पास तक इतनी सम्पत्ति होती है, कि अगर वह न भी कमाये, तो भी नौकर-चाकर रखकर ऐश-ओ-आराम की ज़िन्दगी बिता सकता है। दरअसल हमने आज़ाद भारत में करोड़पति सांसद मंत्री और विधायक पैदा किये हैं, लेकिन एक आम आदमी को मरने के लिए उसके हाल पर भी नहीं छोड़ा है। उसे कर वसूली से लेकर दूसरे तरह की अवैध वसूली का ज़रिया बनाकर गन्ने की तरह निचोड़कर फटेहाल बना डाला है। क्या यह सूरत बदलनी नहीं चाहिए? ज़रूर बदलनी चाहिए। एक पुराने सर्वे के आँकड़े बताते हैं कि देश के महज़ दो फ़ीसदी लोगों के पास बाक़ी के 98 फ़ीसदी लोगों के बराबर जितनी सम्पत्ति है।

एक और तस्वीर का ज़िक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। हमारे देश में तक़रीबन 8 से 10 फ़ीसदी सांसद ऐसे हैं, जो अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर संसद में आते हैं। सवाल यह है कि क्या यह लोग अपने क्षेत्र की चिन्ता छोड़कर दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए लालायित रहते हैं? नहीं। दरअसल कड़ुवी सच्चाई यह है कि यह लोग अपने क्षेत्र में अच्छा रिकॉर्ड नहीं होने के चलते, दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, ताकि उन्हें जीत मिल सके; क्योंकि अपने क्षेत्र में उन्हें जीत मिलने से रही। हमारी समस्या यह है कि हम धर्म, जाति को लेकर लड़ते रहते हैं, क्योंकि धर्म पर चलने के बजाय ख़ुद को धर्म का रक्षक मान बैठे हैं। यही वजह है कि आज देश में तक़रीबन 30 लाख धार्मिक स्थल होने के बावजूद अपराध बढ़ रहे हैं। अब तो धार्मिक स्थलों पर भी अपराध हो रहे हैं। देश में इसके कई उदाहरण हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश इसका गवाह बना है। अजीब बात है कि हमने 30 लाख के क़रीब धार्मिक स्थल बना लिये, लेकिन शिक्षण संस्थान तीन लाख भी नहीं बना पाये, अस्पताल एक लाख भी नहीं बना पाये। शराब के ठेके लाखों की संख्या में खोल दिये और उनकी संख्या में बढ़ोतरी ही कर रहे हैं, लेकिन उद्योगों को ख़त्म करने पर आमादा हैं। क्या हम ऐसे ही विश्वगुरु भारत का निर्माण करेंगे? आज लाखों लोग सन्त-महात्माओं की शरण में जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं; लेकिन संस्कार फिर भी घट रहे हैं। क्या वजह है इसकी? मेरे ख़याल से इसकी वजह शिक्षा में कमी और हर हाथ में काम की जगह अधिकतर हाथों में मोबाइल का आना है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर किसान पुत्र अपने बूढ़े माता-पिता को खेतों में काम करने को भेज देते हैं और ख़ुद पढ़ाई और दूसरे कामों के नाम पर मोबाइल में व्यस्त रखते हैं। फिर कहते हैं कि खेती में तो नुक़सान-ही-नुक़सान है। ऐसे युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि खेती का घाटा तो अगली फ़सल में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन आप लोग जो ज़िन्दगी का घाटा कर रहे हो, उसका आपको ताउम्र नुक़सान उठाना पड़ेगा। अपने आसपास से नहीं, तो कम-से-कम पूँजीपतियों और उद्योगपतियों के संघर्षों के बारे में पढ़कर ही सीखो, जो अरबों रुपये के मालिक होने के बावजूद दिन-रात मेहनत करते हैं। तहलका

(लेखक दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं।)

letters@tehelka.com

बजट 2021

कोविड-19 से त्रस्त अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवन देगा वैक्सीन बजट!

संजय थापा

कोविड-19 से मार खायी अर्थ-व्यवस्था के बीच अगला वित्तीय बजट पेश हो रहा है। इसमें 'वी' अर्थात् वैक्सीन का प्रभाव तो है ही, लेकिन महामारी में लगे अर्थ-व्यवस्था के झटकों के बाद अब विकास दर का ग्राफ कुछ-कुछ ऊपर की तरफ़ बढ़ता दिख रहा है। इसके साथ बजट में विशेष रूप से प्रत्यक्ष करों की बड़े करदाताओं की श्रेणी पर कोरोना सेस की उम्मीद के बीच पहली बार केंद्रीय बजट पूरी तरह से काग़ज़ रहित और एक विशेष ऐप के माध्यम से सुलभ हो रहा है।

पहली फरवरी से बजट के बाद के सत्रों में कई आत्मनिर्भर योजनाओं को पहले ही शुरू कर दिया गया है, ताकि लॉकडाउन प्रभावित क्षेत्रों पर कोरोना के प्रभाव को कम करने का लक्ष्य रखा जा सके; जैसे कि 21 लाख करोड़ रुपये के हिस्से के रूप में कोविड आत्मनिर्भर योजना के तहत मार्च में एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद घोषित की गयी।

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' प्रत्येक ग़रीब परिवार को पाँच किलो चावल, पाँच किलो गेहूँ और एक किलो दाल देने का वादा किया गया था और 2.33 करोड़ दैनिक वेतनभोगियों को मनरेगा के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन भी घोषित किया गया था। इस बजट में विशेष रूप से उच्च व्यय को आवंटित करने के साथ कृषि के लिए भी कुछ नया है। क्योंकि दिसंबर, 2020 तक बेरोज़गारी दर 10 फ़ीसदी तक बढ़ गयी थी, इसलिए इस पर चर्चा लाज़िम है। प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना और साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर अधिक ध्यान है ही। पिछले साल बजट बाद कोविड-19 पैकेज में सरकार ने प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना में 1.7 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये थे। इंफ्रास्ट्रक्चर का ख़र्च भी बढ़ेगा; क्योंकि सरकार ने 2023 तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर लिया है। राजकोषीय घाटे की चिन्ता के बावजूद बजट में खपत और रोज़गार बढ़ाने और अर्थ-व्यवस्था में अधिक लिक्विडिटी देने के लिए एक बड़ा क़दम आम आदमी पर कर का बोझ कम करना और अधिक क्रय शक्ति देने के साथ-साथ उद्योग को राहत देना भी है। स्वास्थ्य अवसंरचना व्यय को बढ़ावा मिलना ही चाहिए, ताकि पिछले साल महामारी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी की शुरू की गयी आत्मनिर्भर भारत यात्रा के दौरान एमएसएमई पर ख़र्च का लाभ मिल सके। ई-कॉमर्स और रिटेल सेक्टरों को करों में और विशेष रूप से प्रक्रियाओं में अनुकूल उपचार की उम्मीद है; क्योंकि लॉकडाउन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और डब्ल्यूएफएच सुविधा पर ज़ोर दिया।

घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) लॉकडाउन अवधि में एक बड़े विकल्प के रूप में उभरा है, जिसने लोगों को घर से काम करने की आवश्यकता पैदा की है। इसे रोज़गार या एक वैकल्पिक कार्य प्रारूप के विकल्प के रूप में माना जा सकता है और इस क्षेत्र को बजट से शायद कुछ कर प्रोत्साहन मिलेगा। रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो कोविड के दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, इस बार बजट में वित्त मंत्री से पहले ही सहानुभूति की उम्मीद किये हुए हैं। हाउसिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम पर अधिक आवंटन और ब्याज सब्वेंशन स्कीम में प्रधानमंत्री आवास योजना और सभी के लिए क़िफ़ायती आवास और किराये के आवास पर काम होगा। पिछले साल की तुलना में अधिक प्रोत्साहन और कमीशन आ रहा है, जिसमें रियल एस्टेट के लिए बजट आवंटन 25,000 करोड़ रुपये आंका गया था। ग्रामीण क्षेत्र और शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की लोगों ने काफ़ी उम्मीद कर रखी है; क्योंकि शिक्षण संस्थानों को वर्ष के बड़े हिस्से में बन्द कर दिया गया।

अब जबकि लॉकडाउन को हटा दिया गया है, फिर भी कोविड का दुष्प्रभाव असंगठित क्षेत्र पर बहुत गहरा पड़ा है, जो अभी भी कम माँग और श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन के बाद चुनौती झेल रहा है। मनरेगा पर अतिरिक्त ख़र्च के साथ-साथ असंगठित और सूक्ष्म उद्यमों के लिए पैकेज और वोकल फॉर लोकल के तहत कुटीर उद्योगों पर अधिक ज़ोर दिया जाना अपेक्षित रहा। इस बीच आरबीआई और सरकार को कोरोना प्रभावित क्षेत्र को अधिक राहत पहुँचाने के सन्दर्भ में विशेष पैकेज मिले, यह उम्मीद थी ही। प्रभावित उधारकर्ताओं ने एनपीए पर रुख़ नरम करने और साथ ही अधिस्थगन के सन्दर्भ में कहा था कि सरकार ने पहले ही एक बड़ी घोषणा की थी। राजस्व के साथ प्रत्यक्ष करों में किसी भी रियायत की घोषणा मुश्किल है। हालाँकि कुछ कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स (सीजीपी) उत्पादों की माँग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी के मोर्चे में कुछ और बदलाव किये जाने का विकल्प है। पीएलआई योजनाओं के साथ-साथ सीएपीईक्स के प्रोत्साहनों से बजट में शायद बढ़ोतरी होगी; यहाँ तक कि राजकोषीय घाटे के घटने की लागत पर भी। राजस्व संग्रह भी जीएसटी में प्रारम्भिक गिरावट के बाद उत्तरार्ध की अवधि में ठीक होना शुरू हो गया है। अर्थ-व्यवस्था में बदलाव अपेक्षित था ही, फिर भी सरकार के पास अपने राजस्व को पूरक करने के लिए बहुत कम संसाधन हैं। शेयर बाज़ार हर समय ऊँचे स्तर पर है और सरकार इस अवसर का इस्तेमाल पीएसयू शेयरों के विनिवेश के ज़रिये भुनाने में कर सकती है। इन बाधाओं के साथ भविष्य में जीडीपी में बदलाव की उम्मीद है। हालाँकि खपत की माँग को कोरोना वायरस से पूर्व के स्तर पर वापस लाने और अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अधिक समय लगेगा। वित्त वर्ष 21 के लिए राजकोषीय घाटा 7.75 फ़ीसदी को पार करने की सम्भावना है। राज्य और केंद्र का साझा वित्तीय घाटा 12.5 फ़ीसदी पार करने की आशंका है। त

letters@tehelka.com

बाइडन-हैरिस का अमेरिका

अमेरिका में जो बाइडन युग का आग़ाज़ हो गया है। दुनिया के सबसे ताक़तवर देश में इस सत्ता परिवर्तन के बाद भारत में भी दोनों देशों के सम्भावित रिश्तों को लेकर अनुमान लगाये जा रहे हैं। कमला हैरिस के रूप में भारतीय मूल की उप राष्ट्रपति बनना भारत के लिए एक सकारात्मक सन्देश है। लेकिन अमेरिकी केबिनेट में भारत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से जुड़े लोगों को न लेना बाइडन की भारत के प्रति आगे की नीतियों को काफ़ी हद तक स्पष्ट करता है। लेकिन क्या बाइडन चीन के साथ ट्रंप प्रशासन जैसा ही रुख़ रखेंगे या फिर कोई बदलाव करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। सम्भावना यही है कि चीन को रोकने के लिए बाइडन भारत के साथ साझेदारी रखेंगे। चीन के साथ भारत का सीमा तनाव अभी बना हुआ है, ऐसे में अमेरिका की भूमिका भारत के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अमेरिका भारतीयों, ख़ासकर युवाओं को लेकर क्या नीति रखता है? यह भी बहुत अहम मुद्दा है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन और भारत से जुड़ी सम्भावनाओं पर विशेष संवाददाता **राकेश रॉकी** की रिपोर्ट :-

सन् 1998 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और भारत के पोखरण में परमाणु परीक्षण से अमेरिका में नाराज़गी थी। जो बाइडन तब प्रमुख डेमोक्रेट नेताओं में शामिल थे। उस समय उन्होंने भारत का पक्ष लिया था। यही नहीं सन् 2006 में जब भारत का अमेरिका से ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ, तब भी भारत को विशेष अहमियत देने वाला ड्राफ्ट, उस समय उप राष्ट्रपति बाइडन ने ही तैयार किया था। लेकिन भारत के सबसे बड़े ग़ैर-राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की केंद्रीय सत्ता में विराजमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े लोगों को बाइडन का अपनी केबिनेट में शामिल न करना भी एक बड़ी बात है। इससे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि बाइडेन भारत के प्रति तो झुकाव रखते हैं, लेकिन वह भारत की वर्तमान राजनीति

और मुख्य राजनीतिक पार्टी से ख़ुश नहीं हैं। अब जबकि बाइडन राष्ट्रपति बन गये हैं, तब उनका यह रुख़ बहुत मायने रखता है। क्योंकि बाइडन का यह क़दम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से बेहतर निजी रिश्तों के दावों को भी पलीता है। यह भी भारत के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होगा कि चीन के साथ उनके प्रशासिक रिश्ते कैसे होंगे? बाइडन अभी तक भारत की क्षेत्रीय सम्प्रभुता की रक्षा का समर्थन करते रहे हैं। सम्भावना है कि भारत-अमेरिका के बीच रक्षा सम्बन्धों में भविष्य में और मज़बूती आयेगी।

भारत के लिए सबसे महत्त्वपूर्व अमेरिका से रक्षा सम्बन्ध हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, ट्रंप के जाने और बाइडन के सत्ता सँभालने के बावजूद दोनों देशों के रक्षा सम्बन्धों पर असर की सम्भावना लगभग न के बराबर है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच दोनों देशों में ड्रोन से लेकर ऐंटी एयर मिसाइल जैसे हथियारों की ख़रीद को लेकर बातचीत की ज़मीन तैयार हो रही है। दोनों देश पहले ही रक्षा और रणनीति क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जता चुके हैं। चुनाव के समय अमेरिका की घरेलू राजनीति ऐसी थी कि भारत, ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के बहुत क़रीब माना जाता था। हालाँकि जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी घरेलू राजनीति का दोनों देशों के सम्बन्धों पर ख़ास असर पड़ने की सम्भावना नहीं है।

हाल के महीनों में 2+2 स्तर बातचीत ने दोनों देशों के बीच सहयोग की नयी कड़ी शुरू की है। बाइडन की टीम के सदस्य कर्ट कैम्पबेल, एंथनी ब्लिंकेन, मिशेल फ्लोरनी आदि को भारत के प्रति काफ़ी सकरात्मक रुख़ रखने वाला माना जाता है। चीन से सीमा तनाव के दौरान ट्रंप के भारत के समर्थन में दिखने से चीन भी काफ़ी ख़फ़ा रहा था। देखना होगा कि बाइडन का इसे लेकर क्या रुख़ रहता है। हालाँकि जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि बाइडन प्रशासन की चीन को लेकर तल्खी ट्रंप के समय जैसी न रहे। ट्रंप की तरह बाइडन के सार्वजनिक मंचों से चीन को कोसने की सम्भावना बहुत कम दिखती है।

बाइडन प्रशासन में उप राष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, जो दोनों देशों के बीच रिश्ते निभाने में बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। इसके अलावा बाइडन की टीम में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह मिली है। इसे बहुत महत्त्वपूर्ण कहा जाएगा। वैसे बाइडन के पद ग्रहण से पहले अमेरिका के भावी रक्षा मंत्री जनरल (अवकाश प्राप्त) लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि चीन पहले ही क्षेत्रीय प्रभुत्वकारी शक्ति बन

बाइडन पिछले समय में भारत में सीएए और एनआरसी के अलावा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को ख़त्म करने और राज्य का विशेष दर्जा वापस लेने को लेकर असहज टिप्पणियाँ कर चुके हैं। डेमोक्रेट्स का एक बड़ा वर्ग शुरू से मानवाधिकार को लेकर काफ़ी गम्भीर माना जाता रहा है। यदि आने वाले समय में इस पर बाइडन प्रशासन या डेमोक्रेट्स की तरफ़ से कोई बात उठती है तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के लिए मुश्किल घड़ी हो सकती है।

चुका है और अब उसका लक्ष्य नियंत्रणकारी विश्वशक्ति बनने का है। उन्होंने क्षेत्र और दुनिया भर में चीन के डराने-धमकाने वाले व्यवहार का उल्लेख करते हुए अमेरिकी सांसदों से ये बातें कहीं। ऑस्टिन ने कहा- 'वह (चीन) पहले ही क्षेत्रीय प्रभुत्वकारी ताक़त है और मेरा मानना है कि अब उसका लक्ष्य नियंत्रणकारी विश्व शक्ति बनने का है। वह हमसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए काम कर रहा है और उसके प्रयास नाकाम करने के लिए पूरी सरकार को एक साथ मिलकर विश्वसनीय तरीक़े से काम करने की ज़रूरत होगी।' इस बयान से चीन के प्रति अमेरिका की नयी सरकार की सोच का पता लगता है।

एक मौक़े पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट माँगते हुए देखा गया। देश में इसे लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ, हालाँकि भाजपा ने इसे दोनों के दोस्त होने की दुहाई देकर उचित बताया। अब जबकि ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर हो चुके हैं, यह कहा जा सकता है कि भारत को कई क्षेत्रों में इस दोस्ती के बावजूद कोई बड़ा लाभ नहीं मिला। उदाहरण के लिए व्यापार के क्षेत्र में भारत को फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रंप को लेकर यह साफ़ हो गया था कि मोदी से दोस्ती के बावजूद उनकी प्राथमिकता अपने देश के हितों की रहती थी। बाइडन प्रशासन में इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद कम ही है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी बाइडन के साथ कैसा व्यक्तिगत रिश्ता बना पाते हैं?

यदि बाइडन के हाल के बयानों और उनकी वेबसाइट का गहराई से अध्ययन करें, तो साफ़ होता है कि वह अमेरिका में देश के बने उत्पादों के बड़े समर्थक दिखते हैं। इसमें कोई दो-राय नहीं कि बाइडन प्रशासन में डाटा प्रोटेक्शन, लोकलाइजेशन, डिजिटल सर्विस टैक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपटी राइट्स या इम्पोर्ट ड्यूटी से जुड़ी नीतियाँ, अमेरिकी व्यापार को ध्यान में रखकर बनेंगी। हाँ, बाइडन एच-1बी वीज़ा में भारतीयों की हिस्सेदारी और ग्रीनकार्ड्स आधारित रोज़गार में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में ट्रंप प्रशासन के समय तय की गयी स्टूडेंट-वीज़ा अवधि सीमित की थी, जिसे बाइडन वापस ले सकते हैं।

टकराव के मुद्दे

यदि पिछले तीन राष्ट्रपतियों बुश, ओबामा और ट्रंप के कार्यकाल को देखा जाए, तो भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है; लेकिन इनमें सुधार हुआ है। बाइडन के आने से भी भारत-अमेरिकी रिश्तों में ख़ास बदलाव नहीं आयेगा। क्योंकि कोई ऐसा बड़ा कारण सामने नहीं, जिससे लगे कि बाइडन की भारत को लेकर नीति में कोई बड़ा बदलाव आयेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो मज़बूती आयी, जो मनमोहन सिंह के दौर में और भी पक्की हुई। ट्रंप को तो मोदी अपना दोस्त कहते थे और उन्होंने ट्रंप की चुनाव के लिए मदद करने की भी कोशिश की। बाइडन के साथ मोदी के रिश्ते कैसे होते हैं, यह आने वाले समय में साफ़ हो जाएगा। हालाँकि व्यापार एक क्षेत्र है, जिसमें पहले से दोनों देशों के बीच कुछ समस्याएँ हैं। भारत में मेक इन इंडिया पर जिस तरह का मोदी सरकार का ध्यान है, उससे व्यापार में कुछ आशंकाएँ जानकार व्यक्त करते हैं। लेकिन बाइडन पिछले समय में भारत में सीएए और एनआरसी के अलावा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को ख़त्म करने और राज्य का विशेष दर्जा वापस लेने को लेकर असहज टिप्पणियाँ कर चुके हैं।

डेमोक्रेट्स का एक बड़ा वर्ग शुरू से मानवाधिकार को लेकर काफ़ी गम्भीर माना जाता रहा है। यदि आने वाले समय में इस पर बाइडन प्रशासन या डेमोक्रेट्स की तरफ़ से कोई बात उठती है तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के लिए मुश्किल घड़ी हो सकती है। अमेरिका ही नहीं, दूसरे कुछ देशों में भी सीएए और एनआरसी के अलावा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को ख़त्म करने को लेकर मोदी सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। इसके अलावा अमेरिका रक्षा क्षेत्र

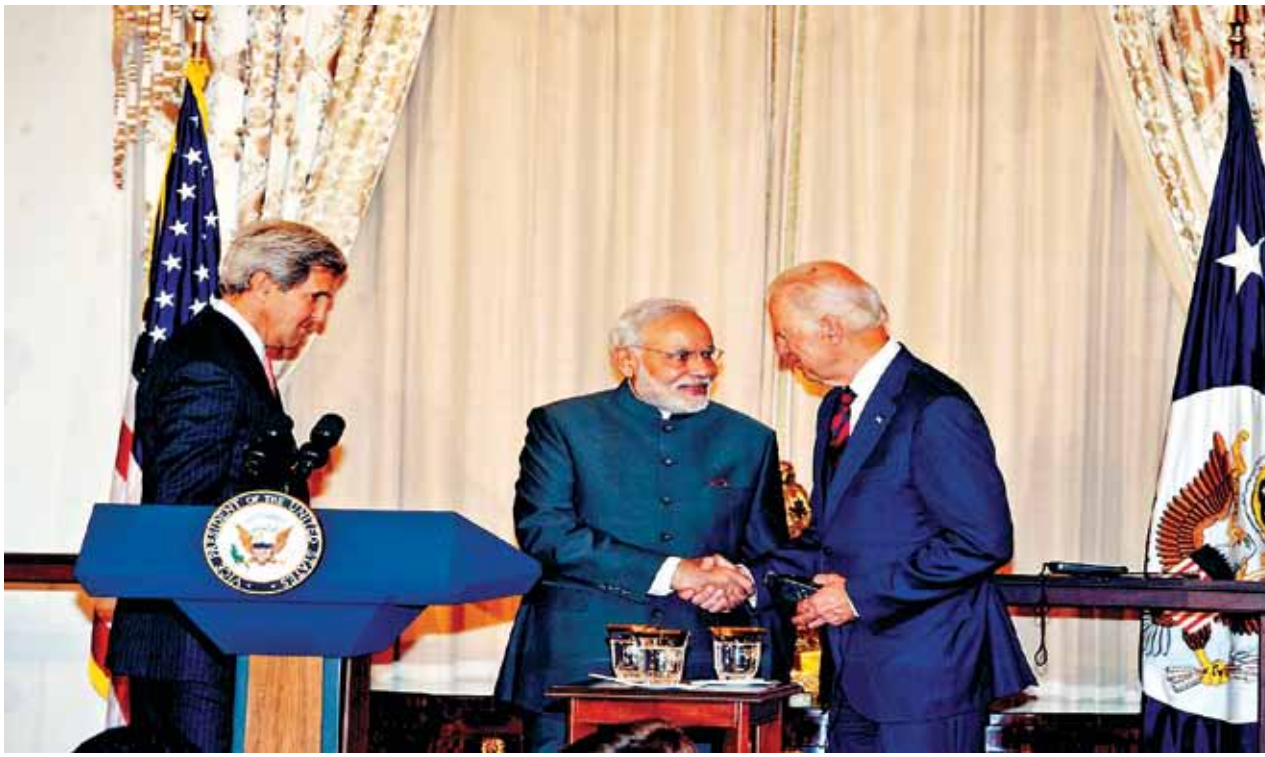

में अपने व्यापार हितों के प्रति बहुत सतर्क रहता है। मोदी से दोस्ती के बावजूद ट्रंप इस मामले में कभी समझौता करते नहीं दिखे थे। बाइडन उनसे अलग साबित होंगे, इसकी सम्भावना न के बराबर है। भारत के लिए रूस से एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीद को लेकर अमेरिका नाराज़ रहा है। यह मामले सामान्य रूप से चले तो ठीक है, मगर यदि किसी कारणवश गम्भीर रूप लेंगे, तो दोनों देशों के रिश्तों पर इसका काफ़ी विपरीत असर पड़ सकता है।

लेकिन भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की कड़ी को चीन मज़बूत करता है। चीन भारत और अमेरिका दोनों के लिए सामान रूप से चुनौती है। बाइडन भारत से अलग जाकर चीन से दो-दो हाथ नहीं कर सकते। बाइडन अपने चुनाव अभियान के दौरान चीन को लेकर सख़्त रुख़ दिखाते रहे हैं। जानकारों के मुताबिक, चीन के ख़िलाफ़ बाइडन भारत को मज़बूत साझीदार बनाना चाहेंगे।

चीन के साथ ही भारत के रिश्तों में पाकिस्तान का भी कोण है। दरअसल अमेरिका की दक्षिण एशिया क्षेत्र में कुछ मजबूरियाँ रही हैं। इन मजबूरियों में एक अफ़ग़ानिस्तान भी है, जहाँ अमेरिकी सेनाएँ अभी भी हैं। पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफ़ग़ानिस्तान के मामले में महत्त्वपूर्ण है। बाइडन भले पाकिस्तान को लेकर डबल गेम खेलने जैसी टिप्पणी कर चुके हों, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान से अपनी सेनाएँ पूरी तरह वापस करने तक वह पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे। भारत के लिए समस्या बस यही है कि पाकिस्तान, जहाँ कश्मीर को लेकर इमराम ख़ान के आने के बाद पूरी तरह भारत-विरोधी रुख़ अख़्तियार कर चुका है, वहीं वह पूरी तरह चीन की गोद में भी बैठ चुका है। ट्रंप के समय में मोदी पाकिस्तान पर कुछ मौक़ों पर दबाव डालने में सफल रहा था। क्या बाइडन ऐसी ही भूमिका भारत के लिए निभा पाएँगे? कहना कठिन है। वैसे हाल में अमेरिका के मनोनीत रक्षा मंत्री जनरल ऑस्टिन पाकिस्तान को भारत-विरोधी आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए इशारों में चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने यह तो कहा कि पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में शान्ति प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान दिया है। लेकिन पाकिस्तान यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत विरोधी आतंकवादी गुटों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ख़िलाफ़ जो क़दम उठाये हैं, वो काफ़ी नहीं हैं। ऑस्टिन ने कहा- 'मैं अपने कार्यकाल में पाकिस्तान पर दबाव डालूँगा कि वह अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादियों के शरणस्थली के रूप में न होने दे।'

हिंसा और दबाव

अमेरिका में बीते और नये साल में कुछ घटनाएँ हुईं। इनमें एक तो यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता बचाने के लिए चुनाव में जिस तरह धाँधली के आरोप लगाकर न्यायालयों और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की, उसमें वह सफल नहीं हुए। दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप की याचिकाएँ ख़ारिज कर दीं। भारत में पिछले कुछ समय में सरकार पर जिस तरह सरकारी संस्थानों को अपनी राजनीति के हिसाब से चलाने के आरोप मोदी सरकार पर लगे हैं, उसे देखते हुए सबक़ लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस तरह वाशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल हिल पर ट्रंप के समर्थक हिंसक हो गये और उन्होंने संसद में तोड़फोड़ और हिंसा की, जिससे ग़लत सन्देश गया है। पुलिस के साथ झड़प में गोली लगने से एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गयी। पुलिस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी मिले। सेना की स्पेशल यूनिट (विशेष टुकड़ी) ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। वाशिंगटन में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा।

बाइडन की आव्रजन विधेयक पेश करने की योजना है। इसमें देश में क़ानूनी दर्जे के बिना रह रहे क़रीब एक करोड़ 10 लाख लोगों को आठ साल के लिए नागरिकता देने का प्रावधान होगा। एक अनुमान के मुताबिक, इसमें क़रीब पाँच लाख लोग भारतीय मूल के हैं। यह आव्रजन विधेयक निवर्तमान ट्रंप प्रशासन की कड़ी आव्रजन नीतियों के विपरीत होगा। बाइडन ने चुनाव प्रचार के दौरान ही आव्रजन पर ट्रंप के क़दमों को अमेरिकी मूल्यों पर कठोर हमला क़रार दिया था। तब बाइडन ने कहा था कि वह इस नुक़सान की भरपाई करेंगे।

विधेयक के तहत पहली जनवरी, 2021 तक अमेरिका में किसी क़ानूनी दर्जे के बिना रह रहे लोगों की पृष्ठभूमि की जाँच किये जाने की सम्भावना है। की जाएगी और यदि वे कर जमा करते हैं और अन्य बुनियादी अनिवार्यताएँ पूरी करते हैं, तो उनके लिए पाँच साल के अस्थायी क़ानूनी दर्जे का मार्ग प्रशस्त होगा या उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद उन्हें तीन और साल के लिए नागरिकता मिल सकती है। मुस्लिम देशों से लोगों के आगमन पर रोक समेत आव्रजन सम्बन्धी ट्रंप के क़दमों को पलटने के लिए बाइडन के क़दम उठाने की सम्भावना है। बाइडन ने कहा था कि वह कांग्रेस के साथ वीज़ा प्रणाली, एच 1-बी वीज़ा में सुधार करने के लिए काम करेंगे; ताकि वीज़ा पर रहने वालों को नौकरी स्विच करने की अनुमति मिल सके। इससे भारतीय कामगारों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बाइडन ने 1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों को वैध बनाने का वादा किया गया था, उनके घोषणा पत्र के अनुसार, इनमें से पाँच लाख भारतीय हैं।

चीन का बदला

चीन डोनाल्ड ट्रंप से कितना नाराज़ था, यह इस बात से ज़ाहिर हो जाता है कि जो बाइडन के सत्ता सँभालते ही चीन ने बड़ा क़दम उठाते हुए ट्रंप के राष्ट्रपति काल में अहम पदों पर रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम माइक पोम्पियो का है। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे रॉबर्ट सी.ओ. ब्रायन पर भी चीन ने प्रतिबन्ध लगा दिया। यही नहीं चीन ने चीन-अमेरिका सम्बन्धों को ख़राब करने और चीन के अंदरूनी मामलों में दख़ल देने का आरोप लगाते हुए इन नेताओं पर प्रतिबन्धों की घोषणा की। तो क्या यह माना जाए कि चीन बाइडन से बेहतर रिश्तों की उम्मीद किये हुए हैं? क्या वह विशेष रूप से जुड़े लोगों पर प्रतिबन्ध लगाकर बाइडन के प्रति हल्का रुख़ दिखाना चाहता है?

चीन ने ट्रंप प्रशासन के इन लोगों पर प्रतिबन्ध की घोषणा करते हुए राष्ट्र की सम्प्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया। पोम्पियो और अन्य 27 अधिकारी बैन के बाद अब चीन की सीमा में किसी भी तरह की यात्रा नहीं कर सकेंगे। दिलचस्प यही है कि चीन ने यह ऐलान तब किया, जब जो बाइडन का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। चीन ने आरोप लगाया कि ये सभी लोग चीन-अमेरिका के रिश्तों को ख़राब करने के ज़िम्मेदार थे। सूची में पोम्पियो के अलावा रॉबर्ट सी. ओब्रायन, पीटर नेवारो, डेविड स्टिलवेल, मैथ्यू पॉटिंगर, एलेक्स अजर, कीथ क्रैच, केली डीके क्राफ्ट, जॉन आर. बोल्टन, स्टीफन जैसे नाम शामिल हैं। अब इन सभी के साथ ही इनके परिवार के सदस्य भी चीन की मुख्य भूमि के अलावा हॉन्गकॉन्ग, मकाऊ में भी प्रतिबन्धित कर दिये गये हैं और वे चीन या चीन की किसी भी कम्पनी के साथ व्यापार भी नहीं कर पाएँगे। भले चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में भी चीन के कई अधिकारियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था; जिनमें शिनजियाँग प्रान्त के गवर्नर जैसे लोग नाम शामिल थे। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने निवर्तमान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को महाविनाश का पुतला क़रार दिया और कहा कि उनके द्वारा चीन को नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी क़रार दिया जाना केवल रद्दी का एक पुर्ज़ा भर है। बता दें कि चीन के वुहान में कोरोना विषाणु की उत्पति के आरोप अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने लगाये थे। अमेरिका में तो इसे लेकर एक मामला भी दर्ज किया गया था। अभी चीन ने बाइडन को लेकर खुले तौर पर कुछ नहीं कहा है। उनके सत्ता सँभालने को लेकर भी कोई अहम प्रतिक्रिया चीन की तरफ़ से नहीं आयी है। बाइडन ने भी शपथ ग्रहण के बाद ख़ुद अपने भाषण में चीन को लेकर कोई बड़ी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की थी। हालाँकि इसके बावजूद यह तय है कि चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते कोई मित्रता वाले तो नहीं ही होंगे।

यह माना जा रहा था कि बाइडन शुरुआत में चीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने चीन से जुड़ा कोई भी बड़ा बयान नहीं किया। वैसे अपने प्रति बाइडन के नज़रिये से चीन भी सतर्क है। विशेषज्ञ बताते हैं कि दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में ख़ास बदलाव नहीं आयेगा। अमेरिका में नया राष्ट्रपति बनने के बाद चीन मान रहा है कि अमेरिका कई मुद्दों को लेकर कड़ा रुख़ रखेगा। हालाँकि चीन के

न्यूक्लियर फ़ुटबॉल की पॉवर

अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि कोई निवर्तमान राष्ट्रपति नये राष्ट्रपति को न्यूक्लियर फुटबॉल और कोड दिये बिना व्हाइट हाउस छोड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस छोड़ा, तो उन्होंने जो बाइडन को यह दोनों चीज़ें नहीं दीं। न्यूक्लियर लॉन्च कोड एक कार्ड पर लिखे होते हैं, जिसे बिस्किट भी कहते हैं। ये न्यूक्लियर बटन जैसी कोई चीज़ नहीं है। दरअसल अमेरिका में पुराने राष्ट्रपति के पद छोड़ने और नये राष्ट्रपति के शपथ लेने के साथ न्यूक्लियर पॉवर का भी ट्रांसफर होता है। दुनिया या दुश्मन को तबाह करने की ताक़त नये राष्ट्रपति के पास आ जाती है। यह न्यूक्लियर पॉवर एक काले रंग के ब्रीफकेस में बन्द होती है। इसी को न्यूक्लियर फुटबॉल भी कहते हैं। राष्ट्रपति के पास दो न्यूक्लियर फुटबॉल और उसमें दो सेट न्यूक्लियर लॉन्च कोड रखे होते हैं। न्यूक्लियर कोड एक कार्ड पर लिखे होते हैं, जिसे न्यूक्लियर बिस्किट भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें अमेरिकी राष्ट्रपति के पास हर वक़्त रहती हैं। फुटबॉल में परमाणु हमले के लिए कोड होते हैं, इसके ज़रिये ही अमेरिकी राष्ट्रपति पेंटागन को न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। ये न्यूक्लियर कोड कभी भी राष्ट्रपति से अलग नहीं होता है, जब अमेरिका में नये राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो उस दौरान ही ब्रीफकेस भी एक से दूसरे के पास चला जाता है। लेकिन ट्रंप बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, लिहाज़ा नये राष्ट्रपति को न्यूक्लियर लॉन्च कोड ट्रांसफर नहीं किया और उनके साथ न्यूक्लियर फुटबॉल भी फ्लोरिडा चला गया। हालाँकि इसमें रखे न्यूक्लियर लॉन्च कोड दोपहर 12 बजे और बाइडेन के शपथ लेने के साथ ही डेड हो गये। इसके बाद बाइडन के लिए वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल से न्यूक्लियर फुटबॉल और न्यूक्लियर लॉन्च कोड का दूसरा सेट आया, जिसे अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को ट्रांसफर किया।

कहानी कमला हैरिस की

भारतीय मूल की कमला हैरिस के अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत उप राष्ट्रपति बनने से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को बेहतर करने को लेकर भारत में उन्हें बड़ी उम्मीद से देखा जा रहा है। बता दें डेमोक्रेट्स में कमला को 'फीमेल ओबामा' के नाम से भी पुकारा जाता है और हैरानी की बात यह है कि वह सीनेट की सदस्य भी पहली बार ही बनी हैं। नवम्बर के चुनाव में अपनी जीत के बाद हैरिस ने अपने सम्बोधन में भारत की अपनी पृष्ठभूमि के बारे में गर्व से बताया था। अपनी दिवंगत माँ श्यामला गोपालन, जो एक कैंसर शोधकर्ता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थीं; को याद करके कमला भावुक हुई थीं और कहा था कि माँ ने उनके राजनीतिक करियर में इस बड़े दिन के लिए उन्हें तैयार किया था। हैरिस 56 साल की हैं और उन्हें बेहिचक उपलब्धियों की खान कहा जा सकता है। वह सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला, पहली भारतवंशी और पहली अफ्रीकी अमेरिकी हैं। राष्ट्रपति बाइडन ने ही उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उप राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना था। दिलचस्प यह है कि एक ऐसा भी समय था, जब कमला हैरिस अपने प्रतिद्वंद्वी रहे बाइडन की कटु आलोचक थीं। हैरिस सीनेट के तीन एशियाई अमेरिकी सदस्यों में से एक हैं। कमला का जन्म 20 अक्टूबर, 1964 को हुआ। माँ श्यामला गोपालन सन् 1960 में भारत के तमिलनाडु से यूसी बर्कले पहुँची थीं, जबकि उनके पिता डोनाल्ड जे. हैरिस सन् 1961 में ब्रिटिश जमैका से इकोनॉमिक्स में स्नातक की पढ़ाई करने यूसी बर्कले आये थे। यहीं अध्ययन के दौरान दोनों की मुलाक़ात हुई और मानव अधिकार आन्दोलनों में भाग लेने के दौरान उन्होंने विवाह करने का फ़ैसला कर लिया। हाई स्कूल के बाद हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली कमला जब सात साल की थीं, तो उनके माता-पिता एक-दूसरे से अलग हो गये। कमला और उनकी छोटी बहन माया अपनी माँ के साथ रहीं और उन दोनों के जीवन पर माँ का बहुत प्रभाव रहा। हालाँकि वह दौर अश्वेत लोगों के लिए सहज नहीं था। कमला और माया की परवरिश के दौरान उनकी माँ ने दोनों को अपनी पृष्ठभूमि से जोड़े रखा और उन्हें अपनी साझा विरासत पर गर्व करना सिखाया। वह भारतीय संस्कृति से गहरे से जुड़ी रहीं। हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद हैरिस ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से क़ानून की पढ़ाई की और सन् 2003 में वह सैन फ्रांसिस्को की शीर्ष अभियोजक बनीं। सन् 2010 में वह कैलिफोर्निया की अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला और पहली अश्वेत व्यक्ति थीं; जबकि सन् 2017 में हैरिस कैलिफोर्निया से जूनियर अमेरिकी सीनेटर चुनी गयीं। कमला ने सन् 2014 में जब अपने साथी वकील डगलस एम्पहॉफ से विवाह किया, तो वह भारतीय-अफ्रीकी और अमेरिकी परम्परा के साथ-साथ यहूदी परम्परा से भी जुड़ गयीं। अब वह अमेरिका की उप राष्ट्रपति हैं और भारत को उन पर गर्व है।

अख़बार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नये प्रशासन के बाद चीन और अमेरिका के बीच कुछ व्यापारिक मसले हल हो सकते हैं। बाइडन टीम के सदस्य जेनेट येलेन कह चुके हैं कि अमेरिका में नया प्रशासन चीन की अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था को कमज़ोर करने वाले तरीकों के ख़िलाफ़ दूसरे विकल्पों का भी उपयोग करेगा। येलेन, ट्रेजरी सेक्रेटरी चुने गये हैं और उनका साफ़ मानना है कि चीन की वजह से अमेरिकी कम्पनियों की क़ीमतें गिर रही हैं।

बाइडन का भाषण

शपथ लेने के बाद अपने पहले सम्बोधन में देश के अब तक के सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति बाइडन ने घरेलू आतंकवाद और श्वेतों को श्रेष्ठ मानने वाली मानसिकता को हराने की लड़ाई में अमेरिका के सभी नागरिकों से शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि आज हम एक उम्मीदवार की जीत का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मक़सद और लोकतंत्र की जीत का जश्न मना रहे हैं। देश के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 78 वर्षीय बाइडन ने न सिर्फ़ अपने वैश्विक सहयोगियों के साथ सम्बन्धों को दुरुस्त करने का वादा किया, बल्कि देश के लोगों से सच की रक्षा करने और झूठ को हराने का भी आह्वान किया।

नवंबर में घोषित चुनाव परिणाम में बाइडन की जीत को अस्वीकार करने के ट्रंप के प्रयासों का परोक्ष सन्दर्भ देते हुए उन्होंने कहा- 'आज अमेरिका का दिन है। लोकतंत्र की जीत हुई है।' कोरोना वायरस संक्रमण और नस्लीय अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई जैसी चुनौतियों का सन्दर्भ देते हुए बाइडन ने कहा- 'एकजुट होकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। महामारी को हराने, हालात सुधारने, देश को एकजुट करने के लिए एकजुटता ही आगे का रास्ता है।' बाइडन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह सभी अमेरिकी नागरिकों के राष्ट्रपति हैं, उन्हें वोट देने वालों के भी और नहीं देने वालों के भी। अपने 21 मिनट लम्बे भाषण में बाइडन ने चुनौती स्वीकार करने और लोकतंत्र बहाल करने के लिए अमेरिकी नागरिकों की प्रशंसा की। उन्होंने क्रोध और विभाजन को शह देने वालों की आलोचना की और उनका विरोध करने वालों से कहा - 'एक बार मेरी बात सुनें। सच और झूठ सब सामने आते हैं।'

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपने सन्देश में बाइडन ने अमेरिका के साझेदारों के साथ सम्बन्धों को दुरुस्त करने और दुनिया के साथ एक बार फिर साझेदारी बढ़ाने का वादा किया। अनुभवी नेता ने अपने भाषण में कहा- 'हम शान्ति, प्रगति और सुरक्षा के क्षेत्र में मज़बूत और विश्वस्त साझेदारी होंगे। अमेरिका ने परीक्षा दी है और मज़बूत होकर उभरा है। हम अपने साझेदारों के साथ सम्बन्धों को दुरुस्त करेंगे और एक बार फिर दुनिया के साथ अपना मेल-जोल बढ़ाएँगे।' बाइडन ने कहा कि हम सिर्फ़ अपनी शक्ति के आधार पर नेतृत्व नहीं करेंगे, बल्कि उदाहरण पेश करेंगे और उसके आधार पर आगे चलेंगे। हम शान्ति, प्रगति और सुरक्षा के लिए मज़बूत और विश्वस्त साझेदार साबित होंगे। जो बाइडन ने कहा कि देश की सीमाओं के बाहर के लिए उनका सन्देश है कि हम अपने सहयोगियों के साथ रिश्ते फिर सुधारेंगे और दोबारा दुनिया के साथ कूटनीतिक सम्पर्क बहाल करेंगे, तो एक नयी उम्मीद विश्व शान्ति के लिए दिखती है।

ट्रंप बनाएँगे अपनी पार्टी !

डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस छोड़कर फ्लोरिडा जा रहे थे, तब एयरपोर्ट पर अपने समर्थकों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण बात कही– 'आप जल्दी ही हमें किसी और रूप में देखेंगे।' इससे एक तो यह संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति के अगले चुनाव के लिए ट्रंप हार की धूल झाड़कर जल्दी ही फिर सक्रिय होने की तैयारी में हैं। वास्तव में ट्रंप के यह कहने के क्या मायने थे? इसे लेकर अमेरिकी मीडिया में कुछ समय से छप रही रिपोर्ट्स को भी देखना होगा। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जिस तरह ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग की कार्यवाही हुई है और कैपिटल हिल में उनके समर्थकों ने जो किया, उससे रिपब्लिकन पार्टी में उन्हें अगली बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाये जाने का विरोध हो सकता है। ऐसे में दोबारा राष्ट्रपति बनने की जबरदस्त ख़्वाहिश पाले ट्रंप अपनी ही पार्टी भी बना सकते हैं।

अमेरिकी मीडिया में तो इस नयी पार्टी का नाम तक बता दिया गया है। इसका नाम 'पैट्रियाट पार्टी' हो सकता है। ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में समर्थकों से कहा था कि जिस आन्दोलन को हमने शुरू किया है, यह केवल शुरुआत है। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका में अटकलों का बाज़ार गरम है। उधर वॉल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप नयी पार्टी बनाने को लेकर समर्थकों से विचार-विमर्श कर चुके हैं। देखना होगा ट्रंप इसे लेकर कितनी गम्भीरता दिखाते हैं। ट्रंप यह तो कह ही चुके हैं कि वह राजनीति में बने रहेंगे और उनका आन्दोलन एक शुरुआत भर है। यहाँ यह बताना दिलचस्प है कि तमाम परम्पराओं को तोड़ते हुए ट्रंप बाइडन के शपथ ग्रहण के समय व्हाइट हाउस छोड़ चुके थे। रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप की घोषणाओं और उनके क़दमों-बयानों से बेचैनी महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, रिपब्लिकन पार्टी एक बहुत बड़ा धड़ा ट्रंप के साथ है और उनके उग्र राष्ट्रवाद के एजेंडे से सहमत है। जबकि दूसरा धड़ा इसे अलगाववादी एजेंडा मानता है। कैपिटल हिल में हिंसा के बाद रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिट मैकॉनल ने ट्रंप पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही अपने समर्थकों को उकसाया। भीड़ के दिमाग़ में झूठ भरा। यहाँ यह बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव पर जब निचले सदन में मतदान हुआ था, तो ट्रंप की ही पार्टी रिपब्लिकन के 10 सांसदों ने ट्रंप के ख़िलाफ़ मतदान किया था। फ़िलहाल रिपब्लिकन पार्टी में मिट मैकॉनल अपनी स्थिति मज़बूत करने में जुटे हैं, जो ट्रंप के बाद पार्टी में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नेता हैं।

कई फ़ैसले पलटे

अमेरिका की सत्ता हाथ में आते ही बाइडन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेरिस जलवायु समझौते और अमेरिका में मुस्लिम ट्रैवल बैन को ख़त्म करने जैसे फ़ैसले पलट दिये। नये राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में अमेरिका की फिर से वापसी के लिए उस पर हस्ताक्षर कर दिये।

बाइडन ने पेरिस जलवायु समझौते में दोबारा शामिल होने का ऐलान करते हुए कहा कि देश की जनता से चुनाव के दौरान उन्होंने इसका वादा किया था। इसके अलावा बाइडन ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग तेज़ करने के इरादे से महामारी कोरोना वायरस को रोकने के एक फ़ैसले पर दस्तख़त किये। इस आदेश के मुताबिक, उन्होंने मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया है। बाइडन ने अमेरिका में ट्रंप द्वारा कुछ मुस्लिम देशों और अफ्रीकी देशों के आवागमन पर रोक लगाने जैसे फ़ैसलों को पलटते हुए इस प्रतिबन्ध ख़त्म कर दिया है। बाइडेन ने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के ट्रंप के फ़ैसले को भी पलट दिया और इसके लिए फंडिंग भी रोक दी। इस फ़ैसले के बाद मैक्सिको ने जो बाइडेन की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के तुरन्त बाद कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन के विस्तार पर भी रोक लगाने के आदेश पर दस्तख़त किये हैं।

कीस्टोन एक तेल पाइपलाइन है, जो कच्चे तेल को अल्बर्टा के कनाडाई प्रान्त से अमेरिकी राज्यों इलिनोइस, ओक्लाहोमा और टेक्सास तक ले जाती है। बाइडन ने कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन के ख़िलाफ़ बात की थी और यहा कहा था– 'टार सैंड्स की हमें ज़रूरत नहीं है।'

बाइडन के राष्ट्रपति अभियान का एक प्रमुख वादा कीस्टोन एक्सएल परियोजना को रद्द करने की प्रतिबद्धता थी। भविष्य में बाइडन पूर्व सरकार की ओर से शुरू की गयी कई परियोजनाओं से हाथ खींच सकते हैं। जैसे, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्तपोषण के माध्यम से अर्जेंटीना में फ्रैकिंग और तेल-गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जो पिछली बार वाका मुएर्ता परियोजनाओं के लिए हुआ। निर्वाचित उप राष्ट्रपति कमला हैरिस सहित कई अमेरिकी सीनेटरों ने इसके ख़िलाफ़ एक याचिका पर हस्ताक्षर किये थे। बाइडन ने कहा था कि वह वनों की कटाई के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को जवाबदेह ठहराएँगे। अन्य देशों के साथ रैली करने और ॲमेजन की सुरक्षा के लिए 20 अरब डॉलर (क़रीब 1500 अरब रुपये) का समर्थन देने से शायद यह हासिल किया जा सकता है। हालाँकि स्थानीय ब्राजीलियाई समूह इस बात पर ज़ोर डालते हैं कि यह इस तरह से किया जाना चाहिए, जो ब्राजील की अमेजन के अपने हिस्से पर सम्प्रभुता को स्वीकार करता है और उसका सम्मान करता है।

letters@tehelka.com

सूखा ग्रस्त गाँव में जल संचय से ग्रामीणों ने बदल दी तस्वीर

- बुंदेलखण्ड के जखनी गाँव में उमाशंकर पांडे ने ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक काम करके बदल दी गाँव की तस्वीर
- उच्च शिक्षा प्राप्त युवा कर रहे हैं खेती, सम्पन्न हुए लोग, भारत सरकार ने जखनी को दी जलग्राम की मान्यता

मंजू मिश्रा

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था- 'तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होने की सम्भावना है। पर हम प्रयास करें कि वह भारत में न हो।' अनेक विद्वान भी पानी को लेकर तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर चुके हैं। इसलिए बेवजह अनाप-शनाप पानी बहाने वाले लोगों को यह ज़रूर समझना और जानना चाहिए कि यह भविष्यवाणी लोगों ने यूँ ही अकारण नहीं कर दी, बल्कि इसके पीछे वो आँकड़े हैं; जो न केवल हमें चौंकाते हैं, बल्कि चिन्ता में भी डालते हैं। हममें से अधिकतर लोग नहीं जानते कि नदियों को हमारे पूर्वज कितने तप से धरा पर लाये और उन्हें कितनी कुर्बानियाँ देकर भी ज़िन्दा रखा, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत-से नुक़सान उठाये। हमारी संस्कृति में नदियाँ, तालाब, कुएँ, बावड़ियाँ और जल श्रोत पूजनीय, जन-समाज की आस्था का केंद्र थे और इसीलिए इन्हें जीवंत रखने में सभी की सहभागिता थी। लेकिन ओछे ज्ञान, जीने की अकड़, जागरूकता के अभाव, अन्धी-आस्था, आधुनिकता की होड़ और सरकारों की उदासीनता के कारण आज हमारा जनमानस जल-श्रोतों से दूर है; इनके प्रति उदासीन है और उन्हें प्रदूषित कर रहा है। जीवनदायी जल को व्यर्थ में बहाता लापरवाह मनुष्य पीने वाले जल की समाप्ति की भयावहता से अनभिज्ञ है। हमारे ही देश में अब भी सैकड़ों ऐसे गाँव हैं, जहाँ पानी की बूँद-बूँद की क़ीमत वहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कुल मिलाकर अगर हम सब आज जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हुए, तो निश्चित ही आने वाले समय में मनुष्य जाति बूँद-बूँद पानी के लिए तरसेगी, आपस में लड़ेगी-मरेगी।

सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति के अनेक ग्रन्थों में जल की विभीषिका का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर की अनेक घटनाएँ तो प्रमाण ही हैं; परन्तु वर्तमान कलियुग में प्रत्यक्ष सुनने और देखने के बाद प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर के अलावा भारत के अनेक इलाक़ों में हर साल पीने योग्य पानी के बिना अकाल-दुर्भिक्ष से तो लोग अभिशप्त हैं और मौत के डर से अपनी जन्मभूमि से पलायन करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। दुनिया के कई देश पानी की कमी से जूझ रहे हैं और कई शहर ख़ाली हो रहे हैं। जल के बिना सामाजिक और आर्थिक ताना-बाना भी तब टूटता नज़र आ रहा है। जल ही जीवन है। जल में अमृत है, ऊर्जा है, सिद्धि है, गति है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वायु को शुद्ध करने की क्षमता है। मानवता के हित में नि:शुल्क पानी पिलाने वाले भारत में नदियाँ बेचना, जल का बाज़ारीकरण समस्या का समाधान नहीं है। बोतल बन्द पानी 15 रुपये से 150 रुपये लीटर तक बिक रहा है। आने वाले समय में इसका कारोबार 160 बिलियन को छू जाने वाला है। ग़रीब पानी कहाँ से पीयेगा, किसान कहाँ से खेत को पानी देगा? ये बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं। बाँधों में नदियों को बाँधकर जल को अपने अधीन करने का कार्य हो रहा है, तो किसान को खेती के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? भू-जल कहाँ से रिचार्ज होगा और कृषि प्रधान भारत का किसान पानी के बिना खेत छोड़ देगा, गाँव छोड़ देगा या फिर पानी को गहरे बोर करके प्राप्त करेगा, जिससे खेती-किसानी महँगी तो होगी ही, साथ ही लगातार गिरता भू-जल का स्तर निरंतर और गिरता चला जाएगा। इससे बोर का ख़र्च और बढ़ेगा, जो कि लम्बे समय तक

चल भी नहीं पाएगा। यही नहीं, कम भूमि का छोटा किसान पानी की कमी और महँगी, ख़र्चीली खेती के कारण स्वत: ही समाप्त हो जाएगा और अन्न देने वाला ख़ुद ही दाने-दाने का मोहताज हो जाएगा।

विकट जलस्रोत, लेकिन लोग प्यासे

वर्तमान में मध्य भारत का सूखाग्रस्त बुंदेलखण्ड ऐसा क्षेत्र है, जहाँ सूखे के दौरान सरकारों ने मालगाड़ी के ज़रिये पीने का पानी भिजवाया। यह ऐसा स्थान जहाँ, जल संसाधनों की प्रचुरता है और कभी यहाँ पानी की मात्रा प्रचुर थी। क़रीब 35 छोटी-बड़ी नदियाँ यहाँ हैं, जिनमें पाँच बड़ी और 30 प्रदेश स्तर की हैं। इतना ही नहीं, यहाँ क़रीब 125 छोटे-बड़े बाँध हैं, 27,000 तालाब हैं, 52,000 कुएँ, 300 नाले, 150 बावड़ियाँ और चंदेल, बुंदेल राजाओं द्वारा स्थापित लगभग 51 परम्परागत और प्राकृतिक जल संसाधन और अनुसंधान केंद्र हैं। एशिया की सबसे बड़ी ग्रामीण पेयजल योजना पाठा चित्रकूट बुंदेलखण्ड में ही है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जल की तमाम योजनाओं में अरबों रुपये ख़र्च करने के बावजूद भी बुंदेलखण्ड आज प्यासा क्यों है? आख़िर यहाँ मालगाड़ी से पानी भेजने की नौबत क्यों आयी? क्या कारण रहा है कि सरकारों के अनेक प्रयासों के बावजूद भी समस्या ज्यों-की-त्यों बनी रही। सरकारों ने अपना काम किया, लेकिन जिनके लिए काम किया, उस समाज ने उन कामों के प्रति क्या ज़िम्मेदारी दिखायी? भू-जल संरक्षण करना सरकार का नहीं, समाज का काम है। लेकिन सरकार के कार्यों में उन्होंने क्या सहयोग किया? क्या केवल भोगी बनकर उपभोग किया और उपलब्ध कराये गये संसाधनों का दोहन करके सरकारों के भरोसे छोड़ दिया? सवाल यह है कि हम दिये गये संसाधनों से समस्या का स्थायी समाधान निकालकर गाँव, शहर प्रदेश और देश की उन्नति में सहायक बने अथवा नहीं? शायद नहीं। वहीं सरकारों ने भी इस बारे में बेहतर तरीक़े से नहीं सोचा। क्योंकि यदि ऐसा पुरानी सरकारें सोचतीं, तो सरकार को बुंदेलखण्ड में पीने का पानी मालगाड़ी से नहीं भेजना पड़ता। पानीदार बुंदेलखण्ड फिर से पानी के लिए आत्मनिर्भर होता, स्वावलंबी होता। इन तमाम घटनाओं के बावजूद इनका उपाय अँधेरा-अँधेरा कह देने की बजाय एक छोटा-सा दीपक लेकर उजाला करने में छुपा है।

उमाशंकर ने कर दिखाया कमाल

दृढ़ संकल्पित उमाशंकर पांडे के नेतृत्व में

बुंदेलखण्ड के बांदा ज़िले के जखनी गाँव के लोगों ने अपना भरोसा जगाया। अपनी परम्परागत खेती-किसानी का सहारा लिया और बिना किसी सरकारी सहायता, संसाधन के गाँव के बच्चे, बुजुर्ग, जवान स्त्री-पुरुष सभी ने गाँव के जल देव को जगाया। इन लोगों ने अपने गाँव के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सामुदायिक आधार पर फावड़े, कस्सी, डलिया, टोकरा लेकर परम्परागत तरीके से बिना किसी आधुनिक मशीनी-तकनीकी के पानी रोकने का बंदोबस्त किया। सब समझ चुके थे कि पानी बनाया नहीं जा सकता, न ही बादलों को लाकर अपनी इच्छा से बरसाया जा सकता है, लेकिन प्रकृति द्वारा दिए पानी को रोककर पानी की फ़सल को बोया जा सकता है, संरक्षण से पानी बचाया जा सकता है।

उमाशंकर पांडे

किस तरह किया काम

उमाशंकर ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पूरे गाँव ने खेतों की मेड़बन्दी की और पानी की फ़सल बोने का पुरखों का मन्त्र सिद्ध किया।

मेडबन्दी के बाद अब बारी थी कि जल की निरंतर प्राप्ति के लिए पानी की फ़सल कैसे बोयी जाए, कैसे पानी की खेती की जाए। जिसके लिए उमाशंकर ने समुदाय के साथ गाँव के पानी का मैनेजमेंट किया, गाँव के तालाबों को पुनर्जीवित करवाया राज समाज सरकार को साथ लिया और खेतों की मेड़ से निकलने वाले अतिरिक्त पानी और गाँव के बचे पानी का रुख़ तालाबों की ओर मोड़ दिया। यानी खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी, गाँव में...। ग़ज़ब की सोच! पहली बारिश होते ही वर्षा की बूँदें जहाँ गिरीं, वही उन्हें रोककर संचित किया। ऊँची मेड़ों के कारण ज़मीन ने जी भरकर पानी पीया। खेतों का पेट भरने के बाद बाहर निकलते पानी ने तालाबों का रुख़ किया। तालाब पानी से भरने लगे। गाँव के सभी छः-के-छः तालाब पानी से लबालब भर गये। यही नहीं, तालाबों के भरने से गाँव के 30 कुएँ भी अपना यौवन दिखाने लगे और कुओं का जलस्तर भी 15 से 20 फीट पर पहुँच गया।

मेड़-मेड़ पर पेड़

गाँव वालों का हौसला बढ़ा, तो काम यहीं नहीं रुका। उन्होंने मेड़-मेड़ पर पोधरोपड़ का काम शुरू कर दिया। लहलहाती फ़सलों के बीच धीरे-धीरे पेड़ झूमने लगे। मानों कह रहे हों कि अब बादलों से पानी लाने का काम हमारा और उसे रोकने का काम तुम्हारा।

संघर्ष की लम्बी दास्ताँ

इस गाँव को ख़ुशहाल बनाने के लिए उमाशंकर पांडे को पूरे गाँव के साथ लम्बा संघर्ष करना पड़ा। और आख़िरकार सूखे बुंदेलखण्ड में लगातार 21 वर्षों की मेहनत रंग लायी। इस जखनी गाँव में कभी खेती नहीं हो पाती थी; लेकिन आज इस गाँव में रिकॉर्ड फ़सल उत्पादन होता है। पिछले वर्ष ही जखनी के किसानों ने 21,000 कुंतल बासमती धान और 13,000 कुंतल गेहूँ का उत्पादन किया।

इस तरह गेहूँ, धान, चना, तिलहन, दलहन के साथ-साथ सब्ज़ी, दूध और मछली पालन से जखनी के किसान अब समृद्ध और साधन-सम्पन्न होने लगे हैं। यहाँ तक कि चार बीघे के छोटे-से-छोटे किसान के पास भी आज अपना ट्रैक्टर है, वह भी बिना किसी क़र्ज़ के।

खेती से जुड़ गये उच्च डिग्रीधारी युवा

20 साल पहले जखनी गाँव बांदा ज़िले का सबसे ग़रीब गाँव था। यहाँ का एक भी नौजवान

गाँव में नहीं था। वर्तमान में 99 फ़ीसदी नौजवान, जो कभी पलायन कर गये थे; वापस आ गये हैं और अपनी परम्परागत खेती करने लगे हैं। इन किसानों में अधिकांश युवा हैं। कोई एम.काम., कोई एम.एससी., कोई पी.एचडी. कोई वी.टेक., कोई एम.एड, कोई बी.एड, तो कोई एल.एल.बी. है। उच्च शिक्षा की डिग्री लेकर शहरों की नौकरी छोड़कर गाँव में खेती कर रहे हैं। आज जखनी गाँव प्रदेश का सबसे सम्पन्न गाँव माना जाता है।

मंडियों में जखनी के खाद्यान्न की बढ़ी माँग

सामुदायिक आधार पर चला यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, गल्ला मंडियों में जखनी के किसानों के धान को अधिक मूल्य और सम्मान मिला, तो सब्ज़ी मंडी में भिंडी, बेंगन, प्याज, टमाटर की सर्वाधिक माँग होने लगी। इससे प्रभावित होकर आसपास के लगभग 50 गाँवों के सैकड़ों किसानों ने भी जखनी की तरह खेती करने का संकल्प लिया और उन्होंने हज़ारों बीघा ज़मीन की अपने संसाधनों से मेड़बन्दी कर दी और यहीं से जलग्राम जखनी की जलक्रान्ति सूखे बुंदेलखण्ड में फैलने लगी। गाँव से पलायन कर गये नौजवान अपने खेतों में बिना मज़दूरों के स्वयं काम करने लगे। तालाबों में मछली पालन, दुग्ध उत्पादन और कृषि आधारित रोज़गारों से गाँव ख़ुशहाल होने के साथ-साथ स्वावलंबी बनने लगा। पिछले पाँच वर्षों एक मीटर 34 सेंटीमीटर ज़िले का भू-जलस्तर बढ़ा है। ऐसी रिपोर्ट माइनर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश ने दी है। आज सरकार सूखे बुंदेलखण्ड के चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, छतरपुर में सरकारी धान ख़रीद सेंटर बनाकर धान ख़रीद रही है। अब यहाँ पानी की वजह से लाखों कुंतल धान पैदा होता है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में किसानों ने फ़सल बोने का रक़बा बुंदेलखण्ड में मेड़बन्दी करके तीन लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ाया है। आज बुंदेलखण्ड आत्मनिर्भर हो रहा है। यहाँ के किसानों की अपनी मेहनत की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उनके साथ खड़ी हैं।

जखनी को मिली जलग्राम की मान्यता

बिना किसी सरकारी सहयोग के सामुदायिक आधार पर आस-पास के गाँवों में फैलती इस जलक्रान्ति की बोछार जब सरकार तक पहुँची, तो किसानों के लिए चिन्तित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिन्तन को जखनी की जलक्रान्ति ने गति दी। उन्होंने तुरन्त देश भर के सरपंचों को मेड़बन्दी सहित परम्परागत तरीक़े से जल संरक्षण के लिए पत्र लिखा इस पर पहल की। जल शक्ति मंत्री

गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन पर जलशक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने जखनी का रुख़ किया। जल सचिव यू.पी. सिंह ख़ुद जखनी के खेतों में आकर किसानों से मिले, उनके कार्य और परिणाम को देखा और तमाम भागदौड़ के बाद सरकार के जलक्रान्ति अभियान के अंतर्गत ग्राम जखनी को सम्पूर्ण भारत के लिए जलग्राम की मान्यता मिली। प्रत्येक ज़िले में जखनी मॉडल पर जलग्राम के लिए दो गाँव चुने गये। वर्तमान में जलक्रान्ति अभियान के अंतर्गत जलशक्ति मंत्रालय ने जखनी मॉडल पर जलग्राम बनाने के लिए देश के 1050 गाँवों की सूची तैयार की है, जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

तकनीक को समझने के लिए आने लगे देश-विदेश से विशेषज्ञ

बिना किसी सरकारी सहायता, बिना किसी आधुनिक मशीनी प्रशिक्षण व नवीन ज्ञान तकनीकी के ऋषि-मुनि प्रदत्त खेती-किसानी के परम्परागत तरीक़ों से केवल सामुदायिक आधार पर उमाशंकर के गाँव जखनी ने सिद्ध कर दिया कि वातानुकूलित कमरों में बैठने से जल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए जनमानस को स्वयं ही जागना होगा। अपने जलाश्य की सुध लेनी होगी और जलाश्य पर बैठकर ही जल का हल निकालना होगा। जखनी से निकली छोटी-सी जल मशाल आज सम्पूर्ण भारत में सामुदायिक प्रयास से जल संरक्षण की चर्चा विश्व स्तर पर होने लगी है। जल संरक्षण की इस तकनीक को जानने, समझने के लिए देश विदेश के जल विशेषज्ञ, सरकार की विशेषज्ञ समिति, 2030 वर्ल्ड वाटर रिसोर्स ग्रुप, कृषि प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल जीवन मिशन (उत्तर प्रदेश), जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जल वैज्ञानिक, छात्र लगातार जखनी पहुँच रहे हैं; शोध कर रहे हैं। उन किसानों के कार्य पर, जिनके पास कोई डिग्री

नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं; यहाँ तक की शिक्षा का कोई आधारभूत ज्ञान नहीं।

पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से मिली थी प्रेरणा

15 साल पहले पूर्व राष्ट्रपति स्व. अब्दुल कलाम आज़ाद की प्रेरणा और आह्वान से उमाशंकर पांडे ने अपने गाँव को जलग्राम बनाने का संकल्प लिया था। तब साधारण-से दिखने वाले उमाशंकर के संकल्प से लोग अचम्भित थे और सशंकित भी, कि बिना किसी संसाधन और सरकारी सहायता के गाँव का सीधा-सादा किसान कैसे सूखाग्रस्त गाँव को पानीदार बनाएगा? कैसे राष्ट्रपति जी के जलग्राम स्वप्न को पूरा करेगा? कैसे अपने गाँव को पानी की समस्या से उबारेगा? कैसे उमाशंकर की परम्परागत भूजल संरक्षण तकनीक पूरे देश को पानीदार बनाने की दिशा देगी? लेकिन भूजल विशेषज्ञ अविनाश मिश्र की परम्परागत सामुदायिक तकनीक और आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ से मेड़बन्दी यज्ञ की शुरुआत से स्वावलंबन का मंत्र लेकर उमाशंकर पांडे ने जखनी गाँव को जलग्राम बनाकर वह संकल्प पूरा किया। किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में देश के अनेक गाँव जखनी की तर्ज पर जल संरक्षण के परम्परागत तरीक़े प्रयोग में ला रहे होंगे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है।

भले ही कोई डिग्री धारक पढ़ा-लिखा अनुसंधानकर्ता जल संरक्षण के मामले में अधिक शिक्षित हो; लेकिन भारत के अनपढ़ किसानों ने सिद्ध कर दिया कि जल हमारे अपने पुरुषार्थ से ही बच पाएगा। बिना किसी सरकारी सहायता के सामुदायिक आधार पर समाज को फिर से आगे आकर आस्था और संकल्प के साथ अपनी ऋषि आधारित परम्परागत खेती-किसानी से ही जल को बचाना होगा और गाँव-गाँव को जल-स्वावलंबी बनाना होगा। वर्षा बूँदे जहाँ गिरें, वही रोकना होगा। बड़ी बात है कि जलग्राम जखनी के इन योद्धाओं ने न तो कोई सरकार से पुरस्कार के लिए आवेदन किया, न ही सरकारी अनुदान के लिए आवेदन किया और न ही अपमान से डरे। और जीत का नतीजा यह हुआ कि नीति आयोग ने देश की सबसे महत्त्वपूर्ण वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट-2019 में जखनी गाँव को देश का आदर्श गाँव माना है। तत्कालीन ज़िलाधिकारी (बांदा) ने 470 ग्राम पंचायतों में जखनी मॉडल भू-जल संरक्षण के लिए लागू किया। जल मंत्रालय, भारत सरकार ने सन् 2015 में जलग्राम विधि को उपयुक्त माना। सन् 2016 में 1050 जल ग्राम देश में चिह्नित किये। कुल मिलाकर जब ग्रामीण समाज खड़ा हुआ, तब सरकार खड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की देखरेख में कोरोना-काल के दौरान सर्वाधिक धनराशि मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से जखनी के भूजल संरक्षण मंत्र मेड़बन्दी के आधार पर सूखा प्रभावित राज्यों की तीन लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ख़र्च की। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की ज़िलाधिकारी ने 14 गाँवों को जलग्राम बनाया। कह सकते हैं कि सरकार सुनती है; लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए।

धैर्य और सच्चे संकल्प ने ही जखनी को सिद्धि, प्रसिद्धि, समृद्धि दिलायी। हमें बग़ैर सरकार की सहायता के सामुदायिक आधार पर परम्परागत तरीक़े से भू-जल संरक्षण करके जखनी ने जो उदाहरण दिया। जखनी की इस जलग्राम क्रान्ति 'खेत पर मेड़, मेड़-मेड़ पर पेड़' को पूरे भारत के गाँवों को स्वीकारना होगा; जो जल के लिए होने वाले किसी भी सम्भावित विश्वयुद्ध को टालने का सहज, परम्परागत और स्थायी उपाय है। तहलका

letters@tehelka.com

कोरोना टीका लगवाने से क्यों कतरा रहे लोग ?

- अविश्वास और डर की वजह से बहुत-से लोग नहीं लगवा रहे टीका
- एसएमएस और फोन करके बुलाने पर भी नहीं जा रहे अस्पताल

राजीव दुबे

देश में भले ही कोरोना टीके को लेकर उपलब्धि भरी गाथाएँ गायी और सुनायी जा रही हों, लेकिन हक़ीक़त तो कुछ और ही है। लोगों में कोरोना टीका की विश्वसनीयता को लेकर डर और शंकाएँ बरक़रार है। हाल यह है कि क़रीब 25 फ़ीसदी लोग टीका लगवाने के लिए ही आगे आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों से लेकर स्वास्थ्यकर्मी तक टीका लगवाले से बच रहे हैं। उनका मानना है कि जल्दबाज़ी में तैयार किया गया टीका कहीं उनको मुसीबत में न डाल दे। दरअसल टीका लगने की शुरुआत (16 जनवरी) के बाद से कुछ की मौतें भी हुई हैं और कुछ लोगों को एलर्जी सहित तामाम स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक़्क़तें हुई हैं, जिससे लोगों में डर बैठ गया है। तहलका संवाददाता ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में लोगों से कोरोना और वैक्सीन को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि जब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और कोरोना तक़रीबन ख़ात्मे की ओर है, तो टीका क्यों लगवाएँ। पंजाब के रोपड़ ज़िले के निवासी जत्थेदार दर्शन सिंह का कहना है कि सरकार अपनी सियासत चमकाने के लिए टीकाकरण का आँकडा बनाने में लगी है; जबकि कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं। अब तक़रीबन एक से दो फ़ीसदी ही कोरोना के मामले बचे हैं, टीका लगवाकर क्यों जान जोखिम में डालें। उनका कहना है कि दिल्ली की सीमाओं पर दो महीने से किसान बैठे हैं; किसी को कोई कोरोना नहीं हुआ है। तो कोरोना को लेकर सरकार बे-वजह हौवा क्यों बना कर रही है? पंजाब के होशियारपुर निवासी सरदार इन्द्रजीत

सहोता का कहना है कि कोरोना को लेकर जो डर बनाया गया था, वो डर चला गया है। अब टीका लगवाने का कोई मतलब नहीं है।

मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी), जहाँ क़रीब 300 स्वास्थ्यकर्मी हैं, के स्वास्थ्य कर्मचारियों और डॉक्टरों तक ने टीका लगवाने से मना कर दिया था। डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के टीका लगवाने से मना करने पर शासन-प्रशासन ने दबाब बनाया, तब यहाँ के डॉक्टरों को प्रेरणा समिति का गठन करना पड़ा। तब जाकर कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों व सभी ने लगवाने शुरू किये। यही हाल मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह ज़िले का है। यहाँ के कर्मचारियों ने पहले तो टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जब देश में टीके के नुक़सान के मामले सामने आये, तो उन्होंने टीका न लगवाने का फ़ैसला कर लिया। स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहले एसएमएस और फोन करके भी बुलाया जा रहा है, तब भी वे नहीं जा रहे हैं। स्वास्थ्य का हवाला देकर बच रहे हैं; टीकाकरण की तारीख़ बढ़वा रहे हैं। जब यह हाल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों का है, तो आम जनता में तो भय फैलना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, झाँसी और कानपुर के लोगों ने तहलका को बताया कि अजीब हालात हैं। एक ओर तो सरकार टीकाकरण को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तामाम क़ायदे-क़ानूनों को लागू कर रही है, वहीं रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद टीका लगवाने से डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तक कतरा रहे हैं। इसका मतलब टीके को लेकर अभी अविश्वास की स्थिति है। यही वजह है कि आम नागरिकों में तामाम तरह की अफ़वाहें, डर, और आशंकाएँ फैल रही हैं।

दिल्ली, जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाएँ हैं; के कर्मचारियों बताते हैं कि कोरोना टीके को लेकर सरकार का कहना है कि जिसको टीका लगवाना है, वह लगवा सकता है और जिसको नहीं लगवाना है, वह न लगवाये। यानी की कोई ज़ोर-जबरदस्ती नहीं है। वहीं सरकार टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाने के लिए काम कर रही है और टीका लगवाने के लिए दबाव बना रही है। डीएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल बंसल का कहना है कि दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पतालों में टीके लग रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में टीके को लेकर आशंकाएँ हैं कि जल्दबाज़ी में लाया गया टीका कहीं किसी दिक़्क़त में न डाल दे। इसलिए स्वास्थ्य कर्मचारी हों या आम लोग, अभी पूरी तरह से टीके के नुक़सान-फ़ायदे पर नज़र रखे हुए हैं। लगता है पूर बरोसा होने पर लोग इसे लगवाने के लिए तैयार होंगे। डॉ. बंसल ने बताया कि जो कोरोना का भय था, पर अब नहीं रहा। इसके अलावा जिन लोगों को कोरोना हुआ था, वे स्वस्थ्य भी हो गये हैं। ऐसे में लोगों का मानना है कि अब टीकाकरण की क्या ज़रूरत? कुछ लोगों का मामना यह भी है कि जब वैक्सीन आ गयी है, तो दवा और कैप्सूल भी आ सकते हैं, तो दवा के सेवन से ही कोरोना को मात देंगे। उन्हें लगता है कि टीके की तुलना में दवा का रिएक्शन कम होगा।

दिल्ली में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वे वैक्सीन लगवाने किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन लगाकर आँकड़ों को पूरा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी राजेश प्रसाद का कहना है कि सरकार ने जो टीका बनवाया है, वो मानक समय से पहले तैयार हो गया है, जिससे लोगों में विश्वास का अभाव है। क्योंकि तमाम बीमारियों के टीकों को लेकर वर्षों से शोध ही चल रहा है, जिसमें एचआईवी भी शामिल है। ऐसे में कोरोना टीके को लेकर जो जल्दबाज़ी दिखायी गयी है, उसे लेकर आशंका है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जिस प्रकार कोरोना वायरस और उसके टीके को लेकर सियासत के नफ़ा-नुक़सान का खेल खेला जा रहा है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि मरीज़ों में भेदभाव और बीमारी का विभाजन नहीं हो सकता है। ऐसे में जिस तरीक़े से कई चरणों और उम्र को देखकर में टीकाकरण की बात की जा रही है, उससे कोरोना वायरस का निदान नहीं हो सकता। डॉक्टरों का कहना है कि जिन्हें कोरोना संक्रमण की शिकायत या आशंका है, उनको टीका लगना चाहिए, न कि रिकॉर्ड बनाने के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। जाने-माने आयुर्वेदाचार्य डॉ. दिव्यांग देव गोस्वामी का कहना है कि कोरोना के कम होते मामले यह बताते हैं कि देश में लोगों ने अपने बल-बूते पर जागरूकता और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कोरोना को क़ाबू कर लिया है। इसलिए सरकार कोरोना टीके को लेकर भी जागरूकता पर बल दे। दिल्ली के कई डॉक्टरों का मानना है कि देश के नागरिकों की इम्युनिटी पॉवर अन्य देशों की तुलना में ठीक है। अब कोरोना वायरस ख़ात्मे की ओर है। ऐसे हालात में अब टीकाकरण को लेकर ज़्यादा शोर-शराबा ठीक नहीं है। सरकार को अब उन मरीज़ों के इलाज पर भी ज़ोर देना चाहिए, जो कोरोना-काल में इलाज नहीं करवा पाये। तहलका

letters@tehelka.com

टीकाकरण में जातिवादी भेदभाव का आरोप

इधर कोरोना वायरस के टीकाकरण में जातिवादी भेदभाव का आरोप लग रहा है। आरोप यह है कि सबसे पहले निचले तबक़े (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि अगर कोई शारीरिक या मानसिक नुक़सान हो, तो वह निचले तबक़े के लोगों को हो। आरोप है कि उच्च वर्ग इस इंतज़ार में है कि सब ठीक रहा, तो वह टीका लगवाएगा।

एक वेबसाइट पर प्रकाशित अपने एक लेख में असिस्टेंट प्रो. प्रमोद रंजन ने लिखा है- 'सभी जानते हैं कि टीका पहले लेने का ख़तरा उठाने के लिए जिन स्वच्छता कर्मियों को आगे किया जा रहा है, वे भारत में निम्न कही जाने वाली जातियों से आते हैं; जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक दमन का शिकार रही हैं। भारत में कोविड-19 का पहला टीका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में दिया गया। इसके लिए एम्स ने अपने सफ़ाई कर्मचारी मनीष कुमार को चुना। मनीष की जाति का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इस बात की पूरी सम्भावना है कि मनीष दलित समुदाय से आते हैं। क्योंकि भारत में सफ़ाई कर्मचारियों का लगभग शत्-प्रतिशत उन दलित और पिछड़ी जातियों से आता है, जिन्हें जाति-व्यवस्था के अनुसार गन्दे कामों को करने के लिए उपयुक्त माना गया है।'

प्रो. रंजन आगे लिखते हैं- 'सच्चाई यह है कि भारत का उच्चवर्ग, जो सामान्य तौर पर सामाजिक रूप से उच्च और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है, वह इंतज़ार करो और देखो की नीति पर चल रहा है। उसके लिए वैक्सीन की राजनीति एक ऐसा समुद्र मंथन है, जिसके बारे में वह अभी कुछ तय नहीं कर पा रहा है। इस मंथन से निकला कलश (टीका) अगर अमृत साबित होगा, तभी वह उसे ग्रहण करेगा; लेकिन उससे पहले उसे पीकर शूद्रों-अतिशूद्रों (मूल हिन्दू मिथक के अनुसार, असुरों-राक्षसों) को चखकर देखना होगा।'

सरकार को अब उन मरीज़ों के इलाज पर भी ज़ोर देना चाहिए, जो कोरोना-काल में इलाज नहीं करवा पाये।

ग्यारह बच्चों की मौत के दोषियों को होगी सज़ा ?

पीड़ित परिजनों को मिलेगा मुआवज़ा

महेंद्र सिंह राठौड़

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जम्मू-कश्मीर सरकार से रामनगर क्षेत्र में 11 बच्चों की मौत पर कड़ा संज्ञान लिया है। आदेश में मृतक बच्चों के क़रीबी परिजनों को तीन-तीन लाख रुपये रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने इसे घोर लापरवाही बताते हुए कहा कि सरकार की ओर से पहली घटना के बाद गम्भीर प्रयास करती तो इतने बच्चों की मौत नहीं होती। इस मुहिम की शुरुआत सुकेश खजूरिया ने की थी जिसे वे शुरुआत बता रहे हैं। दोषियों को सलाख़ों के पीछे पहुँचाने के लिए उनके पास पुख़्ता सुबूत है और वे सज़ा से बच नहीं सकेंगे।

शिक्षक अशोक कुमार कहते हैं कि उनके दो साल के बच्चे अनिरुद्ध की मौत की वजह यही बेस्ट कोल्ड सीरप रही। इस ज़हरीली दवा ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुआवज़े का आदेश आर्थिक संबल देगा; लेकिन दवा निर्माता कम्पनी के मालिकों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वे रसूख़दार और पैसे वाले हैं; लेकिन बचने नहीं चाहिए। उन्हें कड़ी सज़ा मिले, जो नज़ीर बन सके; ताकि फिर कोई अनिरुद्ध या पंकू जैसे नौनिहालों को मौत न मिले। राष्ट्रीय मीडिया को चाहिए कि वह इस मुद्दे को शिद्दत से उठाये, ताकि हम लोगों को इंसाफ़ मिल सके। बता दें कि 'तहलका' ने शुरू से ही इस मामले को गम्भीरता से उठाया, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

गोविंदराम, निम्मो देवी, अनिल कुमार और भोली देवी के नौनिहालों की मौत इसी दवा से हुई। प्रभावित परिजनों के मुताबिक, रामनगर में 11 बच्चों की मौत तो सरकारी आँकड़ों में है, पर यह संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी निश्चित तौर पर बच्चों की मौतें हुई होंगी, जो बच्चे दवा से किसी तरह बच गये, उनमें कई तरह के विकार पैदा हो गये हैं। जम्मू के ऊधमपुर ज़िले के रामनगर क्षेत्र में दिसंबर, 2019 से जनवरी, 2020 के दौरान एक के बाद एक करके 11 बच्चों की मौत हुई। जाँच के बाद मौत की वजह बेस्ट कोल्ड सीरप का सेवन पाया गया। रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब (आरडीटीएल) में जाँच के दौरान यह मानकों पर खरी नहीं उतरी। हिमाचल के बद्दी में डिजिटल विजन नामक कम्पनी ने यह दवा खाँसी-जुकाम ठीक होने के लिए निर्मित की; लेकिन यह जानलेवा साबित हुई और कम्पनी को पता भी नहीं चला और न जाने कितना उत्पाद अन्य राज्यों में भेज दिया? किस राज्य में कितने बच्चे इस दवा के सेवन से मरे? इसका पता भी नहीं है। जाँच के बाद कम्पनी का लाइसेंस रद्द करके उसे सील किया गया।

25 दिसंबर, 2019 को श्रेयांस ने दम तोड़ दिया। अपने घर पहुँचे तो रामनगर क्षेत्र में दो दिन बाद 27 दिसंबर को तीन साल के बच्चे कनिष्क की मौत की ख़बर मिली। उसकी मौत की वजह भी हमारे श्रेयांस जैसी रही। उसे भी खाँसी-जुकाम की शिकायत थी। दो दिन बाद 29 दिसंबर को लगभग एक साल की बच्ची जाह्नवी और अगले दिन डेढ़ साल की बच्ची लक्ष्मी को मौत ने निगल लिया। छः दिन में तीन मौतें! बीमारी एक, दवा भी एक और मौत की वजह भी एक। लेकिन उस समय किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्वास्थ्य विभाग इसे अज्ञात बीमारी से होने वाली मौत मानता रहा। बच्चों की मौत का सिलसिला रुका नहीं, तीन दिन बाद नये साल में 2 दिसंबर को चार साल के अमित को भी नहीं बचाया जा सका। अगले दिन तीन साल की सुरभि, दो साल के अनिरुद्ध, एक साल का पंकू, डेढ़ साल के अक्षु, एक वर्षीय नीजू और दो वर्षीय जानू; सब खाँसी-जुकाम जैसी बीमारी के आगे हार गये।

क़रीब एक माह में 11 मौतों से रामनगर के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। स्वास्थ्य विभाग के अलावा शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौत की एक ही वजह सामने आने पर दवा का पता लगाया गया। सभी बच्चों को उसी डिजिटल विजन नामक कम्पनी की दवा दी गयी थी। उसे देने के बाद ही बच्चों की तबीयत

बिगड़ी। फिर दवा को जाँच के लिए चंडीगढ़ की रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजा गया। जाँच में ख़ुलासा हुआ कि कोल्ड बेस्ट पीसी सीरप मानक पर खरी नहीं उतरी और सेंपल फेल हो गया। दवा में डाई एथिलीन ग्लायकोल की मात्रा 34.5 फ़ीसदी पायी गयी, जो तय मात्रा से ज़्यादा थी। इससे यह ज़हर का काम कर रही थी।

ऊमधपुर ज़िले के रामनगर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत ख़स्ता है। दूरदराज़ के गाँवों में तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएँ न के बराबर हैं। यहाँ के कई गाँव तो सड़कों से भी नहीं जुड़े हैं; जबकि कई गाँव आज के दौर में बिजली से भी वंचित है। रामनगर के अस्पताल में उनकी पहुँच इतनी आसान नहीं दिखती। हालत यह कि कई बार मरीज़ों को परिजन चारपाई पर ही लाने पर विवश हैं। रामनगर के अस्पताल में कई डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में मरीज़ों को ज़िला अस्पताल ऊधमपुर स्थानांतरित करना पड़ता है। यहाँ से आवागमन के भरपूर साधन नहीं हैं, बावजूद इसके लोग किसी तरह पहुँचने पर मजबूर हैं। कहा जा सकता है कि जम्मू संभाग का यह इलाक़ा स्वास्थ्य सेवाओं में बेहद पिछड़ा हुआ है।

बेस्ट कोल्ड सीरप के सेवन से जिन बच्चों की मौत हुई उनमें, जाह्नवी केवल 11 माह की और सबसे बड़ा अमित चार साल का था। ज़्यादातर बच्चों के परिजन आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। मज़दूरी आदि कर किसी तरह घर का काम चलाते हैं। बच्चों के उपचार पर हज़ारों रुपये ख़र्च किये। बहुत से परिजनों पर उधारी हो गयी, बावजूद इसके बच्चे भी नहीं बचे। उनके मुताबिक, मुआवज़े के आदेश के बाद उन्हें लगता है कि बच्चों को इंसाफ़ मिलेगा।

इंसाफ़ की डगर

रामनगर इलाक़े में 11 बच्चों की मौत और पीड़ित परिवारों को इंसाफ़ दिलाने की मुहिम में सामाजिक कार्यकर्ता सुकेश चंद्र खजूरिया का विशेष योगदान है। खजूरिया राज्य सरकार की अधिकृत सिटीजन एडवाइजरी समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। देशहित से जुड़े मुद्दों और आम लोगों के इंसाफ़ के लिए वे आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। रामनगर के इस मामले वे हर पीड़ित परिवार को जानते हैं, उनके गाँवों तक पहुँच चुके हैं। हर पीड़ित सदस्य उन्हें जानता है, उन पर भरोसा जताता है।

जाँच रिपोर्ट से लेकर अन्य दस्तावेज़ उनके पास है। राष्ट्रीय मानवाधिकार और राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग तक वे पहुँच गये हैं। उनकी पहल पर ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मृतक बच्चों के क़रीबी परिजनों को तीन-तीन लाख रुपये मुआवज़े का आदेश दिया है। जम्मू के अलावा यह मामला हरियाणा और हिमाचल से जुड़ा है। इसके लिए उन्हें काफ़ी भागदौड़ भी करनी पड़ती है। वह कहते हैं कि थककर बैठने वालों में वह नहीं है। जिनके बच्चे ज़हरीली दवा की वजह से मौत के शिकार हो गये, वह उनके साथ पहले दिन से खड़े हैं। अभी तो आयोग ने जम्मू-कश्मीर सरकार की लापरवाही को मद्देनजर रखते हुए मुआवज़े के आदेश दिये हैं। बच्चों की मौत के दोषी तो दवा निर्माता कम्पनी के मालिक है। उनके ख़िलाफ़ संगीन आरोप है। पुख़्ता सुबूत हैं, उन्हें सलाखों के पीछे जाना ही होगा। इससे बच्चे तो वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन उनके परिजनों को लगेगा कि हाँ, कुछ इंसाफ़ ज़रूर हुआ है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में भी यह मामला उठ चुका है। दवा कम्पनी राज्य में है लिहाज़ा सरकार की कड़ी कार्रवाई की दरकार है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में कह चुके हैं कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बेस्ट कोल्ड सीरप दवा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दवा जाँच में मानकों पर खरी नहीं उतरी है। यह कम्पनी की बहुत बड़ी ख़ामी है। इस प्रकरण में कड़ी कार्रवाई होगी। यह राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है लिहाज़ा किसी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। जाँच रिपोर्ट आते ही शीर्ष अफ़सरों को तुरन्त प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिये गये।

निर्माता कम्पनी डिजिटल विजन

हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर के कालाअंब स्थित दवा कम्पनी डिजिटल विजन का कारोबार देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में है। सन् 2009 में स्थापित कम्पनी का टर्नओवर 45 करोड़ के आसपास है। यहाँ 250 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कम्पनी का स्वामित्व पुरुषोत्तम गोयल और कोनिक गोयल का है। कम्पनी अफ़ग़ानिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया, सूडान, घाना, कांगो, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, वियतनाम, आयरलैंड और स्पेन तक फैला है। आयरलैंड में तो कम्पनी का पंजीकृत दफ़्तर भी है। कुल 165 से ज़्यादा दवाइयों का उत्पादन यहाँ होता है। टेबलेट-केप्सूल से लेकर इंजेक्शन तक यहाँ तैयार होते हैं। रामनगर में बच्चों की मौत के लिए डिजिटल विजन कम्पनी ही प्रमुख तौर पर ज़िम्मेदार है। हिमाचल के बद्दी, बरोटीवाल और कालाअंब क्षेत्र दवा उद्योग का गढ़ है। यहाँ साढ़े चार सौ से ज़्यादा इकाइयाँ हैं। दवा कम्पनियों को सरकार की ओर के विशेष छूट दी जाती है। तहलका

letters@tehelka.com

क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज़रूरी है ?

मदीहा रज़ा

आप भावनात्मक तरीक़े से मूर्ख बनाना बन्द कीजिए! ऐसे वाक्यों का मतलब यह भी है कि किसी को भावनात्मक तरीक़े से जुड़ने के लिए ख़ुद को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो उसे तकनीकी रूप से कम बुद्धिमान माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जो लोग हल्की-फुल्की बातों पर अन्दर से टूट जाते हैं, वे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते और उन्हें अपरिपक्व कहा जाता है।

आमतौर पर बुद्धिमान लोगों को ऊँची सोच वाला माना जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईक्यू) बुद्धिमत्ता भागफल (आईक्यू) से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। विशेष रूप से कारोबार की दुनिया में देखें, तो सबसे सक्षम और प्रभावी व्यक्ति उच्च ईक्यू वाले ही होते हैं। वास्तव में पारम्परिक बुद्धि परीक्षणों पर औसत अंक वाले लोग 70 फ़ीसदी उच्च आईक्यू वाले लोगों को हरा देते हैं, और इसका कारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है। 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को स्थान दिया है। क्योंकि सफलता के लिए शीर्ष 10 सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य-स्थल कौशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हाल के वर्षों में इसे प्रबन्धन का एक बेहद महत्त्वपूर्ण कारक माना जाने लगा है। कहते हैं कि हर चीज़ की अति बुरी होती है। इसलिए अत्यधिक संवेदनशील लोग लगातार भावनात्मक बारीक़ियों से वाक़िफ़ होते हैं। ये लोग दूसरों को आसानी से अपने ऊपर हावी होने देते हैं। वहीं जो लोग भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, वे भावनात्मक लोगों से अपना काम निकालते हैं, जिससे उन्हें ठेस पहुँचती है, जो निरंतर चिन्ता की वजह बनती है।

क्या है भावनात्मक बुद्धिमत्ता ?

क्या आप अक्सर आवेगपूर्ण स्थिति में रहते हैं? ऐसी बातें कहते हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि आपको बाद में पछताना नहीं चाहिए? या क्या आप अपनी भावनाओं से वंचित और भावनात्मक रूप से सुन्न महसूस करते हैं? तो सम्भवत: आपको अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हममें से ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करना मुश्किल हो सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपने आपमें और एक के निर्णयों को दूसरों के प्रभावों को पहचानने के तरीक़े को प्रबन्धित करने की क्षमता का वर्णन करती है। ईक्यू के मुख्य कारकों में आत्म-जागरूकता, स्व-प्रबन्धन, सामाजिक जागरूकता और सम्बन्ध प्रबन्धन शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र में निहित, सहानुभूति, सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्म-नियंत्रण, उपलब्धि, अनुकूलनशीलता, प्रभाव, संघर्ष प्रबन्धन, संगठनात्मक जागरूकता, संरक्षक, टीमवर्क, प्रेरणादायक नेतृत्व सहित 12 ईआई कौशल हैं। इन कौशलों को प्राथमिक स्थान के रूप में भावनाओं के साथ अधिक-से-अधिक जुड़ाव की आवश्यकता होती है और यह किसी भी इच्छुक शख़्स की विकास प्राथमिकताओं का एक हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा भावनात्मक बुद्धिमत्ता चिन्ता को कम करने, कुशलता से बात करने, दूसरों के साथ सहानुभूति रखने, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने और तर्कों को हल करने में अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और सकारात्मक तरीक़े से उपयोग करने की क्षमता है। जब आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से जानने और समझने की क्षमता विकसित करते हैं, तो आपको यह जानना आसान हो जाएगा कि दूसरे के प्रति कितने संवेदनशील हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्त्वपूर्ण साबित हुई और इसने विभिन्न रोगों से निपटने के लिए मार्गदर्शन का काम किया। क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कहीं ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गयी। अनिश्चितता के समय में अपनी ख़ुद की भावनाओं को पहचानने और बेहतर ढंग से सँभालने की क्षमता आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान करती है।

हालाँकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें एक कठिन परिस्थिति से निपटने और विभिन्न बीमारियों से जूझने में मदद करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे मस्तिष्क को भावनात्मक संकट से निपटने की क्षमता का समर्थन करती है। यह लचीलापन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत रखता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। भावना अब नैदानिक सिद्धांत के केंद्र में है और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। मनोवैज्ञानिक तरुण साह के अनुसार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एकीकरण कई विषयों से समझ सकते हैं। क्योंकि इस बात पर आम सहमति है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का काम सन्तुष्टि, तनाव स्तर, परलोक पर ध्यान है और सकारात्मक वातावरण को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिद्धांत है, जो नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि इसमें मरीज़ की देखभाल और प्रभाव, निर्णय लेने, महत्त्वपूर्ण सोच और बड़े पैमाने पर नर्सों की प्रैक्टिस के महत्त्व को प्रभावित करने की क्षमता है। तबाही के समय हमारे घरों, कार्य-स्थलों और सार्वजनिक क्षेत्र में स्वस्थ परिवेश को बनाये रखने के लिए सहानुभूति, आत्म-नियमन और सकारात्मक सम्बन्धों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार नीति निर्माताओं को इस कठिनाई को जीतने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) की सराहना, वकालत और चैनलाइज करना आवश्यक है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व

होशियार लोग अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली हो सकते हैं; लेकिन जीवन में हमेशा पूरे नहीं होते। आप लोगों को सामाजिक रूप से अक्षम और काम पर या अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों में असफल देख सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बौद्धिक क्षमता या बुद्धिमत्ता भागफल (आईक्यू) अपने आपमें पर्याप्त नहीं है। वास्तव में आईक्यू अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह ईक्यू अन्तिम परीक्षा का सामना करते समय आपके तनाव और भावनाओं को प्रबन्धित करने में मदद करेगा।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल उतनी ही बेहतर है, जितनी कि बेहतर बुद्धिमत्ता भागफल। जब आपके रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों में ख़ुशी और सफलता की बात करता है। तनाव को संतुलन में लाओ और अप्रिय भावनाओं को सहन करना सीखो,

जो किसी व्यक्ति के मज़बूत भावनात्मक स्तर को दर्शाती है। कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप कितने चिन्तित या भावनात्मक रूप से नियंत्रण से बाहर हैं। यदि आपके पास अच्छी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, तो जीवन आसान और अधिक संतोषप्रद हो जाता है।

तरुण साह ने कहा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके दैनिक जीवन के कई अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करती है, जैसे कि आप किस तरह से व्यवहार करते हैं और कैसे आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। आप अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से सम्बन्ध बनाने के लिए भावनाओं की समझ का उपयोग कर सकते हैं। बेहतर रिश्ते बनाकर अधिक-से-अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा सुखद जीवन जी सकते हैं।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण कैसे करें

ये प्रमुख कौशल एक व्यक्ति को भावनात्मक बुद्धि विकसित करने में मदद करते हैं :-

1. आत्म-प्रबन्धन : भावनात्मक बुद्धिमत्ता के निर्माण के लिए तनाव का प्रबन्धन पहला क़दम है। स्वस्थ तरीक़ों से अपनी भावनाओं को प्रबन्धित करना। जैसे- पहल करना, प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार ख़ुद को अनुकूलित करना, आप आवेगी भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। स्वयं से अनजान होना पर्याप्त नहीं है। एक को अपनी भावनाओं से निपटने में सक्षम होना चाहिए। अपनी क्षमता और ख़ामियों की खोज करें और जानें कि वे आपके विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? और तदनुसार कार्य करें।

2. आत्म-जागरूकता : आत्म-जागरूकता में तीन स्तरों पर अपने और अपने व्यवहार को समझना शामिल है- 1) आप क्या कर रहे हैं? 2) आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? और 3) आप अपने बारे में क्या नहीं जानते? हममें से अधिकांश लोग यह नहीं जानते हैं कि हम कैसे कार्य करते हैं और हम आधा समय क्या करते हैं? हम ऑटोपायलट- व्हाट्स ऐप, इंस्टाग्राम पर हैं और तस्वीरें इत्यादि पोस्ट करते हैं; ईमेल चेक करते हैं। अपने स्वयं के लिए जगह ढूँढना और अपने जीवन के बारे में सोचना, इन दिनों सोशल मीडिया पर विचरण के कारण मुश्किल हो जाता है। वास्तव में हम आमतौर पर इन विकृतियों में शामिल होते हैं, ताकि बहुत-सी असहज भावनाओं से बचा जा सके, जो हमें लगातार प्रभावित करती हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण करने के लिए हमें स्वयं के बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए।

3. सामाजिक जागरूकता : सामाजिक जागरूकता में भावनाओं को स्वीकार करना शामिल है। इससे हम अन्य लोगों की चिन्ताओं को, भावनात्मक संकेतों से समझ सकते हैं। सामाजिक ज़िन्दगी आराम से गुजरती है और एक समूह या संगठन में शक्ति को गतिशीलता मिलती है। यदि आप अच्छे सम्बन्धों को विकसित करने और उन्हें बनाये रखने में सक्षम हैं, तो स्पष्ट रूप से संवाद करें; दूसरों को प्रेरित करें और प्रभावित करें। एक टीम में अच्छा काम करें। क्योंकि संघर्ष व प्रबन्धन जैसे गुण आपकी सामाजिक चेतना दिखाते हैं।

4. सम्बन्ध प्रबन्धन : भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास का सम्पूर्ण बिन्दु अंतत: जीवन में स्वस्थ सम्बन्धों को प्रोत्साहित करता है। हममें से बहुत-से लोग अपनी भावनाओं से वंचित हैं; विशेष रूप से सुदृढ़ भावनाएँ; जैसे कि क्रोध, उदासी, भय। क्योंकि बचपन से हमें अपनी भावनाओं को छिपाना सिखाया जाता है। इसलिए हम अपनी भावनाओं को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम अपनी भावनाओं को अस्वीकार कर सकते हैं या दबा सकते हैं, मगर उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। वो अभी भी वहाँ हैं, चाहे हम उनके बारे में जानते हों, या नहीं। एक शून्य हमेशा हमारे भीतर कहीं रहता है। रिश्ते अंतत: हमारे मूल्यों को व्यक्त करने का तरीक़ा हैं। हमारी भावनाएँ उस व्यक्ति के लिए कार्यों को प्रोत्साहित करके उन मूल्यों को पूरा करती हैं। दुर्भाग्य से अपनी सभी भावनाओं से जुड़े बिना, हम तनाव के प्रबन्धन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए अपनी भावनाओं को पहचानें।

5. प्रेरणा : प्रेरणापूर्ण ध्यान और ऊर्जा के साथ चीज़ों को करने का प्रयास करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण घटक है। यह समूह या टीम का नेतृत्व करते समय एक ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीक़े से सँभालने में मदद करता है। इसमें कुछ करने के हमारे व्यक्तिगत कारण शामिल हैं; यह हमारी ड्राइव, पहल, प्रतिबद्धता, आसासा और पैसे या मान्यता से परे कुछ हासिल करने की दृढ़ता का एक संयोजन है। अनुसंधान से पता चलता है कि आशावाद एकल सबसे बड़ा व्यवहार है, जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

6. सहानुभूति : अपनी बात पर अडिग रहते हुए दूसरों को पहचानने में सक्षम होना? इस घटक को सहानुभूति कहा जाता है। यह कुशलता से काम करने के लिए लोगों के एक बड़े समूह के साथ काम करते समय होने वाली अपार गुणवत्ता है। अच्छी तरह से निर्मित भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला नेता टीम के सदस्यों के सफल प्रदर्शन की पहचान को जानता है और उसकी सराहना करता है।

7. ध्यान : ध्यान और गहरी साँस लेना लोगों को वर्तमान में रहने और मन तथा शरीर में बेहतर स्थिरता प्राप्त करने के लिए अधिक नियंत्रण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। गहरी साँस लेने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो नकारात्मक विचारों को बदलने और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। तहलका

letters@tehelka.com

उच्च ईक्यू विकसित करने की आदतें

अपनी (भावनात्मक बुद्धिमत्ता) ईक्यू को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीक़ा नियमित आदतों में शामिल करें, जिससे तार्किक और भावनात्मक दिमाग़ के बीच संचार को मज़बूत किया जा सकता है। आत्म-जागरूकता में दोहन करना और सचेतन का अभ्यास करना मस्तिष्क को मज़बूत करने और इसके तर्कसंगत और भावनात्मक क्षेत्रों के बीच सम्बन्ध बनाने के लिए शानदार तरीक़े हैं। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं को नोटिस करते हैं, जो हमेशा आसान नहीं होते हैं; लेकिन इसे नियमित रूप से पूरी तन्मयता या ध्यान-अभ्यास के ज़रिये बेहतर बनाया जा सकता है।

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग भी, जब उनका तनाव का स्तर बढ़ता है और वे तनाव को अपने ऊपर लेने की अनुमति नहीं देते हैं; पहचानने की आदत में पड़ जाते हैं। इसके बजाय वे तनाव को कम करने और शान्त रहने के लिए स्वस्थ आदतों का निर्माण करते हैं। व्यायाम इसमें बहुत मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, उच्च ईक्यू वाले लोग सकारात्मकता को एक नियमित अभ्यास बनाते हैं। यहाँ तक कि जब चीज़ें गम्भीर दिखती हैं, तो वे कृतज्ञता और सकारात्मकता पा सकते हैं। यह उन्हें सक्रिय रहने की अनुमति देता है, जो उन्हें सबसे कठिन समय के दौरान सर्वोत्तम सम्भावित निर्णय लेने की क्षमता देता है।

अफ़ग़ानी महिलाओं में फिर दहशत !

अमेरिका के अपने सैन्यबल हटाने के बयान के बाद अफ़ग़ानिस्तान में दो महिला न्यायाधीशों की हत्या

अलका आर्य

क़तर की राजधानी दोहा में अफ़ग़ानी सरकार के अधिकारियों व तालिबान के बीच जारी शान्ति-वार्ता के दरमियान 17 जनवरी को अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी क़ाबुल में बन्दूकधारियों ने एक कार पर गोलीबारी की, जिसमें उच्च अदालत में कार्यरत दो महिला न्यायधीशों को मौत हो गयी। यह आलेख लिखे जाने तक किसी भी संगठन ने ज़िम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन अफ़ग़ान सरकार का मानना है कि इस हमले के पीछे तालिबान का हाथ हो सकता है। ग़ौरतलब है कि यह वारदात 17 जनवरी को हुई यानी ठीक दो दिन बाद जब अमेरिकी प्रशासन ने 15 जनवरी को बयान जारी कर कहा कि उसने अफ़ग़ानिस्तान में अपने बलों की संख्या 5,000 से कम करके 2,500 कर दी है। यूँ तो बीते कई महीनों से अफ़ग़ानिस्तान में पत्रकारों, डॉक्टरों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उच्च अदालत की दो महिला न्यायधीशों को निशाना बनाने वाली घटना से अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं की हिफ़ाज़त, उनके ख़िलाफ़ हिंसा, महिला अधिकारों को ख़तरे वाला मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह है कि क्या यह घटना क़तर में जारी शान्ति-वार्ता में तालिबान के ऊपर महिलाओं के प्रति उनके रूढ़ नज़रिये में बदलाव लाने के लिए दबाव डालने का काम करेगी। बहरहाल अफ़ग़ानिस्तान की आधी आबादी यानी औरतें, लड़कियाँ इस समय सुकून की ज़िन्दगी नहीं जी पा रही हैं, उन्हें चिन्ता शान्ति-वार्ता के आगामी नतीजों को लेकर है कि कहीं उनके संविधानप्रदत्त अधिकारों में कटौती न हो जाए और वे आगे बढ़ने की बजाय पीछे न धकेल दी जाएँ।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और तालिबान के बीच अफ़ग़ानिस्तान से 19 साल के बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी सम्बन्धी समझौता 29 फरवरी, 2020 को हुआ था। समझौते में कहा गया है कि अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी 18 महीनों के भीतर होगी, बशर्ते तालिबान आतंकवादी समूहों से लड़ने की प्रतिबद्धता का सम्मान करे। इस समझौते के अनुसार, आगामी मई तक अमेरिका अपनी शेष सेना को भी वापस बुला लेगा। लेकिन अमेरिका के नये राष्ट्रपति जो बाइडन आने वाले समय में इस सन्दर्भ में क्या रुख़ अपनाते हैं? यह देखना होगा। पर अफ़ग़ानी महिलाओं पर उनके सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक अधिकारों में कटौती होने का ख़तरा मँडराने लगा है। उन्हें भय है कि सन् 2004 में बने जिस संविधान ने उन्हें मर्दों के बराबर अधिकार दिये, कहीं उनमें कटौती न हो जाए। फिर से 2001 से पहले वाला महिला अधिकारों को दबाने वाला माहौल व नियम उन पर हावी न हो जाए। दो दशक पूर्व यानी सन् 2001 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला करके इसे वैश्विक आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग बताया था, इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि उनकी मंशा अफ़ग़ानिस्तान की महिलाओं को बेहतर ज़िन्दगी जीने व उनके मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अनुकूल अवसर मुहैया कराना भी है। दरअसल सोवियत संघ के द्वारा अफ़ग़ानिस्तान पर क़ब्ज़ा करने से पहले और युद्ध के कुछ वर्षों तक भी वहाँ महिलाओं की स्थिति अधिक ख़राब नहीं थी। विशेषतौर पर शहरी महिलाओं की। उन्हें शिक्षा हासिल करने का अधिकार था। वे पेशेवर करियर में भी थीं। न्यायपालिका व अफ़ग़ान की संसद में भी नज़र आती थीं। सन् 1964 के अफ़ग़ानी संविधान का मसौदा तैयार करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभायी। यह तथ्य सर्वविदित है कि सन् 1979 में सोवियत संघ के अफ़ग़ानिस्तान पर क़ब्ज़े व उसके बाद मुजाहिदीन के उदय से, जिसने इस मुल्क को इस्लामिक स्टेट में तब्दील कर दिया; यहाँ उस दौरान बहुत कुछ बदल गया। हालात बद से बदतर होते चले गये। सन् 1990 के शुरुआत में अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के ज़ोर पकड़ने से सिर्फ़ मुल्क की ही नहीं, बल्कि महिलाओं की हालत भी पिछड़ती चली गयी। उन्हें

फिर से पारम्परिक लैंगिक भूमिकाओं में धकेल दिया गया। मर्द-औरत के बीच भेदभाव वाली संस्कृति ज़ोर पकड़ती गयी। लड़कियों के पढ़ने पर कई पाबन्दियाँ लगा दी गयीं। नौकरी करने तक की इजाज़त नहीं थी। स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच बहुत ही सीमित थी। बुर्क़ा अनिवार्य कर दिया गया। घर के बाहर बिना मर्द के निकलने पर मनाही थी और यह मर्द भी परिवार का सदस्य होना चाहिए था। परम्पराओं के बोझ से लदी तक़रीबन हर लड़की और फिर जल्द ही दहशत से ग़ुलाम औरत में तब्दील होती गयी। जिसकी न तो अपनी ज़िन्दगी के अहम फ़ैसलों में कोई सुनवाई होती और न ही किसी भी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक फ़ैसलों में उसे जगह मिलती थी। मर्द का साया ही उस पर शासन करता, चाहे वह घर की चहारदीवारी में हो या घर की दहलीज़ के बाहर। गृहयुद्ध में पतियों, भाइयों व पिता के मारे जाने से महिलाओं की स्थिति सामाजिक व आर्थिक रूप से और भी कमज़ोर होती चली गयी। एकल महिलाओं, विधवाओं और बच्चों की मुश्किलें तालिबान शासन में बराबर बढ़ती ही चली गयीं। युवा लड़कियों, महिलाओं पर यौन-दुराचार के झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेलों में बन्द कर दिया गया। ऑनर किलिंग की घटनाएँ आम हो गयी थीं। अमेरिका ने जब सन् 2001 में आतंकवाद का सफ़ाया करने की दलील देकर अफ़ग़ानिस्तान

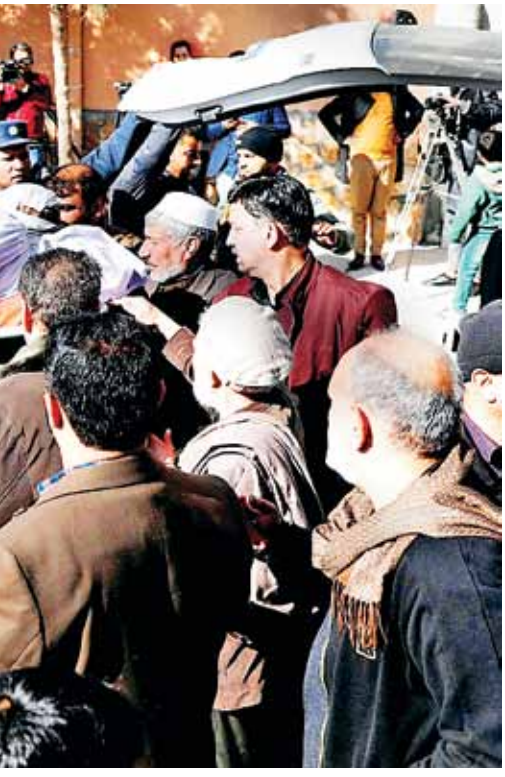

के आतंकवादी ठिकानों पर हमले किये और उसके बाद वहाँ सरकार बनवाने में मदद की, तब अफ़ग़ानिस्तान में 2004 में जो संविधान बना, उसे बनाने में महिलाओं ने अहम योगदान दिया।

अफ़ग़ानिस्तान के अख़बार 'द डेली आउटलुक' ने हाल ही में अपने सम्पदाकीय में लिख है- 'तालिबानी शासन के बाद के संविधान को लोकतांत्रिक मूल्यों और इस्लामी उसूलों, दोनों के आधार पर अनुमोदित किया गया था और इन दोनों के बीच के सामंजस्य को देश-दुनिया ने भी स्वीकार किया। नज़ीर के तौर पर यह संविधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूनिवर्सल डिक्लियरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनी मान्यता देता है। मानवाधिकारों की इस सार्वभौमिक घोषणा के तहत प्रत्येक मनुष्य को वो तमाम अधिकार और स्वतंत्रता हासिल हैं, जिनकी इसमें घोषणा की गयी है और किसी को भी नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक पृष्ठभूमि, सम्पत्ति, जन्म या अन्य किसी हैसियत के आधार पर इनसे वंचित नहीं किया जा सकता।'

मौजूदा संविधान में लैंगिक भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। और संवैधानिक रूप से मर्द और औरत, दोनों को बराबर हक़ हासिल हैं, और ऐसे हक़ बताते हैं कि औरतें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी और फ़ौज व पुलिस सेवा में योगदान की हक़दार हैं। उल्लेखनीय है कि इस मुल्क के मौजूदा संविधान के अनुच्छेद-83 में संसद के निचले सदन में महिलाओं के लिए 27 फ़ीसदी तथा ऊपरी सदन के लिए 50 फ़ीसदी सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। आज यहाँ पर महिलाएँ टैक्सी ड्राइवर हैं, टीवी एंकर हैं, संसद में हैं, बैंक में भी नज़र आती हैं और न्यायाधीश की कुर्सी पर भी। अपने राष्ट्र को आगे ले जानी वाली प्रगतिशील नीतियों को बनाने वाली समितियों व उन्हें लागू कराने वाले बोर्ड का हिस्सा भी हैं। सन् 2003 में यहाँ प्राइमरी शिक्षा में नामांकित लड़कियों की दर 10 फ़ीसदी से भी कम थी, जो सन् 2017 में यह बढ़कर 33 फ़ीसदी तक पहुँच गयी। यह उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन दर बढ़ रही है। इसी तरह सैंकडरी शिक्षा में यह दर छ: फ़ीसदी से बढ़कर 39 फ़ीसदी तक पहुँच गयी है। 2020 तक अफ़ग़ान सिविल सेवकों में 21 फ़ीसदी महिलाएँ थी, जबकि तालिबान शासन के दौरान यह तादाद लगभग शून्य थी। इस 21 फ़ीसदी में 16 फ़ीसदी महिलाएँ वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर पर अपनी सेवाएँ दे रही हैं। अफ़ग़ान संसद में 27 फ़ीसदी महिलाएँ हैं। सवाल यह है कि जब अफ़ग़ानी अधिकारियों और तालिबान के नुमाइंदों के बीच शान्ति वार्ता का दौर जारी है, तो क्या इस शान्ति वार्ता की मेज पर महिलाओं को हासिल मौजूदा हक़ों को संवैधानिक तौर पर बरक़रार रखने का लिखित ठोस आश्वासन तालिबान से लिया जाएगा? इसके अलावा भविष्य में भी मुल्क की लड़कियों, औरतों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों में उनकी हिस्सेदारी को और मज़बूत करने पर भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा हक़ीक़त यह है कि दोहा में जारी शान्ति-वार्ता में तालिबान अफ़ग़ानी औरतों के हक़ों और उनकी स्वतंत्रता के बारे में बात करने से कतरा रहा है।

अफ़ग़ान सरकार की ओर से वार्ता के लिए गठित कमेटी में चार महिलाएँ हैं, लेकिन तालिबान की वार्ता टीम में कोई भी महिला नहीं है। इस बाबत वह ख़ामोश है। पर यह गम्भीर मुद्दा है और इस मुल्क की शिक्षित, जागरूक, सशक्त महिलाएँ उनके अधिकारों को कमज़ोर करने वाली किसी भी शान्ति-वार्ता को मनाने से इन्कार करती हैं। क्योंकि वे ऐसी शान्ति-वार्ता चाहती हैं, जिसमें तालिबान कमज़ोर स्थिति में नज़र आये। वे नहीं चाहतीं कि तालिबान इतना मज़बूत होकर सामने आये कि वह मौजूदा संविधान को फिर से लिखे और महिलाओं को ग़ुलाम बना डाले।

अफ़ग़ानी महिलाएँ इस बात से भी भयभीत हैं कि तालिबान अगर हावी हो गया, तो उनकी ही ज़िन्दगी नहीं, बल्कि छोटी बच्चियों का भविष्य भी तबाह हो जाएगा और वे फिर से यौन तथा शारीरिक शोषण की शिकार होने लगेंगी। आज भी अफ़ग़ानिस्तान के कुछ इलाक़ों में तालिबान का दबदबा है और वहाँ की लड़कियों-औरतों पर कई तरह की पांबदियाँ साफ़ नज़र आती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन ने 20 जनवरी को कार्यभार सँभाला है, वह अफ़ग़ानी महिलाओं को हासिल अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता को बरक़रार रखने के लिए क्या हस्तक्षेप करेंगे? क्या वह कोई रणनीति अपनाएँगे? इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नज़र है। क्या इसका ख़ुलासा 29 फरवरी से पहले हो सकता है? क्योंकि क़रीब 18 महीने की बातचीत के बाद 29 फरवरी, 2020 को अमेरिका व तालिबान के बीच सैन्य समझौता हुआ था, इस 29 फरवरी इसका एक साल पूरा हो जाएगा। यूँ तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का यह फ़र्ज़ बनता है कि वे तालिबान पर इतना दबाव बनाएँ कि उसे यह गारंटी देनी ही पड़े कि वह औरतों पर अपनी मानसिकता, शरिया क़ानून की अपनी व्याख्या नहीं थोपेगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, शायद भविष्य में हो! तहलका

letters@tehelka.com

झारखण्ड में हड़िया-दारू क़ानून अवैध, लेकिन परम्परा में वैध

प्रशांत झा

झारखण्ड में रहने वाले या राज्य के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी रखने वाले सभी लोग हड़िया-दारू शब्द से वाक़िफ़ हैं। क्योंकि राज्य में हड़िया-दारू आम बात है। बड़े-तो-बड़े बच्चे तक इसके बारे में जानते हैं। गाँव-देहात क्या, बीच शहर में भी यह खुलेआम सड़क किनारे बिकती है। दरअसल झारखण्ड में हड़िया-दारू भले ही क़ानून अवैध हो, लेकिन परम्परा में यह वैध है और क़ानून पर परम्परा इतनी भारी है कि इसकी बिक्री को सरकार के लिए रोक पाना आसान नहीं है। इसलिए सरकार क़ानूनी रूप से नहीं, लोगों में जागरूकता फैलाकर इस अभिशाप से मुक्ति का रास्ता अपनाने का प्रयास कर रही है।

हड़िया परम्परा और सांस्कृतिक विरासत

हड़िया आदिवासियों की परम्परा और सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। इसमें चावल के साथ-साथ सात तरह की जड़ी-बूटी मिलायी जाती है। ये जड़ी-बूटी मेडिसनल प्लांट की होती हैं। चावल को पकाने के बाद इसे ठंडा किया जाता है। चावल के अलावा गेहूँ व मडुवा भी मिलाया जाता है। रानू, धतूर समेत अन्य जड़ी-बूटियाँ पीसकर पके हुए चावल में उन्हें मिलाया जाता है। इसके बाद इस पके हुए चावल को किसी बर्तन (ख़ासकर मिट्टी के बर्तन) में तीन-चार दिन किण्वन, एक तरह के ठण्डे ज़मीनी उबाल (फर्मेंटेशन) के लिए रख दिया जाता है। तीन-चार दिन बाद इसमें पानी मिलाकर हड़िया-दारू तैयार की जाती है।

आदिवासी समाज के लिए आम पेय पदार्थ

राज्य के आदिवासी समाज में हड़िया-दारू को एक अच्छा पेय पदार्थ माना जाता है। आदिवासियों ने इसके मूल रूप में पोषण का ध्यान रखा है। आदिवासी समाज और हड़िया व महुआ पर रिसर्च करने वाली राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य वासवी किड़ो कहती हैं कि पारम्परिक रूप से जो हड़िया तैयार की जाती है, वह स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। इसमें जिस रानू को मिलाया जाता है, उसमें हाई कैलोरी होती है। साथ ही यह प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। किड़ो ने कहा असल में आदिवासियों का यह ख़ास पेय रोज़मर्रा की ज़रूरतों या फिर नशे के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसे ख़ासतौर पर घर में किसी धार्मिक आयोजन के लिए या फिर मेहमानों के लिए बनाया जाता रहा है। खेती या मेहनत का काम करने वालों के बल, ख़ासकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हड़िया, जिसे कुछ लोग हड़िया-दारू भी कहते हैं; दी जाती रही है। यह पीलिया, डायरिया, ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन जैसी कई बीमारियों को ठीक करती है।

विकृत होकर जुड़ गया दारू शब्द

राज्य में आम बोलचाल की भाषा में हड़िया के साथ दारू शब्द जुड़ गया है। लेकिन हड़िया अलग और दारू अलग शब्द है। आदिवासी परम्परा में केवल हड़िया शब्द ही है। इसमें दारू शब्द इसलिए

भी जुड़ गया, क्योंकि अब में हड़िया का उपयोग नशे के लिए भी होने लगा है। इसे व्यावसायिक रूप देने के लिए जड़ी-बूटी की जगह स्प्रीट, यूरिया व अन्य नशे का सामान मिलाया जाने लगा। इसके अलावा नशे के लिए अधिक मात्रा में धतूर व अन्य जंगली फल-फूल का इस्तेमाल होने लगा और जड़ी-बूटी की मात्रा कम होती गई। तब इस शब्द के साथ दारू जुड़ गया। अब हड़िया-दारू शब्द प्रचलन में आ गया है।

महिलाओं के लिए रोज़गार का ज़रिया

हड़िया-दारू का प्रयोग जब नशे के लिए होने

हड़िया और दारू अलग-अलग शब्द हैं। पारम्परिक हड़िया स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। साथ ही जड़ी-बूटी और महुआ के जो बाई प्रोडक्ट है, वह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसने धीरे-धीरे विकृत रूप ले लिया है। हड़िया-दारू के साथ महुआ की अवैध बिक्री रुकनी चाहिए। सरकार को इसके विकृत रूप को समाप्त कर वैध बनाना चाहिए। इसके बाई प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए। इसका बाई प्रोडक्ट काफ़ी लाभदायक साबित होगा। महिलाओं को रोज़गार से जोड़कर ही इस पर क़ाबू पाया जा सकता है।

वासवी किड़ो

आदिवासी मामलों की जानकार व पूर्व सदस्य, राज्य महिला आयोग

राज्य में हड़िया-दारू अवैध है। इसका बड़े पैमाने पर जहाँ भी निर्माण होता है, विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। राज्य में समय-समय पर छापा मारा जाता। बड़ी मात्रा में अवैध रूप से चल रहे हड़िया-दारू को नष्ट किया जाता है। क्योंकि यह परम्परा में शामिल है, इसलिए छोटे-छोटे स्तर पर कार्रवाई सम्भव नहीं है। इसके लिए सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं को हड़िया-दारू बेचना छोड़कर दूसरे रोज़गार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार उन्हें दूसरा रोज़गार शुरू करने में भी मदद कर रही है।

विनय कुमार चौबे

सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड

लगा, तो इसने एक व्यावसायिक रूप ले लिया। राज्य में लोग अवैध रूप से विभिन्न जगहों पर बड़े पैमाने पर इसे बनाने लगे। धीरे-धीरे अनेक ग़रीब महिलाएँ अपना परिवार चलाने के लिए इस व्यवसाय से जुड़ गयीं। रोज़गार के लिए छोटे-छोटे स्तर पर हड़िया तैयार करने लगी।

महिलाएँ ही इस पेशे से ज़्यादा जुड़ी हैं और राज्य में खुले रूप से ज़्यादातर जगहों पर हड़िया-दारू महिलाएँ ही इसे बेचती हुई नज़र आती हैं। वे छोटे स्तर पर थोड़ा पारम्परिक और थोड़ा नया स्वरूप देकर अपने ही घर में हड़िया तैयार कर बेचती हैं। हड़िया बेचने वाली एक महिला ने बताया कि एक गिलास हड़िया 10 रुपये में बिकता है। एक दिन में दो-तीन सौ रुपये की कमायी हो जाती है। इससे घर का ख़र्च चलता है। बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। महिला ने कहा यह काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूसरा काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर दूसरा रोज़गार मिल जाए, तो इस काम को छोड़ दूँ।

हड़िया-दारू के ख़िलाफ़ महिलाओं ने ही छेड़ी जंग

राज्य में हड़िया के साथ-साथ महुआ का भी प्रचलन धीरे-धीरे बढ़ गया। हड़िया और महुआ को विकृत रूप देकर बड़े पैमाने पर इसे व्यवसायिक रूप देकर बेचा जाने लगा। इससे ग़रीब परिवार बर्बाद होने लगे। तब राज्य के कई गाँवों की महिलाएँ जागरूक हुईं और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करने लगी हैं। राज्य के कई हिस्सों में महिलाओं ने ही हड़िया-दारू के ख़िलाफ़ जंग छेड़ रखी है, जिसमें कई स्वयं सेवी संगठन भी मदद कर रहे हैं। महिलाएँ हड़िया-दारू को नष्ट करती हैं।

इसी क्रम में रांची से सटे एक गाँव आरा-केरम पूरी तरह से नशा मुक्त गाँव बन गया है। इस गाँव की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने मन की बात कार्यक्रम में भी की थी।

महिलाओं को रोज़गार से जोड़ रही सरकार

राज्य सरकार जानती है कि हड़िया-दारू को क़ानूनी रूप से दबाकर बन्द नहीं किया सकता है। नतीजतन सरकार हड़िया-दारू की ख़ामियाँ बताकर, महिलाओं को रोज़गार देकर इससे मुक्ति का रास्ता तलाश रही है। सरकार ने हाल में तीन योजनाएँ शुरू की हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हमारी माँएँ-बहनें सड़कों पर हड़िया-दारू नहीं बेचेंगी। इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसी के मद्देनज़र सरकार ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान (आशा) और पलाश ब्रांड के ज़रिये ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किये हैं। तहलका

letters@tehelka.com

अब बंफर लगे वाहनों का कटेगा मोटा चालान

उत्तर प्रदेश में जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों के चालान काटे जाने के बाद अब उन वाहन मालिकों पर भी भारी जुर्माना लगेगा, जिनके वाहनों में बंफर / क्रैश गार्ड / बुल बार लगे होंगे

सुनील कुमार

अब उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस उन वाहनों के भी बंपर तरीक़े से चालान काटेगी, जिन वाहनों में बंफर लगे होंगे। जी हाँ, यह हिदायत अपने वाहनों में क्रैश गार्ड अथवा बुल बार अथवा बंफर लगवाकर चलने वालों के लिए है। क्योंकि अब ऐसा करने पर एक-दो हज़ार नहीं, बल्कि पूरे 5,000 रुपये तक का चालान कट सकता है। उत्तर परिवहन सूत्रों की मानें तो यह नियम 01 फरवरी, 2021 से लागू हो गया है। नये फ़रमान में कहा गया है कि अगर 31 जनवरी के बाद वाहनों में बंफर अथवा क्रैश गार्ड अथवा बुल बार लगे मिले, तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इस बारे में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने एक बयान जारी करके नया आदेश जारी किया है। यह आदेश प्रदेश के सभी सहायक और संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि लोग 31 जनवरी, 2021 तक हर हाल में वाहनों के आगे लगे बंफर हटवा लें अन्यथा गाड़ी मालिकों को काफ़ी दिक़्क़त होगी; क्योंकि इसके बाद अगर वाहनों में बंफर लगे मिले, तो सख़्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन आयुक्त ने मोटरयान अधिनियम की धारा-52 का हवाला देते हुए विभागीय आदेश में कहा है कि वाहनों में बंफर लगाना अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे दुर्घटना के वक़्त जान-माल का गम्भीर नुक़सान होता है। इसलिए वाहनों में बंफर लगवाना पूरी तरह परिवहन नियमों के ख़िलाफ़ है।

युवाओं में शौक़ बन चुका है बंफर लगवाना

पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ साल से युवाओं में बंफर लगावाने का शौक़ पनप चुका है। अधिकतर युवा अपने वाहनों, ख़ासकर बड़े वाहनों में बाद में भारी से भारी बंफर लगवाने के शौक़ीन हो चुके हैं। कुछ युवा अपने को ताक़तवर और रॉयल दिखाने के लिए वाहनों में बंफर लगवाते हैं। जितना भारी दिखने का शौक़, जितना भारी बंफर। लेकिन यह शौक़ केवल युवाओं में ही नहीं है, दिन-रात सड़कों पर चलने वाले वाहनों, ख़ासकर जीप, थ्री-व्हीलर, और दूसरे यात्री वाहनों में बंफर आमतौर पर दिख जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूँ जैसे लगभग सभी छोटे-बड़े शहरों में बंफर लगे वाहन आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। ये बंफर सवारी और माल ढोने वाले वाहनों में तो जैसे आम हो चले हैं। आमतौर पर बंफर और क्रैश गार्ड वाहनों में बाद में वाहनों की सजावट, एसेसीरीज और रिपेरिंग वाली दुकानों पर लगाये जाते हैं।

पहले भी दी जा चुकी है चेतावनी

उत्तर प्रदेश में वाहनों में क्रैश गार्ड और बंफर हटाने को लेकर पहले भी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कई बार चेतावनी जारी कर चुका है। विभाग ने पहले इस पर अंकुश लगाने को लेकर ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई भी की है; लेकिन आज तक इस पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है। मगर अब माना जा रहा है कि इस बार परिवहन विभाग कड़ी कार्रवाई के मूड में है। क्योंकि इस बार जुर्माने की राशि पहले की अपेक्षा बहुत भारी है और जब ट्रैफिक पुलिस पर भारी जुर्माना वसूलने का दबाव ऊपर से होता है, तो चालान काटने के लिए पुलिस और भी ख़ूब सक्रिय हो जाती है। देखना यह है कि वाहन मालिकों से पहले से ही तरह-तरह से भारी जुर्माना वसूल चुका उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अब बंफर के नाम पर कितनी बंपर कमायी करता है? क्योंकि पहले भी कई बार जारी हो चुके ऐसे आदेशों से रिकॉर्ड वसूली तो नहीं हुई, जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब 10 में से 6-7 वाहनों में बंफर लगे मिल जाते हैं, जो कि परिवहन विभाग की तरफ़ से ठोस पहल न करने का नतीजा ही लगता है। अगर बंफर, क्रैश गार्ड और बुल बार लगाने वाले बाज़ारों में जाकर देखें, तो यह धन्धा ख़ूब फल-फूल रहा है। इस धन्धे के फलने-फूलने की एक वजह यह भी है कि इस धन्धे में लगे लोगों को किसी तरह का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है।

जातिसूचक शब्द लिखने पर भी कट रहे चालान

पिछले ही साल दिसंबर में वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखने पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये थे। इसे जातिवाद को ख़त्म करने की बड़ी पहल के रूप में देखा गया। इस मामले में महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आईजीआरएस पर एक शिकायत लिखते हुए वाहनों पर से जातिसूचक शब्दों को हटवाने की अपील की थी। ख़ासतौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की नंबर प्लेटों पर जातिसूचक शब्द लिखे होने की शिकायत करते हुए कहा था कि इससे समाज को बड़ा ख़तरा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों के चालान काटने का आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को दिया और अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) ने नंबर प्लेटों पर जाति लिखाने वाले वाहनों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाकर वाहन मालिकों से जुर्माना वसूलने के आदेश जारी कर दिये। इस मुहिम के अंतर्गत जातिसूचक शब्द लिखाने वालों के पकड़े जाने पर उनके ख़िलाफ़ धारा-177 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे वाहनों पर पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। हालाँकि अब भी ऐसे वाहन नज़र आ ही जाते हैं, जिन पर जातिसूचक शब्द लिखे होते हैं; लेकिन फिर भी बहुत-से लोगों ने जाति लिखी नंबर प्लेटों को या तो हटवाकर उनकी जगह दूसरी प्लेट लगवा ली है या फिर जातिसूचक शब्दों को ही हटा लिया है। इस मुहिम के साथ-साथ परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट के ग़लत साइज, प्लेट पर नंबर न होने और नंबरों की आड़ी-तिरछी या छोटी या दिखायी न देने वाली लिखावट को लेकर भी चालान काटने शुरू कर दिये हैं। इस मुहिम से काफ़ी सुधार हो रहा है।

पहले से काटे जा रहे चालानों पर जुर्माने की राशि

बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग पहले से ही कई कमियों को लेकर वाहनों के चालान करवा रहा है। ये चालान वाहनों में पायी जाने वाली हर कमी और ड्राइविंग के ग़लत तरीक़ों को लेकर किये जा रहे हैं। सभी तरह के चालानों की जुर्माना राशि भी अलग-अलग है। इनमें ज़्यादातर नियमों में फेरबदल करके पिछले साल ही उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली के तहत जुर्माने की राशि बढ़ाई गयी है। इसके तहत राज्य में दो पहिया और चार पहिया वाहनों को चलाते समय मोबाइल पर बात करने से लेकर हेलमेट के न होने तक पर चालान है। नये आदेश में चालान को दो रूपों में लागू किया गया था, पहली बार में कम जुर्माना और दूसरी बार में अधिक जुर्माना। लेकिन पहली बार में ही काफ़ी मोटा चालान कटने और दोबारा में और भारी-भरकम चालान कटने का प्रावधान है। मसलन वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार में 1,000 रुपये का चालान और दोबारा या उसके बाद हर बार मोबाइल पर बात करते पाये जाने पर 10,000 रुपये तक का चालान काटे जाने की मुहिम चल रही है।

इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस में ग़लत जानकारी देने पर भी 10 हज़ार रुपये तक का चालान भरना होगा। बिना हेलमेट पहले वाहन चलाने पर 1,000 रुपये का चालान कट रहा है। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार में 1,500 रुपये का चालान होगा। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी रोकने या इनके रास्ते में अड़चन डालने पर 10,000 रुपये का चालान होगा। वहीं बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक को 5,000 रुपये का चालान भरना होगा। सीट बेल्ट न बाँधने पर 1,000 रुपये का चालान और ट्रैफिक अधिकारी की बात न मानने पर या उसके काम में बाधा डालने पर 2,000 रुपये का चालान भरना होगा। इसी तरह तेज़ गति वाहन चालकों को भी भारी जुर्माना देना होगा, इसमें कार वालों को 2,000 रुपये और कॉमर्शियल वाहन वालों को 4,000 रुपये का चालान भरना होगा। इसी तरह दो पहिया वाहनों पर तीन या इससे अधिक सवारी होने पर 1,000 रुपये का चालान भरने का प्रावधान हो चुका है।

नहीं सुधर रहे लोग

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा भारी जुर्माना वसूले जाने पर भी सुधार हो रहा है, पर उतना नहीं। यहाँ की सड़कों पर बहुत-से लोग नियमों का उल्लंघन करते दिख जाते हैं। क्योंकि परिवहन अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस के जवान हर जगह तो खड़े होते नहीं हैं। ऐसे में लोग अपनी मनमानी ख़ूब करते हैं और जहाँ भी कोई अधिकारी या पुलिस वाला नज़र आता है, वहाँ नियमों का पालन कर लेते हैं। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान रघुवीर ने बताया कि सभी नियम लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाये जाते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। जब लोग नियमों का पालन नहीं करते, तब सरकार को मजबूरन चालान का डर दिखाना पड़ता है; ताकि उनमें सुधार हो सके और सड़कों पर दुर्घटना न हो। तहलका

letters@tehelka.com

वक़्त के निशान

हुमरा क़ुरैशी

लेखक वेद मेहता के निधन के साथ, मैं केवल यह कह सकती हूँ कि हमने एक महान् लेखक ही नहीं, बल्कि एक दृढ़ व्यक्तित्व वाले इंसान को भी खो दिया है। मैं उनसे दो बार मिली थी और सन् 2009 की शरद ऋतु के दौरान एक बार उनका साक्षात्कार किया था; जब वह अपनी पत्नी लिन कैरी (19वीं सदी के अमेरिकी लेखक जेम्स फेनिमोर कूपर के वंशज के साथ) नई दिल्ली आये थे।

वह न केवल एक स्पष्टवादी के रूप में सामने आये बल्कि अपने विचारों में भी वे बहुत साफ़ थे। हालाँकि एक मेनिन्जाइटिस अटैक ने उन्हें 4 साल की उम्र में नेत्रहीन बना दिया था, फिर भी वह बहुत आत्मविश्वास से भरे थे, जीवन से भरपूर। उल्लेखनीय रूप से, अपनी दृष्टिहीनता को उन्होंने अपने लेखन के आड़े नहीं आने दिया। कई बड़ी और लघु कहानियों के साथ 30 से अधिक पुस्तकों के लेखक थे और इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि यह सब उन्होंने तीन दशकों, 1961 से 1994, के बीच किया। वह 'द न्यू योर्कर' में एक स्टाफ लेखक थे।

इन सबसे ऊपर, उन्होंने जीवन तो पूरी तरह से जिया। उनके पेशेवर जीवन के असाधारण आदान-प्रदान के साथ, उनकी अपरम्परागत और रंगीन जीवन शैली में पर्याप्त दिलचस्प मोड़ थे; निश्चित रूप से जब उन्होंने बसने का फ़ैसला किया। सन् 1983 में 49 वर्ष की आयु में विवाह, जैसा कि अरस्तू के दर्शन में है कि शादी में प्रसन्न रहने के लिए एक व्यक्ति को अवश्य ही अपने से कहीं युवा महिला से शादी करनी चाहिए।

मेरे साथ साक्षात्कार के दौरान उन्होंने विस्तार से कहा- 'जब मैं 49 साल का था, तब मैंने शादी की। और लिन मुझसे लगभग 20 साल छोटी हैं। वास्तव में लिन एक दोस्त की भतीजी हैं और मैं उनसे पहली बार तब मिला था, जब वह 11 साल की थीं। और कुछ साल बाद मैं उन्हें फिर से एक पार्टी में मिला। उस समय मैं नशे में था और उन्हें चूम लिया था। अगली सुबह मैंने उन्हें एक माफ़ीनामा भेजा, जिसके जवाब में उन्होंने मुझसे कहा कि यह उनकी तरफ़ से मेरी भावनाएँ थीं। फिर हमने शादी करने का फ़ैसला किया और सन् 1983 में शादी कर ली। आज वह मेरी इकलौती पत्नी हैं और हमारी दो बेटियाँ हैं।'

उन्होंने इस तथ्य पर ज़ोर दिया था कि हमारे ऐतिहासिक अतीत का ज्ञान बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसे उद्धृत करने के लिए मुझे लगता है कि हमारा इतिहास आज की पीढ़ी के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। जो लोग इतिहास के बिना रहते हैं, वे जानवरों से बेहतर नहीं हैं। इतिहास महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि यह जीवन में एक आयाम जोड़ता है, जैसे बच्चे और पत्नी एक व्यक्ति के जीवन में अतिरिक्त आयाम जोड़ते हैं।

हालाँकि वह अमेरिका में बसे थे। वह अफ़ग़ानिस्तान और उसके बाहर अमेरिका की घुसपैठ के सख़्त विरोधी थे। ख़ुद उनके शब्दों में- 'अमेरिका को अफ़ग़ानिस्तान से बाहर निकलना चाहिए। और ईराक एक बड़ी आपदा थी, पूरी तरह से एक तरह की कल्पना; वैसे ही जैसी अमेरिका से वियतनाम और कोरिया में हुई थी। मैं अहिंसा और सहनशीलता की नीति के साथ हूँ। और मेरा मानना है कि अरस्तू के दर्शन (लोकतंत्र) में आप केवल तभी लोकतांत्रिक कहला सकते हैं, जब बहुसंख्यक आबादी मध्यम वर्ग की हो।'

वेद मेहता भारत में दक्षिणपंथ के सत्ता में आने से भी बेहद आशंकित थे। उन्हें इस बात की चिन्ता थी कि समुदायों के बीच विभाजन और साम्प्रदायिक बदलाव लाये जाएँगे, और यह अपने आप में इस देश की जनता के लिए आपदाओं को बढ़ायेगा।

कहाँ हैं बॉलीवुड सितारे

कहाँ हैं वो बॉलीवुड सितारे और तारिकाएँ,

जिन्होंने फ़िल्मों में किसानों की भूमिका निभायी! मुझे लगता है, वे महज़ एक चित्रण कर रहे थे; परी कथा जैसे चरित्र के साथ। उनके साथ हरे-भरे खेतों और घास के मैदानों और जंगलों में और आसपास गाते और नाचते हुए; भले विभिन्न धाराओं और नदियों और गाँव के तालाबों में नहाते हुए नहीं!

मेरा तर्क सरल और सीधा है। चूँकि उन अनगिनत फ़िल्मी क़िरदारों को उनकी किसान भूमिकाओं के कारण लोकप्रियता हासिल हुई, इसलिए उन्हें आज के किसानों और उनकी दुर्दशा पर एक-दो शब्द कहने चाहिए। अगर गाँव के इलाक़ों में गाकर और नाचकर मनोज कुमारों और दिलीप कुमारों की पसन्द उनके ग्राफ को ऊपर ले जा सकती है, तो यह समय किसानों के साथ एकजुटता क़ायम करने का है। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति उन्हें प्रदर्शन करने वाले किसानों तक पूरी शिद्दत के साथ जाने की अनुमति न दे; लेकिन उनके परिवार निश्चित रूप से ऐसा कर सकते थे।

वास्तव में यह निराशाजनक से अधिक है कि बॉलीवुड के जाने-माने पुरुषों और महिलाओं में से कोई भी आगे नहीं आया है और बोल रहा है। क्यों? क्या ऐसा इसलिए है? क्योंकि उनके पास बहुत कम समय या कोई निश्चित वैचारिक झुकाव है या वे वर्तमान राजनीतिक शासकों और उनके नियंत्रण में मशीनरी की प्रतिक्रियाओं को लेकर चिन्तित हैं।

मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि सन् 2002 के गुजरात दंगों के चेहरों के ख़िलाफ़ हममें से कई लोगों ने बात की थी; लेकिन बॉलीवुड ने तब भी निराश किया था। कुछ लोगों ने हत्याओं और नरसंहार के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत दिखायी। लेकिन गुजरात के राजनीतिक शासकों पर बॉलीवुड के बड़े नाम और बैनर क्यों ख़ामोश रहे। उनका जवाब कुछ इतना चौंकाने वाला था- 'अगर हम आन्दोलन में जान गँवाने वालों या उस हालत में पहुँचने वालों के क़रीब पहुँच गये होते, तो हम सरकार की कुदृष्टि में आ जाते और हमारी फ़िल्में निशाना बन जातीं, और इसके साथ ही हम बर्बाद हो गये होते। सच में? नतीजे का इतना ख़ौफ़!'

और अब जबकि बॉलीवुड, करीना-सैफ़ अली ख़ान के दूसरे बच्चे के जन्म की ख़बर सुनने का इंतज़ार कर रहा है कि वे नये बच्चे को क्या नाम देते हैं? आश्चर्यजनक है। करीना और सैफ़ अली ख़ान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। तब बहुत हल्के दर्जे की टिप्पणियाँ की गयी थीं। इनमें से बहुत-सी हिन्दु संगठनों की तरफ़ से।

वास्तव में किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि तैमूर के नाम से जुड़ा एक और आयाम है, एक विजेता का। सन् 1398 में उत्तर भारत में तैमूर के आक्रमण के बाद 1,700 से अधिक लकड़ी नक्काश, वास्तुकार, हस्तलिपि लेखक और अत्यधिक-विशिष्ट रसोइयों (वाज) ने समरकंद से कश्मीर की तरफ़ पलायन कर दिया था। आज भी कश्मीर घाटी में वाज परिवारों का एक बड़ा हिस्सा समरकंद में अपनी उत्पत्ति की बात करता है और इनकी वाजवान दावतों में बहुत माँग है। इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए कि दावतों की दावत कश्मीर के दोनों प्रमुख समुदायों, कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलामनों द्वारा की जाती हैं।

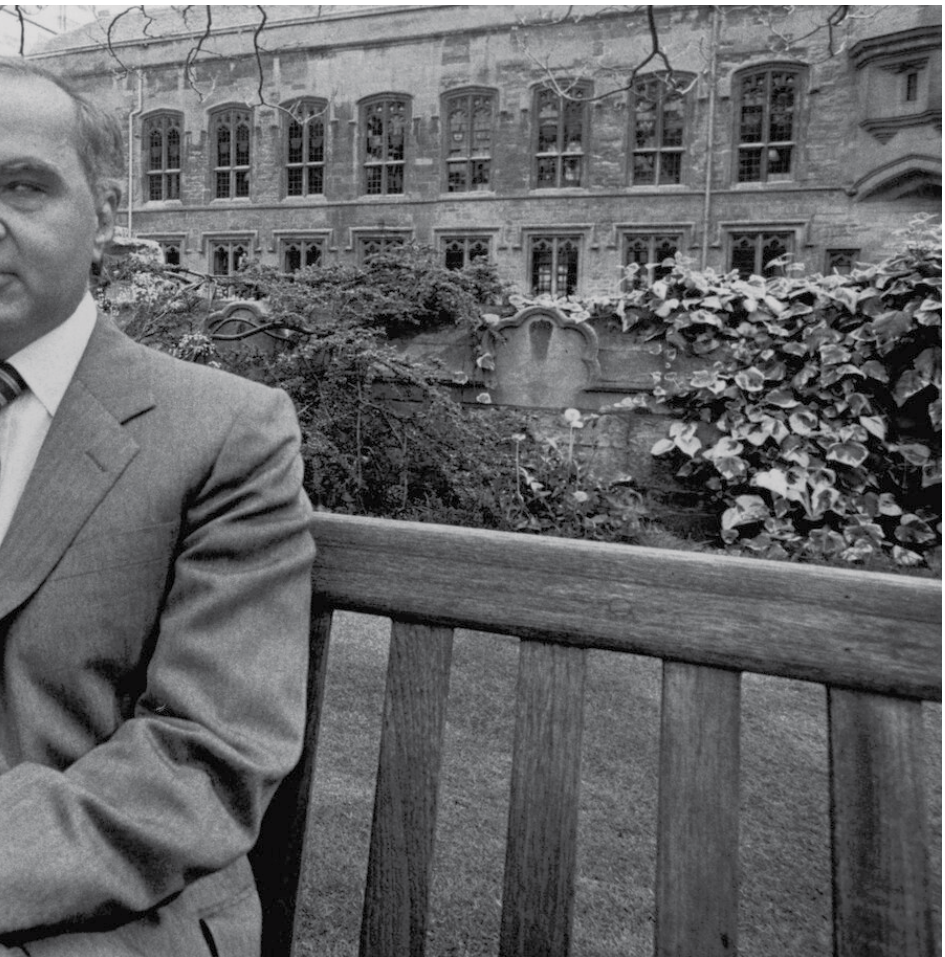

शहरयार की नौवीं बरसी पर

शायर, गीतकार, लेखक शहरयार की अगली पुण्यतिथि (उनका निधन 13 फरवरी, 2012 को हुआ था) पर मैं उनके कोई कविता में नहीं डाल रही हूँ। हालाँकि उमराव जान और गमन में उनके गीत सदाबहार हैं।

हाँ, उनकी कविता के बजाय मैं उनके अवलोकन, सह-हास्य की भावना को उजागर कर रही हूँ...। वह मेरे पिता के पैतृक क़स्बे आँवला (उत्तर प्रदेश) से थे और वह जानते थे कि मेरी छोटी बहन, हबीबा, अलीगढ़ में बस गयी थी। उनके आँवला और अलीगढ़ कनेक्शन के बारे में मुझे तब पता चला, जब मैं पहली बार लगभग दो दशक पहले उनसे मिली थी। एक कॉमन मित्र ने हमें इस विभूति से परिचित कराया- 'वह हबीबा की बहन हैं।'

इस पर उनकी प्रतिक्रिया थी- 'आप हबीबा की बहन!'

'हाँ, मैं हूँ..., वह मेरी छोटी बहन है।'

लेकिन आप अलग दिखती हैं! बहुत अलग! आप दो सगी बहनें हैं! वह अपने सिर को ढककर रखती है; लेकिन आप...!' इसके साथ ही उन्होंने मेरी स्लीव-लेस शर्ट की तरफ़ लगभग अस्वीकार्य निगाह डाली।

'हाँ, हम सगी बहनें हैं।'

'एक ही पिता से?'

'हाँ, बिल्कुल।'

'एक ही पिता?'

'हाँ, हाँ।'

'एक ही पिता!'

'कम-से-कम अम्मा ने तो हमें यही बताया है!'

इसके साथ ही हम दिल खोलकर हँसे...। तहलका

letters@tehelka.com

चींटी के बराबर भी नहीं हमारी हैसियत

पंडित प्रेम बरेलवी

बचपन में कबूतरों और आखेटक यानी शिकारी की कहानी पढ़ी थी। अपनी चतुराई और चूहे की मित्रता के दम पर कबूतर न केवल ख़ुद आज़ाद हो गये, बल्कि आखेटक का जाल भी ले उड़े। आज हम इंसान आपस में इतने बिखर गये हैं कि एक-एक करके आखेटकों के जाल में फँसते जा रहे हैं और आखेट होते जा रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि हम एक-दूसरे के फँसने और फड़फड़ाने पर ख़ुश हैं और उछल रहे हैं। हम ख़ुश इस बात पर भी हैं कि फँसने वाले दूसरे- हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसियन हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, फलाँ हैं-फलाँ हैं। सच तो यह है कि हम सब कुछ हैं, लेकिन इंसान नहीं हैं। क्योंकि हममें एकता नहीं है। अगर कोई ईमानदारी और सच की बात कह दे, तो उसके लाखों दुश्मन! किसी दूसरे मज़हब को मानने वालों से ही नहीं, बल्कि अपने ही मज़हब के मानने वालों से भी। हैरत की बात है न! पहले हम दूसरे मज़हब वालों से लड़ें और अगर कोई यह कह दे कि यह ग़लत है, हमें मज़हबी होने की बजाय इंसान होना चाहिए, तो अपने ही मज़हब वाले को भी दुश्मन साबित कर दें और उसका जीना हराम कर दें कि आख़िर उसने अख़लाक़ और मोहब्बत की बात की कैसे?

क्या अजीब क़िस्म है हम इंसानों की? हम सच का ढिंढोरा तो पीटते फिरते हैं, लेकिन हममें से अधिकतर को सच हज़म नहीं होता। शायद हम सब अपने झूठ को सच साबित करने की होड़ कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा सामना सच से होता है, हम तिलमिला उठते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बिगड़ी औलाद को माँ-बाप सुधरने के लिए कह दें, तो उसे बेहद बुरा लगता है।

आज ईश्वर भी हम इंसानों को देखता होगा, तो सोचता होगा कि काश उसने हम इंसानों को भी जानवर ही रखा होता। सच ही है! कम-से-कम जानवरों ने अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति तो नहीं खोयी है। हम तो दिमाग़दार हैं, अक़्लमंद हैं, पढ़े-लिखे हैं; तो पढ़-लिखकर हमने आख़िर हासिल किया भी क्या है? हमने अपने-अपने अस्तित्व को बचाने के लिए न केवल पृथ्वी के समस्त प्राणियों को, वरन् ख़ुद को भी संकट में डाल रखा है। इसकी जगह अगर हमने सम्पूर्ण मानव जाति के साथ-साथ पृथ्वी के समस्त जीवों की रक्षा की होती, तो शायद आज हम कहीं ज़्यादा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध होते। कह सकते हैं कि हमने पढ़-लिखकर ख़ुद को इतना आधुनिक बना डाला है कि हम एक-दूसरे के अस्तित्व को नकारने लगे हैं। और ख़ुद को इतना बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं कि कई बार तो ईश्वर को भी छोटा सिद्ध करने की भूल कर बैठते हैं। सच तो यह है कि बड़ा बनने के चक्कर में हमारी हालत उस पागल या शराबी जैसी हो चुकी है, जिसके जिस्म में जान नहीं है; लेकिन वह अपने जुनून में किसी को भी नहीं गिनता है।

कभी छोटा बनकर देखिए। कभी दूसरों में ज्ञान की खोज करके देखिए। दूसरों को समझाने से पहले ख़ुद इस बात को भली-भाँति समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व एक चींटी के बराबर भी नहीं। और अगर फिर भी भरोसा न हो और अपने ज्ञान तथा बल पर घमण्ड हो, तो समुद्र को देखिए, उसकी लहरों के भयंकर शोर को सुनिए; आकाश की ऊँचाई को देखिए, उसमें रूई के फाये की तरह उड़ रहे बादलों की गर्जना को सुनिए; कड़कड़ाती बिजली की ज़मीन पर उतरती भयंकर चमक को देखिए; हिमालय की उलटती-पलटती, मौत की तरह तांडव करती कंदराओं को देखिए; ज़मीन के अन्दर की गहराई को देखिए; आग की प्रचण्डता को महसूस कीजिए और वायु के वेग का आभास कीजिए। आपको आपकी तुच्छता का अहसास स्वत: ही हो जाएगा। फिर सोचिए कि ईश्वर ने इतनी भयंकर ताक़तों के बीच हम सबको एक ही तरह का जीवन दिया है। वही पैदा होने की प्रक्रिया, वही साँस लेने का तरीक़ा, वही खाने का तरीक़ा, वही जीने का तरीक़ा और अन्त में मर जाने की मजबूरी। सभी को बराबर हवा, बराबर पानी, बराबर जीने का अधिकार और एक ही तरह से देखने, सुनने, सूँघने तथा, महसूस करने की क्षमता दी है। एक ही तरह का शरीर और रक्त दिया है। तब भी हम यह क्यों नहीं मानते कि हम सबका ईश्वर एक है और वह हम सबका परम् पिता है। फिर हमारे मज़हब अलग-अलग कैसे हुए? हम सब एक-दूसरे से जुदा कैसे हुए? हम एक-दूसरे के दुश्मन कैसे हुए? क्यों हमने मज़हब और ज़ात-पात की दीवारें खड़ी कर ली हैं एक-दूसरे के दरमियान? क्यों हम पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं? क्यों हम उन्हीं धर्म-ग्रन्थों की बात नहीं मानते, जिनके लिए हम आपस में लड़-मर जाते हैं। हम सबको मरकर उसी ईश्वर के दरबार में जाना है, जिसके लिए हम सब आपस में लड़ रहे हैं। उसी ईश्वर को भाषाओं के अन्तर और बदले हुए नामों के चलते गालियाँ दे रहे हैं! कैसे मूर्ख हैं हम? इतनी बड़ी मूर्खता तो पशु भी नहीं करते। हैरत होती है कि हम उस ईश्वर की रक्षा का दम्भ भरते हैं, जिसने हम जैसे अरबों जीवन्त प्राणियों को जन्म दिया है और उसी की मर्ज़ी से, उसी के रहम-ओ-क़रम पर सब ज़िन्दा हैं। हैरत होती है कि हम प्यार बाँटने या प्यार करने वालों को अपराधी मान लेते हैं, उन्हें सज़ा देने तक से नहीं झिझकते; जबकि अपराधियों के पैरों में दण्डवत् हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे अपने बच्चे भी अब हमारा सम्मान नहीं करते। हमने संस्कार खो दिये हैं और अपने बच्चों को भी वाहियात बनाते जा रहे हैं। ऐसे में हमारी यह अपेक्षा कि हमारे बच्चे हमारी इज़्ज़त करें; बेईमानी नहीं, तो और क्या है? क्या अपने ही बच्चों को संस्कारहीन बनाकर हम उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? क्या यह हमारा अक्षम्य अपराध नहीं है? क्या ऐसा करके हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को ख़ुशहाल जीवन दे पाएँगे? इन सवालों का जवाब अपने ही अन्दर खोजना। शायद आपको जवाब मिल जाए। तहलका

letters@tehelka.com

TEHELKA FOUNDERS
Aamir Husain Khan
Abbas Ali Baig & Vinu
Abhay Yograj
Action Aid India Society
Adittya Oomman
Aditya Vinayak Patwardhan
Aga Publications Ltd
Alefiya Shabbir Khorakiwala
Alyque Padamsee
Amal Ganguli
Anil Agarwal
Anil Nayar
Anil Wanvari
Anirudh Gupta
Anju And Abhijit
Anuroop Singh
Arif Mohd Khan
Arindam Chaudhuri
Arnab Basu
Arvind K. Singhania
Asha Sarabhai
Ashish Goel
Ashok Jaipuria
Ashok Sachdev
Ashok Sharma
Ashwani Khurana
Aslam Qader Khan
Av Anoop
Beena And Kishu
Benny Thomas
Bill Emmott
Bindiya Jain
Bunty Pasricha
C Anand David (Man Ford Allianz Pvt. Ltd.)
Ccl Productsindia
Chandni Parekh
Chinmay S Patel
Ck Ranganathan
Collin Benjamin
Color Chips India Ltd
Consumer Guidance Center
Crishna Smita Godrej
Cyrus Guzder
D Surendra Babu
D.Baskar & D.Nirmal
Daniel Lak
Deepak Kapur
Dilip D'souza
Dr K Shashidhar
Dr. Kt Lalwani
Dr. Pradhap C Reddy
Dr. Ravi
Dr.C.P Sreekumar
Dr.S.P. Vasi Reddi
Eric Johnson
Foundation For Demorcratic Reforms
Gaurav Dalmia
Gaurav Singh
Gautam Berry
Gautam Banerjee
Gl Sultania
H K Chaudhary
H P Barooah (Chairman)
Harsh C Mariwala
Hemant D Naiknavare
Hindal Haidar Tyabji
Indian Tv Dot Com
Indrajeet Singh
Ishaat Hussain
J Mehra
J P Singh
Jaaved Ahmed Jaaferi
Jagdip Singh
Jagdish Chokar
Javed Akhtar
Jay Galla
Jayan Pillai
Jb & Neela D'souza
Jeanne-Marie Verghese
Jerry Pinto
Jit Paul
John Fernandes
John Singh
John Thomas Vechurath
K.N.Memani
K.T.S Tulsi
Kabir Vedi
Karan Paul
Karun Krishna Sanghi
Kiran Beeravelli
Kiran Mazumdar Shaw
Aamir Husain Khan
Abbas Ali Baig & Vinu
Abhay Yograj
Action Aid India Society
Adittya Oomman
Aditya Vinayak Patwardhan
Aga Publications Ltd
Alefiya Shabbir Khorakiwala
Alyque Padamsee
Amal Ganguli
Anil Agarwal
Anil Nayar
Anil Wanvari
Anirudh Gupta
Anju And Abhijit
Anuroop Singh
Arif Mohd Khan
Arindam Chaudhuri
Arnab Basu
Arvind K. Singhania
Asha Sarabhai
Ashish Goel
Ashok Jaipuria
Jeanne-Marie Verghese
Jerry Pinto
Jit Paul
Jo
Daniel Lak
Dilip D'souza
Dr K Shashidhar
Dr. Kt Lalwani
Dr. Pradhap C Reddy
Dr. Ravi
Dr. Surinder Kapur
Dr.C.P Sreekumar
Dr.S.P. Vasi Reddi
Eric Johnson
Foundation For Demorcratic Reforms
Gaurav Dalmia
Gaurav Singh
Gautam Berry
Gautam Banerjee
Gl Sultania
H K Chaudhary
H P Barooah (Chairman)
Harsh C Mariwala
Hemant D Naiknavare
Hindal Haidar Tyabji
Indian Tv Dot Com
Indrajeet Singh
Ishaat Hussain
J Mehra
J P Singh
Jaaved Ahmed Jaaferi
Jagdip Singh
Jagdish Chokar
Javed Akhtar
Jay Galla
Jayan Pillai
Jb & Neela D'souza
Jeanne-Marie Verghese
Jerry Pinto
Jit Paul
Jo
Aamir Husain Khan
Abbas Ali Baig & Vinu
Abhay Yograj
Action Aid India Society
Adittya Oomman
Aditya Vinayak Patwardhan
Aga Publications Ltd
Alefiya Shabbir Khorakiwala
Alyque Padamsee
Amal Ganguli
Anil Agarwal
Anil Nayar
Anil Wanvari
Anirudh Gupta
Anju And Abhijit
Anuroop Singh
Arif Mohd Khan
Arindam Chaudhuri
Arnab Basu
Arvind K. Singhania
Asha Sarabhai
Ashish Goel
Ashok Jaipuria
Ashok Sachdev
Ashok Sharma
Ashwani Khurana
Aslam Qader Khan
Av Anoop
Beena And Kishu
Benny Thomas
Bill Emmott
Bindiya Jain
Bunty Pasricha
C Anand David (Man Ford Allianz Pvt. Ltd.)
Ccl Productsindia
Chandni Parekh
Chinmay S Patel
Ck Ranganathan
Collin Benjamin
Color Chips India Ltd
Consumer Guidance Center
Crishna Smita Godrej
Cyrus Guzder
D Surendra Babu
D.Baskar & D.Nirmal
Daniel Lak
Deepak Kapur
Dilip D'souza
Dr K Shashidhar
Dr. Kt Lalwani
Dr. Pradhap C Reddy
Dr. Ravi
Dr. Surinder Kapur
Dr.C.P Sreekumar
Dr.S.P. Vasi Reddi
Eric Johnson
Foundation For Demorcratic Reforms
Gaurav Dalmia
Gaurav Singh
Gautam Berry
Gautam Banerjee
Gl Sultania
H K Chaudhary
H P Barooah (Chairman)
Harsh C Mariwala
Hemant D Naiknavare
Hindal Haidar Tyabji
Indian Tv Dot Com
Indrajeet Singh
Ishaat Hussain
J Mehra
J P Singh
Jaaved Ahmed Jaaferi
Jagdip Singh
Jagdish Chokar
Javed Akhtar
Jay Galla
Jayan Pillai
Jb & Neela D'souza
Jeanne-Marie Verghese
Jerry Pinto
Jit Paul
Jo
Aamir Husain Khan
Abbas Ali Baig & Vinu
Abhay Yograj
Action Aid India Society
Adittya Oomman
Aditya Vinayak Patwardhan
Aga Publications Ltd
Alefiya Shabbir Khorakiwala
Alyque Padamsee
Amal Ganguli
Anil Agarwal
Anil Nayar
Anil Wanvari
Anirudh Gupta
Anju And Abhijit
Anuroop Singh
Arif Mohd Khan
Arindam Chaudhuri
Arnab Basu
Arvind K. Singhania
Asha Sarabhai
Ashish Goel
Ashok Jaipuria
Ashok Sachdev
Ashok Sharma
Ashwani Khurana
Aslam Qader Khan
Av Anoop
Beena And Kishu
Benny Thomas
Bill Emmott
Bindiya Jain
Bunty Pasricha
C Anand David (Man Ford Allianz Pvt. Ltd.)
Ccl Productsindia
Chandni Parekh
Chinmay S Patel
Ck Ranganathan
Collin Benjamin
Color Chips India Ltd
Consumer Guidance Center
Crishna Smita Godrej
Cyrus Guzder
D Surendra Babu
D.Baskar & D.Nirmal
Daniel Lak
Deepak Kapur
Dilip D'souza
Dr K Shashidhar
Dr. Kt Lalwani
Dr. Pradhap C Reddy
Dr. Ravi
Dr. Surinder Kapur
Dr.C.P Sreekumar
Dr.S.P. Vasi Reddi
Eric Johnson
Foundation For Demorcratic Reforms
Gaurav Dalmia
Gaurav Singh
Gautam Berry
Gautam Banerjee
Gl Sultania
H K Chaudhary
H P Barooah (Chairman)
Harsh C Mariwala
Hemant D Naiknavare
Hindal Haidar Tyabji
Indian Tv Dot Com
Indrajeet Singh
Ishaat Hussain
J Mehra
J P Singh
Jaaved Ahmed Jaaferi
Jagdip Singh
Jagdish Chokar
Javed Akhtar
Jay Galla
Jayan Pillai
Jb & Neela D'souza
Jeanne-Marie Verghese
Jerry Pinto
Jit Paul
Jo
Aamir Husain Khan
Abbas Ali Baig & Vinu
Abhay Yograj
Action Aid India Society
Adittya Oomman
Aditya Vinayak Patwardhan
Aga Publications Ltd
Alefiya Shabbir Khorakiwala
Alyque Padamsee
Amal Ganguli
Anil Agarwal
Anil Nayar
Anil Wanvari
Anirudh Gupta
Anju And Abhijit
Anuroop Singh
Arif Mohd Khan
Arindam Chaudhuri
Arnab Basu
Arvind K. Singhania
Asha Sarabhai
Ashish Goel
Ashok Jaipuria
Ashok Sachdev
Ashok Sharma
Ashwani Khurana
Aslam Qader Khan
Av Anoop
Beena And Kishu
Benny Thomas
Bill Emmott
Bindiya Jain
Bunty Pasricha
C Anand David (Man Ford Allianz Pvt. Ltd.)
Ccl Productsindia
Chandni Parekh
Chinmay S Patel
Ck Ranganathan
Collin Benjamin
Color Chips India Ltd
Consumer Guidance Center
Crishna Smita Godrej
Cyrus Guzder
D Surendra Babu
D.Baskar & D.Nirmal
Daniel Lak
Deepak Kapur
Dilip D'souza
Dr K Shashidhar
Dr. Kt Lalwani
Dr. Pradhap C Reddy
Dr. Ravi
Dr. Surinder Kapur
Dr.C.P Sreekumar
Dr.S.P. Vasi Reddi
Eric Johnson
Foundation For Demorcratic Reforms
Gaurav Dalmia
Gaurav Singh
Gautam Berry
Gautam Banerjee
Gl Sultania
H K Chaudhary
H P Barooah (Chairman)
Harsh C Mariwala
Hemant D Naiknavare
Hindal Haidar Tyabji
Indian Tv Dot Com
Indrajeet Singh
Ishaat Hussain
J Mehra
J P Singh
Jaaved Ahmed Jaaferi
Jagdip Singh
Jagdish Chokar
Javed Akhtar
Jay Galla
Jayan Pillai
Jb & Neela D'souza
Jeanne-Marie Verghese
Jerry Pinto
Jit Paul
Jo
Aamir Husain Khan
Abbas Ali Baig & Vinu
Abhay Yograj
Action Aid India Society
Adittya Oomman
Aditya Vinayak Patwardhan
Aga Publications Ltd
Alefiya Shabbir Khorakiwala
Alyque Padamsee
Amal Ganguli
Anil Agarwal
Anil Nayar
Anil Wanvari
Anirudh Gupta
Anju And Abhijit
Anuroop Singh
Arif Mohd Khan
Arindam Chaudhuri
Arnab Basu
Arvind K. Singhania
Asha Sarabhai
Ashish Goel
Ashok Jaipuria
Ashok Sachdev
Ashok Sharma
Ashwani Khurana
Aslam Qader Khan
Av Anoop
Beena And Kishu
Benny Thomas
Bill Emmott
Bindiya Jain
Bunty Pasricha
C Anand David (Man Ford Allianz Pvt. Ltd.)
Ccl Productsindia
Chandni Parekh
Chinmay S Patel
Ck Ranganathan
Collin Benjamin
Color Chips India Ltd
Consumer Guidance Center
Crishna Smita Godrej
Cyrus Guzder
D Surendra Babu
D.Baskar & D.Nirmal
Daniel Lak
Deepak Kapur
Dilip D'souza
Dr K Shashidhar
Dr. Kt Lalwani
Dr. Pradhap C Reddy
Dr. Ravi
Dr. Surinder Kapur
Dr.C.P Sreekumar
Dr.S.P. Vasi Reddi
Eric Johnson
Foundation For Demorcratic Reforms
Gaurav Dalmia
Gaurav Singh
Gautam Berry
Gautam Banerjee
Gl Sultania
H K Chaudhary
H P Barooah (Chairman)
Harsh C Mariwala
Hemant D Naiknavare
Hindal Haidar Tyabji
Indian Tv Dot Com
Indrajeet Singh
Ishaat Hussain
J Mehra
J P Singh
Jaaved Ahmed Jaaferi
Jagdip Singh
Jagdish Chokar
Javed Akhtar
Jay Galla
Jayan Pillai
Jb & Neela D'souza
Jeanne-Marie Verghese
Jerry Pinto
Jit Paul
Jo

PUBLISHED ON 1 FEBRUARY, 2021 RNI NO. DELHIN/2009/28890

FOR THE FORTNIGHT 1-15 FEBRUARY, 2021

INDIA'S MOST ICONIC AND PATH-BREAKING INVESTIGATIVE STORIES

Continue to read

TehelkaHindi.com